बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत की लूट

भाई राजीव दीक्षित जी

- स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता

राजीव भाई दीक्षित - पुस्तक संग्रह②

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत की लूट

राजीव दीक्षित

स्वदेशी प्रकाशन
सेवाग्राम, वर्धा

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत की लूट

लेखक : राजीव दीक्षित

प्रकाशक : स्वदेशी प्रकाशन

सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित

प्रथम संस्करण : मार्च 2012 (2000 प्रतिया)
ई-पुस्तक संस्करण : मार्च 2012

स्वदेशी प्रकाशन, सेवाग्राम, वर्धा द्वारा
राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के लिए प्रकाशित

राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था
सेवाग्राम रोड, हुत्तामा स्मारक के पास
सेवाग्राम, वर्धा - 442 102

मोबाईल : 8380027016, 8380027022
मोबाईल : 982252011, 9422140731

मूल्य : 70 रूपये

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

समर्पित

परमपूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज को
जो भारत को स्वदेशी
बनाने की लडाई का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी
और स्वाभिमानी बनाने के लिए चल रहे
स्वदेशी आन्दोलन और भारत स्वाभिमान
के उन लाखों क्रांतिकारियों को जो
राजीव भाई के स्वदेशी भारत के
सपने को पूरा करना चाहते हैं।

उन सभी पुराने साथियों को जिन्होंने
राजीव भाई के साथ कन्धे से कन्धा
मिलाकर लड़ाई लड़ी

उन सभी नये साथियों को
जो इस लड़ाई को जिन्दा रखना चाहते हैं

विषय सूची

	स्वदेशी के प्रति राजीव भाई को	5
1)	प्रकाशकीय	9
2)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट	12
3)	भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का इतिहास	14
4)	युद्ध की राजनीति और हथियारों का व्यवसाय	45
5)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आपसी विलय	52
6)	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में प्रवेश	56
7)	विदेशी पूँजी का धोखा	61
8)	भुगतान सन्तुलन और निर्यात का भ्रम	69
9)	कर्ज और आर्थिक सहायता की राजनीति	73
10)	उच्च विदेशी तकनीक का झूठ	77
11)	घटते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी	82
12)	दवाओं के नाम पर लूट	86
13)	गुलाम होती खेती	90
14)	आधुनिक विकास या प्रकृति विनाश	96
15)	संस्कृति पर हमला	100
16)	राजनैतिक हस्तक्षेप	104
17)	विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और भारत	118
18)	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सच्चा पहलू	125

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की अगाध श्रद्धा और तड़प को शत:शत नमन

29 नवम्बर की मनहूस शाम को करीब 7:30 बजे किसी ने फोन करके बताया कि राजीव भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पाताल में भर्ती कराया है, वे उस समय छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे और उस दिन भिलाई में शाम को भारत स्वाभिमान की सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही सूचना मिली तो मैने तुरन्त राजीव भाई के नम्बर पर सम्पर्क करने की कोशिश की तो दोनों नम्बर बंद थे, सम्पर्क नहीं हो सका। हरिद्वार से छत्तीसगढ़ के साथियों का नम्बर लेकर फोन लगाया तो बात हुई तब यह सुनिश्चित हुआ कि वास्तव में राजीव भाई की तबीयत ठीक नहीं है उन्हें अस्पाताल में भर्ती किया गया है। तुरन्त मैंने पूछा कि स्वामी जी को खबर की या नहीं तो उन्होंने बताया कि हाँ- स्वामी जी को सूचना कर दी है और वे खुद इस मामले में डॉक्टर से बात कर रहे हैं और यदि स्थिति ज्यादा खराब हुई तो दिल्ली ले जाने की व्यवस्था भी हो रही है। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की एक बार राजीव भाई बात हो जाये लेकिन किसी भी तरह मेरी उनसे बात न हो सकी। समय खराब न करके तुरन्त गाड़ी से रायपुर के लिए निकल गया यह सोचकर कि यदि संभव हुआ तो सेवाग्राम ले आयेंगे और यही इलाज करवा लेंगे।

करीब 9:30 के आसपास नागपुर के आगे कही ढाबे पर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। तभी स्वामी जी का फोन आया और उन्होंने जानकारी दी कि मैं स्वमं इस मामले को लगातार देख रहा हूँ राजीव भाई दवाई लेने से मना कर रहे हैं। वे बार-बार मना कर रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है मुझे तो आर्युवेदिक या होम्योपैथी की दवा भिजवा दी जाये मैं उसी से ठीक हो जाऊँगा। चिन्ता की कोई बात नहीं है। फिर भी डाक्टरों को आवश्यक इलाज के लिए बोल दिया है और संभव हुआ तो उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ भी डाक्टरों से सम्पर्क चालू है। जैसे ही कुछ होगा मैं तुरन्त बताऊँगा।

इसके बाद ड्राइवर ने चाय पीकर दुबारा से गाड़ी चालू की और मैं भिलाई में फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश करता रहा। अनूप भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी आईये समय बहुत कम है, तब मैंने कहा उनसे कहा कि दिल्ली ले जाने की बात हो रही है आप दिल्ली लेकर निकलिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी हालात ऐसी नहीं है कि दिल्ली ले जाया जा सके। आप तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाईये। तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई राजीव भाई से, चक्कर क्या है। राजीव भाई स्वामी जी से बात कर रहे है तो मुझसे क्यों नहीं कर पा रहे है या उनके आसपास के लोग मुझे बात क्यों नहीं करवा रहे हैं।

करीब 12:15 पर स्वामी जी का फिर से फोन आया उन्होंने तुरन्त गाड़ी रोकने के लिए कहा, और फूट फूटकर रोने लगे, लगातार 5-6 मिनट तक रोते रहे। मैं भी उनके साथ रोता रहा। मैं आवाक होकर सुनता रहा। शुरू में मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जब थोड़ा सांस मिली तो स्वामी जी ने कहा कि, अब कुछ नहीं बचा, राजीव भाई हमको छोड़कर चले गये..... मैंने क्या-क्या नहीं सोचा था, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे हाथ पैरों में ताकत ही नहीं बची है। मैंने अपने आपको संभालते हुए स्वामी जी से एक ही प्रार्थना की कि स्वामी जी राजीव भाई के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर पूरा करना है। 'भारत स्वाभिमान' के रूप में उन्होंने जो सपना

देखा है वह पूरा होना चाहिए आप किसी भी कीमत पर यह लड़ाई नहीं रूकने देना. ... फिर उन्होंने पूछा कि आगे क्या करना है तो मैंने उनको कहा कि राजीव भाई वैधानिक रूप से भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव थे इसलिए उनका अंतिम संस्कार भारत स्वाभिमान के मुख्य कार्यालय, हरिद्वार में ही होना चाहिए, आप तैयारी करवाईये मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उसके बाद स्वामी जी का फोन कट गया, फोन पर बात करते-करते उनकी आवाज एकदम निढाल हो गई थी। मैं भी सुन्न हो गया था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करू, शरीर और दिमाग दोनों को जैसे लकवा मार गया हो। काठ जैसा हो गया था।

मैंने जब से होश संभला था तब से सिर्फ राजीव भाई को सिर्फ भाई ही नहीं, माँ-बाप मानकर, उनके साथ और उनके सानिध्य में था। अब वो छोड़कर चले गये तो कैसे आगे बढ़ेगें। उनकी हिम्मत से हम हिम्मत पाते थे, उनके जोश से हमें जोश मिलता था, उनकी निडरता से हमें निडरता मिलती थी, जब वो दहाड़ लगाकर विदेशी कम्पनियों के खिलाफ बोलते थे तब हमारे अन्दर हौसला पैदा होता था। अब कहाँ से यह सब मिलेगा। पूरे रास्ते सभी को सूचना करता रहा कि जिनको भी संभव हो तुरन्त हरिद्वार पहुँचें। जो-जो राजीव भाई को अपना गुरू मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे वे सब हरिद्वार पहुँचे। यह संदेश सभी को पहुँचाने के लिए बोलता रहा।

सुबह करीब 4 बजे भिलाई पहुँचा, अनूप भाई के साथ उस अस्पताल में पहुँचा जहाँ राजीव भाई चिरनिद्रा में लेटे थे। जब आई.सी.यू में पहुँचा तो वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। वेन्टीलेटर चल रहा था। कृत्तिम सांस चालू थी। असली सांस बंद थी। आँखे आधी खुली हुई थीं। जैसे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की आँखे खुली हुई हैं, ठीक वैसी ही, समाधि जैसी स्थिति थी। पता नहीं किसका इंतजार करते हुए सांस निकली थी या पता नहीं क्या सोचते-सोचते सांस निकली, चेहरा एकदम शांत था। कोई तकलीफ या परेशानी जैसा कुछ भी नहीं लगा। चेहरे पर चमक बरकरार थी। डाक्टर ने आकर कुछ बताया, पता नहीं क्या कहा। बस इतना ही समझ में आया कि राजीव भाई नहीं रहे, केवल वेंटीलेटर चालू है। वेन्टीलेटर निकालने के लिए कहा और उनको शांति से सुला देने के लिए कहा, उनकी खुली हुई आंखें बंद कीं और चरणों में प्रणाम किया, सिर्फ एक ही बात मन से निकली इतनी जल्दी क्यों चले गये। अभी तो बहुत काम करना था। बहुत लड़ना था। अपने सपनों का स्वदेशी भारत बनाना था। यह सच है कि अपनी अन्तिम सांस तक राजीव भाई अपनी कर्मभूमि में डटे रहे। देश को स्वदेशी बनाने के अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में लगे रहे जैसे एक सैनिक लड़ाई के अन्तिम दौर तक अपनी स्थिति नहीं छोड़ता; चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाये वैसे ही राजीव भाई अन्तिम समय अपनी समरभूमि में ही थे।

उस समय लगभग 5 बज रहे थे। उनका शरीर सुबह 9-10 बजे तक फ्रीजर में रखा गया। उस समय स्वामी जी का शिविर शिकोहाबाद में चल रहा था वहीं से उन्होंने राष्ट्र को राजीव भाई के जाने का संदेश दिया, पूरे देश में राजीव भाई को जानने वाले और चाहने वालों के लिए यह शोकाकुल संदेश सदमा पहुँचाने वाला था। उनके अंतिम संस्कार की खबर दी गई की वह हरिद्वार में होगा। दूर-दूर से लोग हरिद्वार पहुँचने के लिए निकल पड़े।

सुबह 9 बजे अस्पताल के नीचे वाले हिस्से में ही उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, भिलाई शहर के हजारों स्वदेशी प्रेमी भाईयों-बहनों ने उनके दर्शन किए। लोगों के आँसू रूक नहीं रहे थे। मेरे तो आँसू ही सूख गये थे। आँखें पत्थर हो गई

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

थी, करीब 11 बजे उनको रायपुर लेकर गये वहाँ पर भी उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह जी अपनी श्रद्धांजलि देने आये, और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट लेकर आये जहाँ हजारों भारत स्वाभिमान के कार्याकर्ता उनकी अंतिम विदाई देने के लिए खड़े थे। जैसे ही राजीव भाई वहाँ पहुँचे वैसे ही उनके दर्शन के लिए लोगों में अफरातफरी थी। सब अपने प्रिय राजीव भाई को अंतिम बार एक नज़र देख लेना चाहते थे। फिर तो दुबारा मिलना नहीं होगा। सिर्फ यादें ही रह जायेंगी। वहाँ अंतिम दर्शन के बाद एक छोटे से हवाई जहाज से उन्हें लेकर हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े।

रायपुर से हरिद्वार का सफर कोई साढे तीन घंटे का था। हमारा हवाई जहाज उड़ा। हवाई जहाज के कुल चार सीटें थी। एक पर मैं था और दो पर छत्तीसगढ़ के दो भाई । राजीव भाई मेरे बगल में लेटे हुये थे। एक 6 फुट के बकसे में उनका शरीर बंद था। सफेद-सफेद बादलों के बीच में जब हम जा रहे थे तब बार-बार ऐसा लग रहा था कि राजीव भाई की आत्मा भी, यहीं कहीं बादलों में बीच में ही होगी। वह हमारे साथ ही चल रही होगी, वह तीन घंटे मेरे जीवन में नया मोड़ लेकर आये। सबसे पहले तो बार-बार यही बात मन में आ रही थी। अब क्या करें, कैसे करे, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाये, कैसे राजीव भाई के सपनों को पूरा करें। राजीव भाई के अन्दर भारत को विदेशी संस्कृति और शोषण से मुक्त कराने की और भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी ओर स्वाभिमानी बनाने की जो तड़प थी, उसको कैसे बरकरार रखा जाये। उनकी यह तड़प सभी भारतीयों में कैसे प्रदीप्त की जाये।

राजीव भाई का पूरा जीवन आँखों के सामने घूम गया। कैसे 20 साल का एक नौजवान, जो इलाहाबाद में इंजीनियर बनने आया, घरवालों ने आई.ए.एस. पी.सी. एस के खव्वाब देखकर इलाहाबाद भेजा, वह देश की गरीबी, भूखमरी और शोषण व अन्याय की लड़ाई में शामिल हो गया। शायद राजीव भाई में क्रांतिकारियों का ही खून था जो उन्हें इस क्षेत्र में लेकर आया। उनके जीवन के सभी उतार-चढ़ाव आँखों के सामने घूम गये और अन्त में तमाम विरोधों के बावजूद भारत स्वाभिमान के रूप में देश प्रेम के परवान चढ़ाने का समय भी देखा। लेकिन अचानक से यह ब्रेक लगी कि सबकुछ शीशे की तरह टूटा। उनके चरणों पर हाथ रखकर संकल्प लिया कि मैं जीवन भर राजीव भाई के सपनों को पूरा करने का वचन निभाऊँगा, जिस तरह राजीव भाई अंतिम सांस तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई लड़ते रहे उसी तरह मैं भी अनकी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूंगा। अपनी अंतिम सांसों तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई को जारी रखूंगा और उनकी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूँगा। मन ही मन यह संकल्प लिया ओर मन को मजबूत बनाया। आँसूओं को पौछा और कठोर हृदय करके इस लड़ाई का जूआ अपने कंधों पर डाल लिया। जब तक भारत को पूर्ण स्वदेशी, पूर्ण स्वावलंबी और स्वाभिमानी नहीं बना लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजीव भाई दुबारा से आयेंगे इस अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। यदि कि ऐसा होता भी है तो भी जब तक वे आयें तब तक इसको जिन्दा रखना और चलाये रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। स्वामी जी का तो आशीर्वाद है ही, और राजीव भाई के मानने वाले, चाहने वालों का आशीर्वाद भी रहेगा ही।

करीब 5-6 बजे के आसपास हरिद्वार आ गया, वहाँ आचार्य बालकृष्ण जी राजीव भाई को लेने आये थे। राजीव भाई को लेकर सीध भारत स्वाभिमान के कार्यालय

में गये। वहाँ राजीव भाई के अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। राजीव भाई अमर रहे के नारों के साथ उनका पर्थिव शरीर, श्रृद्धालयम के उसी विशाल हाल में रखा गया जहाँ उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यान दिये थे। सामने वही मंच था। जहाँ राजीव भाई ने स्वामी जी के सनिध्य में देश के नौजवानों को ललकारा था और उनकी आवाज पर सैकड़ों जीवन दानी अपना सबकुछ छोड़कर 'भारत स्वाभिमान' की इस लड़ाई में कूदे थे। उनमें से काफी जीवनदानी भाई वहाँ थे। वे सभी हतप्रभ थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या करें। राजीव भाई को बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, उनको गर्मी बहुत लगती थी इसलिए शायद अपने अंतिम समय में वे बर्फ पर लेटे थे। तब तक माँ-पिताजी भी आ गये। उनको अभी तक नहीं बताया गया था कि राजीव भाई नहीं रहे। हरिद्वार में हाल में प्रवेश से पहले ही उन्हें बताया, हाल में प्रवेश करते ही पिताजी ने विलाप करते हुए पूछा की भैया को कहाँ छोड़ आये, मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, एक बाप अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए आया था, वह बेटा जिसने देश सेवा का व्रत लेकर भारत माँ को विदेशी कंपनियों से मुक्त कराने और खुशहाल भारत बनाने की लड़ाई छेड़ी थी, उसके अंतिम दर्शन के लिए आये थे। माँ बार-बार राजीव भाई के चेहरे को प्यार से छू-छूकर बोल रही थी कि आज ही तेरा जन्मदिन था। एक बार तो उठ जा लेकिन राजीव भाई तो शांत सो रहे थे। स्वामी जी ने सभी को ढांढस बंधाया और कहा कि हम सब आपके बेटे हैं। आप तो हजार बेटे वाली माँ हो। दूर-दूर से सभी साथियों का आना जारी था। पुराने-पुराने साथी आ रहे थे अंतिम दर्शन के लिए। रात भर यह सब चलता रहा।

सुबह 8 बजे कनखल के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ठाठारी पर लिटाने से पूर्व राजीव भाई को स्नान कराया गया। सभी प्रेमी साथियों ने अपने-अपने हाथों से निहलाया, घी चंदन लगाया और खादी के कपड़े में लपेट कर उन्हें ठठरी पर लिटाया गया, उसके बाद वंदेमातरम् के नारों के साथ राजीव भाई को स्वर्गरथ में बिठाया गया। 'वंदेमातरम्' और 'राजीव भाई अमर रहे' के नारों के साथ राजीव भाई को कनखल आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, स्वामी जी की माताजी के आँसू रूक ही नहीं रहे थे। वहाँ पर हरिद्वार के हजारों लोगों ने राजीव भाई के दर्शन किये। वहाँ से घाट तक राजीव भाई को कंघे पर ले जाया गया। कनखल घाट पर उनकी चिता सजाई गई। मैने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी आप राजीव भाई को वर्धा से गंडा बांधकर लाये थे और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आप अपनी सन्यास परम्परा को छोड़कर मुखाग्नि अवश्य दें। स्वामी जी ने, आचार्य जी ने और मैंने तीनों ने मिलकर मुखग्नि दी। सभी उपस्थित कार्यकत्ताओं ने समिधा डाली और राजीव भाई पंचतत्व में विलीन हो गये।

अब उनका शरीर हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका विचार, उनके संकल्प हमारे साथ हैं उन्हें ही पूरा करना है। गंगा में उनकी अस्थियों को इस संकल्प के साथ प्रवाहित किया कि राजीव भाई के विचार पूरे देश में फैलाने हैं। गंगा जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-वहाँ राजीव भाई के विचार फैलेंगें और उन्हीं किनारों पर फिर से वे पैदा होंगे। राजीव भाई की जन्मभूमि गंगा के किनारे ही रही और वे फिर से उन्हीं किनारों पर पैदा होंगे।

स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की अगाध श्रद्धा और तड़प को शत:शत नमन, इस तड़प और श्रद्धा को लेकर हम सब इस लड़ाई को जारी रखेगें.....

प्रदीप दीक्षित (सेवाग्राम वर्धा 13-2-2012)

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

1.

प्रकाशकीय

1498 में वास्को दि गामा अफ्रीका से होता हुआ दक्षिण में केरल के कालीकट समुद्र पर पहुँचा। उसके आगमन के साथ ही पश्चिम के देशों की घुसपैठ भारत में शुरु हो गई थी। शुरुवात में तो वास्को दि गामा जैसे कई लुटेरे भारत में आये। उसके बाद उसी रास्ते से डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी धीरे-धीरे करके आये। उनकी जगह कंपनियों ने ले ली। इतिहास हमें बताता है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1600 में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरु किया। कम्पनी के सिपाहियों और अधिकारियों ने भारत के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी कब्जा किया और लूटने का काम शुरु किया। लूटने के साथ-साथ भारत के विदेश व्यापार, जिस पर स्थानीय व्यापारियों का कब्जा था। उसको भी ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों के जहाजों को रोकना उन्हें परेशान करना शुरु किया तो उन्होंने सारा विदेश व्यापार अंग्रेजों के हाथ में दे दिया।

1706 के बाद फ्रान्सीसियों ने भी भारत में अपनी घुसपैठ बढ़ाई। अंग्रेजों और फ्रांन्सीसियों में युद्ध हुआ, फ्रान्सीसी परास्त हुए और अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ईस्ट इण्डिया केवल एक ही कम्पनी नहीं थी। पश्चिमी देशों ने 16 वीं शताब्दी तक कई कंपनियां बना ली थी जिनका उद्देश्य लूटमारी करना ही था। भारत के साथ-साथ अमरीका और अफ्रीका के देशों में भी इन कम्पनियों ने अपना कब्जा जमाना शुरु कर दिया था। अपने राजाओं से लूट का चार्टर लेकर और सेना लेकर यह कम्पनियां अन्य देशों में जाती थी और व्यापार शुरु करती थी। इतिहास का अध्ययन करें तो साफ पता चलता है कि इन कम्पनियों के पीछे इनके देशों की राजाज्ञा और तन्त्र पूरी तरह मदद करता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पीछे इग्लैण्ड का पूरा सरकारी तन्त्र और रानी की सहमति हुआ करती थी। भारत में 1830 तक कम्पनी राज चला लेकिन ब्रिटेन की रानी की सहमति से। उसके बाद सीधा ब्रिटेन का हस्तक्षेप शुरू हुआ।

1830 के बाद भारत में जब सीधे ब्रिटेन का शासन चलने लगा तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ-साथ कई और कम्पनियों ने भारत में घुसपैठ की। खासकर बंगाल में और विशेष रूप से कलकत्ता में जूट, पटसन और चाय के क्षेत्र कई विदेशी कम्पनियों आ गई थी। यह सभी कंपनियाँ अंग्रेजी शासन के बुलाने पर और उनकी मदद के लिए आई थीं। हम मानते हैं कि 16 वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक अंग्रेजो ने जिस तरह से भारत में लूट और अत्याचार का शासन चलाया वह आजादी के बाद भी जारी है। बस अन्तर इतना है कि आज 4500 से अधिक विदेशी कंपनियां भारत को लूट रही हैं। इसलिए फिर से नया स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है।

भारत का प्राचीन उद्योग मुलत: विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का रहा है। छोटे-छोटे उद्योग, छोटी-छोटी तकनीकें और छोटी-छोटी पूँजी और व्यक्तिगत या परिवार का समूह जो इन उद्योगों में लगा हुआ था, जैसे कपडा उद्योग में रंगाई, बुनाई, कताई पिंजाई, जैसे कई तकनीकी कामों को अलग-अलग स्तरों पर बाँटकर पूरा कपड़ा उद्योग चलता था और विदेशों मे व्यापार होता था। इसी तरह लोहा उद्योग, जूट उद्योग, लकडी का काम और अन्य दस्तकारियों का उद्योग की छोटे-छोटे और विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर चलते थे। लेकिन जब से कम्पनियों का व्यापार शुरु हुआ तब से शोषण का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ।

भारत सोने की चिड़िया था तो इन्हीं छोटे-छोटे और विकेन्द्रित उद्योगों के आधार पर ही था। जैसे-जैसे कम्पनियों के आने से शोषण बढता गया और हमारा सारा व्यापार और उद्योग इन विदेशी कम्पनियों पर आधारित होता गया वैसे-वैसे हम कंगाल होते गये। निवेश के रुप में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पूँजी बहुत कम थी, लेकिन लूट कर ले जाने वाली सम्पत्ति उस तुलना में बहुत अधिक थी। शुरुवात में कम्पनियों को इस लूट का लाइसेंस तो अंग्रेजी सरकार ने ही दिया था। लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकारों ने भी इन विदेशी कंपनियों को लूट का लाइसेंस दिया है। इस किताब में दिये गये कई लेखों से यह सिद्ध होता है।

जैसे-जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की लूट और अत्याचार बढ़ते गये वैसे-वैसे भारत में उनका प्रतिरोध भी बढ़ता गया था। दक्षिण और बंगाल के कई रियासतों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पटखनी भी दी थी। 1857 में तो विद्रोह की खुली घोषणा कर दी थी। केवल सैनिक स्तर पर ही नहीं बल्कि बंगाल में तो विज्ञान और तकनीकी के स्तर पर भी विद्रोह शुरु हो गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरुप स्वदेशी आंदोलन शुरु हुआ जिसमें बंगाल के विभाजन का विरोध और अंग्रेजों के बहिष्कार की शुरुआत हुई। 1916 में गांधीजी के आने के बाद तो स्वदेशी आंदोलन ने नई जमीन तैयार की। अंग्रेजी हुकूमत को राजनैतिक रुप में हटाया जाये इसके साथ-साथ आर्थिक रुप मे भी अंग्रेजी साम्राज्य को हवास्त किया जाये इसके लिए स्वदेशी आंदोलन शुरु हुआ। गांधीजी, तिलक और अन्य क्रान्तिकारीयो के नेतृत्व में शुरु हुआ यह स्वदेशी आंदोलन ने हिन्दुस्तान के मारे गयें उद्योगो के लिए जीवित करने का काम किया।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

गांधीजी की सारी से न इन्ही स्वदेशी आंदोलन में से तैयार हुई थी।

1991 में जब उदारीकरण और वैश्वीकरण शुरू हुआ तबसे ही वैश्वीकरण से होने वाले नुकसानों को लेकर छोटे-छोटे समुह उनका विरोध करते ही आ रहे हैं पानी के सवाल पर, समुद्र में मछली पकडने के सवाल पर, बिजली में विदेशी कम्पनियों को बुलाने के सवाल पर, घोटालों द्वारा देश की लूट के सवाल पर आंदोलन हो रहे हैं लेकिन प. पू. स्वामी रामदेवजी के नेत्तृत्व में भारत स्वाभीमान की शुरूआत एक अनोखी शुरूआत है जो विदेशी कम्पनियों की लूट और स्वदेशी के आग्रह को बडे स्तर पर उठा रहा है। न केवल आवाज उठा रहा है बल्कि विदेशी सामनों के विकल्प भी तैयार कर रहा है। केवल स्वदेशी ही नहीं, व्यवस्था परीवर्तन का सपना भी देख रहा है। यह सपना राजीव भाई का सपना है इसलिए इस सपने को आगे ले जाकर साकार करन का दायित्व हम सब का है।

पिछले 20 वर्षों में राजीव भाई ने जितना बोला है उसकी तुलना में लिखा बहुत कम है। उनके लिखे हुए लेखों और किताबों तथा व्याख्यानों को लिखित रुप में लाने की योजना उनके रहते ही बन गयी थी लेकिन समयाभाव के कारण वह संभव ना हो सका। राजीव भाई के जाने के बाद उनका समस्त साहित्य उपलब्ध करवाने की कोशिश हो रही है। उसी कड़ी में यह किताब भी शामिल है। उनके लिखित और बोले गऐ साहित्य पर लगभग 20 किताबों का संकलन तैयार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि आगामी 30 नवम्बर तक यह सभी किताबें उपलब्ध होंगी।

यह किताब 1990 में उस समय लिखी गई थी जब राजीव भाई ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ आजादी बचाओ आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया। पहले इस किताब का नाम 'बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मकड़जाल' था। लेकिन उन्हें कभी भी यह नाम पसंद नहीं आया। उनकी बहुत इच्छा थी कि यह नाम बदला जाये। उनके रहते तो यह संभव नहीं हो पाया लेकिन उनके जाने के बाद उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए इस किताब का नाम 'बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत की लूट' रखा गया है। यह नाम उन्होंने खुद तय किया था। पुरानी किताब के आंकड़ों को भी उन्होंने ही दुरूस्त किया है।

आज के इस स्वदेशी आंदोलन को तैयार करने में और भारत को स्वदेशी, स्वाबलंबी और स्वाभिमानी बनाने के लिए इस तरह की किताबों का उपयोग हो तो इनकी सार्थकता इसी में है। जैसे जैसे हम विदेशीकरण के जाल फसेंगे वैसे-वैसे यह किताबें हमें अपनी सार्थकता सिद्ध करेंगी।

2.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट

मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में किसी भी नयी खोज ने इतने मनोवेग, गहरे-संदेह, तीखी आलोचना व सनसनी को जन्म नहीं दिया, जितना कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने। जासूसी उपन्यासों का सा रोमांच पैदा करने वाली इनकी रहस्यपूर्ण गतिविधियों की जब कलई खुलती है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस जगत भी भौचक्का रह जाता है जो कि स्वयं इस तरह की कारगुजारियों का भंडाफोड़ करने का आदी है। रोशनी की एक नीली सी लकीर अन्तर्राष्ट्रीय जगत के उन पुरोधओं को भी चकाचौध से आँखे भींचने पर मजबूर कर देती है, जो इस मुगालत में रहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उनके इशारों पर संचालित होती है।

आज ऐसे किसी भी बड़े अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विवादों को ढूँढ़ पाना कठिन है जिनके पीछे कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वार्थ न जुड़े हों। किसी आर्केस्ट्रा के संचालक की भाँति ये कम्पनियाँ यह निर्धारित करती हैं कि देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं नेताओं को किस प्रकार के स्वर निकालने चाहिए। ये कम्पनियाँ उनके प्रति विशेष रूप से निर्मम होती हैं जो उनकी बात नहीं मानते। ऐसे लोगों को सीधे-सीधे उनके पदों से हटा दिया जाता है या उनकी हत्या करवा दी जाती है। इसलिए इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 'सुपर स्टेट'भी कहा जाता है। जिन देशों की ये कंपनियों होती हैं उन देशों की सरकारें भी इनसे भयभीत रहती हैं क्योंकि ये राज्य के ऊपर एक अधिराज्य के रूप में काम करती हैं। अब 'राज्य की नीति', 'राज्य की शक्ति', 'राज्य की सम्प्रभुता', आदि शब्द अर्थहीन हो गये हैं। इन कंपनियों की नीतियों से ही अब राज्य की नीतियां निर्धारित होती हैं। किन्तु विकसित देश इनको बर्दास्त करते हैं और इनका पोषण भी करते हैं क्योंकि ये कम्पनियां उनके लिए विकासशील व

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

अविकसित देशों का दोहन करती हैं और नये साम्राज्यवाद को बनाये रखती हैं।

इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आपस में अनिष्टकारी गठजोड़ वास्तव में नयी सम्प्रभु शक्ति है। ये कंपनियाँ विशाल राजनैतिक शक्ति वाले अधिकाधिक स्वाधीन केन्द्र बनते जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सभी देशों में राज्य के अन्दर राज्य जैसा कुछ बना लिया है जिसने स्वतन्त्र शक्ति हासिल कर ली है। इन कम्पनियों की ताकत का अनुमान इस बात से ही आसानी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राज्य भी इन कम्पनियों की अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता है। अमेरिका के 'फेडरल रिजर्व बोर्ड' को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कितना 'यूरो डालर' कहां और किसके पास है ? और वह अमेरिका में कैसे प्रवेश कराया गया है ? (विदेशों में जमा तरल मुद्रा का भंडार) 'यूरो डालर' कहलाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास करीब 13000 अरब डालर (650,000 अरब रूपये लगभग)की तरल परिसम्पतियाँ बताई जाती है जो विश्व की सभी सरकारों की तरल परिसम्पतियों का लगभग तीन गुना हैं। इनमें जरा सा भी परिवर्तन करने पर विश्व भर में भयंकर वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

सन् 2008 में संसार के कुछ प्रमुख देशों की कम्पनियों ने 10,720 अरब डालर (20,2960 अरब रूपये लगभग) का व्यापार किया। देशों के अनुसार, कम्पनियों के व्यापार का आँकड़ा निम्न है :-

	(1988) में	(2009) में
अमेरिका	4807 अरब डालर	7738904.8 अरब डालर
जापान	2843 अरब डालर	2596696.8 अरब डालर
पश्चिम जर्मनी	1201 अरब डालर	2084787.0 अरब डालर
फ्रांस	947 अरब डालर	2110280.7 अरब डालर
इटली	828 अरब डालर	604299.0 अरब डालर
ब्रिटेन	813 अरब डालर	1748911.7 अरब डालर
कनाडा	482 अरब डालर	343204.6 अरब डालर

(स्रोत: फारचून, जून 2009)

अब राजनैतिक रूप से किसी देश को गुलाम बनाना सम्भव नहीं है। अत: देशों को आर्थिक रूप से इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जरिये गुलाम बनाया जाता है। ये कम्पनियाँ आर्थिक साम्राज्यवादी शोषण का एक प्रमुख हथियार हैं।

2

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में इतिहास

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पत्ति की जड़ें, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान वैनिस, अंग्रेजी, डच और फ्रेंच कम्पनियों के मूल में हैं जो मूलत: व्यापारिक कम्पनियों के रुप में उभरकर सामने आई थीं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्यकाल से पहले (14 वीं और 15 वीं शताब्दी से पहले) दुनियां की सभी सभ्यताओं में जो घुमक्कड़ व्यापारी होते थे वे खुद व्यक्तिगत और निजी तौर पर व्यापार करते थे एक सीमा से दूसरी सीमा में पूरी दुनियां में घूमा करते थे और मुख्य रुप से अपने देश कीं स्वदेशी हस्तकलाओं और स्वदेशी तकनीकों द्वारा बने सामानों का व्यापार करते थे। दूनियां के पूर्वी हिस्से में इस तरह की व्यापारिक संस्थाओं की उत्पत्ति का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। फिर भी, ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हुए देखा जाये तो हम यह मान सकते हैं कि ईसा पूर्व लगभग सभी देशों में इस तरह की व्यापारिक गतिविधियां काफी बड़ी मात्रा में चला करती थीं। और ईसा के बाद पहली शताब्दी से ही समुद्र के रास्ते भारत और मलेशिया, भारत और इन्डोनेशिया और भारत और रोम के बीच व्यापार करने के लिए स्थाई व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। प्राचीन जकार्ता की कहानियों में बेवीलोन और भगरु कच्चा नामक समुद्री पत्तन से पानी के जहाजों का आना जाना तो हमें पढ़ने को मिलता ही हैं। लगभग पहली शताब्दी से ही चीन, वर्मा, मलेशिया, यूरोप के कई देशों में व्यापार के लिए आर्थिक लेन देन तो हमें दिखाई देते ही हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही पश्चिम के साथ हमारा व्यापार कम होता गया और चीन के साथ बढ़ता गया। विशेष रुप से दक्षिण भारत के साथ चीन का व्यापार काफी तेजी के साथ बढ़ता गया। प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के ताम्रलिप्त, मुसीरी, कोरकी और कावेरीपत्तनम् जैसे पत्तन भारत से बाहर दूसरे देशों में व्यापार करने के

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

लिए काफी प्रसिद्ध रहे है। फिर भी जो ध्यान देने की बात है वह यह कि प्राचीन बहुराष्ट्रीय व्यापारियों और आधुनिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में जो मूल अन्तर है वह यह कि प्राचीन बहुराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां कभी भी अपने मूल देश से आने वाली वस्तुओं से और न हीं व्यापार से किसी भी तरह का शोषण करते थे और न हीं देशों की बीच में झगड़े पैदा करवाते थे।

ओद्योगिक क्रान्ति और उसके बाद

16 वीं शताब्दी से पहले और लगभग ओद्योगिक क्रान्ति के 150 वर्षो बाद तक अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में पूर्वी दुनियां का ही वर्चस्व रहा हैं। उस समय के व्यापार में अन्तरराष्ट्रीय पूँजी के निवेश का कोई पहलू नहीं दिखाई देता है। ओद्योगिक क्रान्ति के समय से ही व्यापार के तरीकों में और उत्पादन के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। प्रो. मेथ्यू के शब्दों में "इतिहास के एक निश्चित कालक्रम में, मनुष्य ने उत्पादन की तरनीकी के संचयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और उस संदर्भ में ओद्योगिक क्रान्ति एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शताब्दियों तक मनुष्य और पशु शक्ति के ऊपर निर्भर रहने के बाद यांत्रिकी और रसायन के उपयोग से उत्पादन की नई पद्धतियों को सीखा गया। भारतीय सभ्यता दुनियां में सबसे पहली आर्थिक और प्राचीन सभ्यता है जिसने आर्दश सामजिक- आर्थिक संस्थाओं को जन्म दिया और आर्थिक उत्पादन के लिए मनुष्य की क्षमताओं/दक्षताओं और तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखा।"

ओद्योगिक क्रान्ति 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्थ और 19 वीं शताब्दी के पूवार्ध की देन है। 1765 से 1785 के 20 वर्षो के अन्तराल में कई नये आविष्कार हुए। विशेष रुप से वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में कई आविष्कार हुए। और इन नये आविष्कारों ने उत्पादन की पद्धति में लगातार नये तरीकों को विकसित किया। यह ओद्योगिक क्रान्ति केवल इंग्लैण्ड में ही नहीं हुई थी, बल्कि दुनियां के कई हिस्सों में इस का प्रभाव हुआ था।

"फ्रान्स में भी नेपोलियन बोनापार्ट के समय में उद्योगों की उत्पादन पद्धति में यांत्रिक परिवर्तन के प्रयास किये गये जो नेपोलियन तृतीय तक जाकर सफल भी हुए। जर्मन में भी 19 वी ं शताब्दी में इस तरह के प्रयास हुए और शताब्दी के अन्तिम समय में इस औद्योगिक क्रान्ति के लाभ रुसी अर्थव्यवस्था में शामिल हुए।"

ओद्योगिक क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का उदय हुआ और इस नई आर्थिक पद्धति के संचालन का एक नया शास्त्र विकसित हुआ। उत्पादन की इस नई पद्धति ने वस्तुओं की विविधता में और उनकी उपलब्धता में बहुत तेजी से वृद्धि की। सारस्वातों से

उत्पादित होकर आने वाले सामानों ने वस्तुओं की माँग और रोजगार पैदा करने के अवसर दोनों को बढाया। और, पहली बार तकनीकी को आवश्यक रुप से स्वीकार किया गया और मशीनों के निर्माण में इंजीनियरों का उपयोग किया गया। कारखानों से उत्पन्न देने वाली इन वस्तुओं की अधिकता ने निर्यात के विकास की आवश्यकता को पैदा किया। शुरुवात के समय में कई बड़ी कम्पनियों के चार्टरों में निर्यात की बात शामिल थी। इस रुप में सबसे प्राचीन कम्पनी, 1555 में 'द मुस्कोवी कम्पनी' थी, जो दुनिया के कई देशों में व्यापार करती थी, और जिसको आधुनिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पितामह के रुप में देखा जा सकता हैं। उसके बाद वैसी ही दूसरी 'द टर्की कम्पनी' (1581) थी, तीसरी, 'द हडसन बे'(1670), चौथी, 'द रायल अफ्रीकन कम्पनी'(1672), पाँचवी, 'द ईस्ट इण्डिया कम्पनी'(1600), छठवी, 'द साउथ सी कम्पनी'(1711) हैं।

अमरीका का गृह युद्ध और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इतिहास की किसी भी घटना में अमरीकी कम्पनियों की गतिविधियां सबसे प्रमुख अध्याय होता है। जो यह बताता है कि दूसरे देशों में घुसकर अमरीकी कम्पनियां किस तरह अपना प्रभाव डालती हैं। और अपने इस हस्तेक्षेप के प्रभाव को लगातार बढ़ाने में, यद्यपि इसमें कई बार बाधा भी आती है, कामयाब रही है अमरीका में कम्पनियों के आपसी विलय ने अमरीका में गृह युद्ध करवाया। फिर भी, कम्पनियों के आपसी विलय के विकास का उद्देश्य आपसी प्रतिद्वन्द्विता से बचने के लिए अवसर ढूँढना था। यह कहा गया कि इस तरह के व्यापारिक विलय के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है वह यह कि प्रतियोगिता से बचा जाये जो कि बहुत कठिन होता है और जो अधिकांश प्रतिष्ठानों के लाभ को खत्म कर देता है। यदि एक बार इस तरह का आपसी विलय शुरु होता है तो वह स्वत: ही केन्द्रीकरण की तरफ बढ़ता जाता है।

शुरुवात में, यह 'व्यापारिक विलय' एक 'पूल' के रुप में था जिसे सदस्यों का एक ढीला-ढाला संगठन कहा जा सकता है और जो आपसी प्रतियोगिता से बचना चाहते थे। 1887 के बाद जब 'अन्तरराज्यीय वाणिज्य कानून' आया तो यह 'पूल' प्रभावहीन हो गये। क्योंकि इस कानून ने इन 'पूल' को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तब उसके बाद यह 'पूल' ट्रस्ट के रुप में बदल गये। जिसमें ट्रस्ट के अर्न्तगत सभी सदस्य 'बोर्ड आफ ट्रस्टी' के द्वारा अपनी परिसम्पतियां सुरक्षित रखते थे और ट्रस्ट से प्रमाणपत्र प्राप्त करते थें। इसके अलावा और लाभांश की प्राप्त करते थे बिना किसी मताधिकार के। इस तरह का पहला ट्रस्ट 1882 में स्थापित हुआ। जो 'द स्टॅण्डर्ड आयल कम्पनी'

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

के रुप में था। जिसका मेनेजमेंट 9 लोगों के ट्रस्टी मण्डल का था। जल्दी ही, व्यापार के इस तरीके ने अन्य क्षेत्रों को भी आकर्षित किया। जिसमें चीनी, काटन, लोहा, तेल और शराब जैसी अन्य वस्तुओं के लिए भी इस तरह के व्यापारिक विलय होना चालू हो गये। जब इस तरह के व्यापारिक गठबंधन अचानक से मजबूत हुए और एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के आधार पर संचालन करने लगे तो लोगों के बीच में असंतोष पैदा हुआ। परिणाम स्वरुप कुछ लोगों ने 'एन्टी ट्रस्ट लॉ' के रुप में अपना गुस्सा जाहिर किया। 1890 में राज्य और कई संघीय सरकारों ने इन ट्रस्टों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरु किया तो सालभर के ही अन्दर कई ट्रस्ट खत्म किया गये। इसके बाद पुनः फिर से एक नई व्यापरिक संगठन के रुप में इनका उदय हुआ जिसे 'द होल्डिग्स कम्पनी' के नाम से जाना जाता है।

1907 तक अमरीका में व्यापरिक संगठन के रुप में इन 'होल्डिग्स कम्पनियों' का काफी दबदबा रहा था। अधिकाशं कम्पनियों ने इस नये स्वरुप को ग्रहण कर लिया था। 'होल्डिग्स कम्पनी' के रुप में सबसे प्रमुख कम्पनी यू. एस.स्टील कोरपोरेशन को माना जाता है जो 11 संविधानों के साथ 170 व्यापरिक कम्पनियों को संचालित करती थी। जब इन 'होल्डिग्स कम्पनियों' ने और बड़े-बड़े समूह या कर्टेल बनाना शुरु किया तो रुजवेल्ट की सरकार ने इनके खिलाफ 'एन्टी ट्रस्ट लॉ' के अर्न्तगत कठोर कदम उठायें और कई कम्पनियों के खिलाफ फैसले सुनाये। इन सबके कारण एक नये तरह का गठबंधन सामने आया जिसमें कई इकाईया एक 'कामन वार्ड आफ डायरेक्टर' रखती थी जो अन्तरराज्यीय निर्देशकों की व्यवस्था से चलता था। यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय व्यवस्थापन और संचालन का यह स्वरुप ही आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधार स्तम्भ रहा है।

अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही राज्यसरकारों और इन 'होल्डिग्स कम्पनियों' के बीच में एक युद्ध जैसा चलता रहा है। इस काम के लिए सरकारों ने हमेशा 'शेरमेन एक्ट' और 'क्लेटोन एक्ट' का सहारा लिया है। यद्यपि इस कानून को उपयोग लाने का उद्देश्य इन कम्पनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना था जो अमरीका में प्रतियोगिता के माहोल को रोकना चाहती थीं। इस कारण से धीरे धीरे अमरीका और अन्य देशों के बीच में आर्थिक मतभेद पनपने शुरु हो गये थे। क्योंकि अमरीकी कम्पनियों की कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि कों केवल अमरीका में ही चुनौती दी जा सकती थी। जिसके कारण अमरीका दूसरे देशों पर दबाव बना सकता था। नार्थ सिक्युरिटीज कम्पनी, अमेरिकन

टोबेको कम्पनी और स्टेन्डर्ड आयल कम्पनी के मामलों में एक फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट के अर्न्तगत एक फेडरल कमीशन बैठाया गया। प्रेसीडेन्ट विल्सन के प्रशाशन के दौरान जब इस कमीशन ने 2000 से अधिक कम्पनियों की जाँच की तो पाया कि अधिकांश कम्पनियां भ्रष्टाचार, झुठे विज्ञापन और गलत प्रतियोगिता में लिप्त पाई गई।

1914 के तुरन्त बाद, इस कानून में थोडा ढिलाई दी गई ओर अमरीका के बाहर भी अधिक उत्पादन से होने वाले लाभ समझ में आने लगे तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनियां में सामानों की माँग काफी तेजी से पैदा हुई थी। 1880 से 1890 के दौरान जिस तरह ये बड़ी व्यापारिक कम्पनियों का उदय हुआ था उनकी आलोचना भी शुरु हो गई थी। हेनरी डेमरेस्ट लायड सबसे बड़े आलोचक के रुप में सामने आये। उन्होंने 1894 में 'वेल्थ अगेन्स्ट कामन वेल्थ' नामक किताब में द स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी की एकाधिकार की रणनीति और गतिविधियों पर काफी सामग्री लिखी है।

प्रथम विश्व युद्ध से पहले और बाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थिति

प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पैदा हो चुकी थी। यह दावा किया जाता है कि ब्रिटेन की विलियम लीवर वास्तव में पहली बहुराष्ट्रीय कम्पनी है जिसने अपनी उत्पादन और वितरण की ईकाईयां कई देशों में स्थापित की। जो एक मजबूत तन्त्र द्वारा संचालित होती थी, यह इस बात की द्योतक है कि आधुनिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वरुप यहीं से निर्धारित होता है। फिर भी क्रिस्टोफर टोजेनडेट का मानना है कि सिंगर कारपोरेशन पहली बहुराष्ट्रीय कम्पनी होने की सशक्त दावेदार है क्यों कि यह पहली कम्पनी है जो इतने बड़े स्तर पर पूरी दुनियां में किसी एक सामान को अपने ब्रान्ड़ नाम के आधार पर उत्पादित और वितरित करती है।

इनमें से कुछ कम्पनियां जो स्थापित हुई वह इस प्रकार हैं। एक जर्मन व्यक्ति फेड्रिक व`पर वह नाम है जिसने 1865 में न्यूर्याक के अल्बनी में पहला कारखाना लगाया। स्वीडन के सुप्रसिद्ध अल्फ्रेड नोबल ने हेमबर्ग में बारुद का कारखाना स्थापित किया। सिंगर ने अपनी पहली युनिट, जो विदेश में लगाई, ग्लैसगोड और जरगैल में लगाई।

जब अमरीकी कम्पनियों ने बाहर निकलना शुरु किया

जब अमरीकी कम्पनियों ने दुनियां के अन्य हिस्सों में निकलना शुरु किया

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

तो वे अमरीकीपन के साथ बाहर निकले। बहुत बड़े-बड़े संस्थान स्थापित किए। 1901 में अमरीकी कम्पनी वेस्टिंग हाऊस ने इग्लैण्ड में अपना सबसे बड़ा प्लांट लगाया जो इग्लैण्ड की धरती पर सबसे बड़ी ओद्योगिक ईकाई थी। राकफेलर की स्टॅण्डर्ड आयल यूरोप की सबसे बड़ी कम्पनी थी। 1914 में फोर्ड ने ब्रिटेन में कार बनाने की सबसे बड़ी कम्पनी स्थापित की। नेशनल कॅश रजिस्टर, ईस्ट मेन कलर, और जरनल इलेक्ट्रिक जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अन्य देशों में अपनी ईकाईया स्थापित की। अमरीकी सीनेट की वित्तीय समिति ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में लिखा है वह निम्नलिखित हैं।

(1) केटर पिलर ट्रेक्टर
(2) क्राइमलर कारपोरेशन
(3) फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी
(4) फोर्ड मोटर्स
(5) जनरल इलैक्ट्रिक
(6) जनरल मोटर्स
(7) आई.बी.एम.
(8) इन्टरनेशनल हारवेस्टर
(9) सिंगर
(10) कोका कोला
(11) ईस्टमेन कलर
(12) नेशनल रजिस्टर
(13) क्वाकर ओट्स

कुछ निश्चित मामलों में अमरीकी टेक्नोलोजी और वित्त द्वारा अपनी ईकाईया स्थापित करने के लिए सबसे पहले फोर्ड मोटर्स कम्पनी ने इस तरह की नीतियां अपनाई। कनाडा में जार्डन मेक ग्रेगर ने हेनरी फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड कम्पनी की ईकाई स्थापित करवाई और ब्रिटेन में पर सीवल पैरी ने डीपाबोर्न में फोर्ड की ईकाई खुलवाई। जिस तरह अमरीका ने यूरोप में अपनी आर्थिक घुसपैठ चालू की थी उसके विपरीत ब्रिटेन में काफी कठिनाई सामने आई। ब्रिटिश कम्पनी कार्टलाइम ने अपनी ईकाई के माध्यम से अमरीका की यू.एस. रेयान इण्डस्ट्रीज पर कब्जा किया। अमेरिकन विस्कास कारपोरेशन और दि रायल डच शैल कम्पनी तेल कम्पनियों में एक ताकतवर कम्पनी के रुप में उभरकर सामने आई। दवा और रासायनिक उत्पादों में जर्मन और स्विस कम्पनियों ने अमरीका को काफी पीछे कर दिया था। लेकिन अमेरिकन मार्केट में इन यूरोपीय कम्पनियों की घुसपैठ के मामले में अमरीकी कम्पनियों द्वारा यूरोप के बाजार में

उनकी घुसपैठक की तुलना नहीं की जा सकती। अमरीकी कम्पनियों की घुसपैठ यूरोप के मार्केट में हमेशा अग्रणी रही है। 1902 में मेकेनजी द्वारा लिखित पुस्तक *The Amrican in veders* में लिखा है कि "- अमरीका ने यूरोप को रौंद दिया, न केवल अपने सिपाहियों से बल्कि अपने सामानों से पाट दिया। इस लूट का नेतृत्व करने वाले उद्योग जगत के मालिक और दक्षपूँजीपति थे जिन्होंने मेड्रिड से सेंट पीटर्सबर्ग तक सभी जीवित लोगों को मानसिक रुप से अपने अधीन कर लिया था। हमारे सभ्रान्त वर्ग ने अमेरिकी लडकियों से शादी करना शुरु कर दिया और हमारे ड्राईवरों के स्थान अमरीकी गाडियों के सीखे हुए ड्राईवरो नें ले ली। हमारे बच्चे अमरीकी खाने पर पल रहे हैं, और हमारे मृतको के लिए अमरीकी ताबूत अपनाये जा रहे हैं।"

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर्टेल बनाना

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय का एक कारण यह भी रहा है कि अलग अलग देशों में एक ही तरह का सामान और उत्पादन प्रक्रिया अपनाने के लिए कम्पनियों ने आपस में कार्टेल बनाने पर सहमति तैयार की। इस तरह के समझौते अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता को रोकते हैं और इन गठबंधनों को आधुनिक तकनीकी और शक्ति द्वारा फलने फूलने और समृद्ध बनने की राह खोलते हैं। इसके साथ-साथ वित्तीय बैंकें आसानी से इने धन उपलब्ध धन करवाती है। जो इनको आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में मदद करते है उत्पादन करनेवाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और आर्थिक मदद करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनिया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

जार्ज डब्लू स्टाकिंग और डब्लू वाटकिंस ने अपनी किताब '*कर्टेल इन एक्शन*' में बहुराष्ट्रीय कंपनियो द्वारा कर्टेल बनाने के कई उदाहरण दिये हैं और उन्होंने लिखा है कि डयूयों और आई.सी.आई द्वारा किया गया आर्थिक गठबंध न पहला उदाहरण है जो इस तरह के कर्टेलाइजेशन को व्यवहारिक जगत ने मान्यता प्रदान करवाता है और इस गठबंधन ने दुनियां के रासायनिक उत्पादकों को अपनी मुठ्ठी में करने में बहुत बड़ी मदद की है।

आज का दौर और अमरीकी दादागिरी

दो विश्व युद्धों के बीच के समय में और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद जब यूरोप युद्ध से थक हार कर बैठा था और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था तब अमरीकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही थी। अमरीका की अर्थव्यवस्था ने समय का मौका देखकर तुरन्त अपनी कम्पनियाँ द्वारा न केवल यूरोप की आर्थिक मंदी के लिए बल्कि एशिया के कई हिस्सों में अपने बाजार के विस्तार के लिए

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

उपभोक्ता और वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना के लिए माँग बनाना शुरु कर दिया। इस संदर्भ में यह भी उद्घाटित किया जा सकता है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियो ने 1930 के दशक में लातीनी अमरीकी देशों में अपने को स्थापित करना शुरु कर दिया था। उनका यह आर्थिक साम्राज्य उत्तर में कनाडा तक फैला और दक्षिण में मेक्सिको तक फैला। अमरीकी कम्पनियाँ ने पश्चिम के लगभग सभी देशों में अपनी घुसपैठ बनाई और उनके बाजारों पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। अमरीकी प्रतिष्ठानों ने यूरोप और एशिया में जिस तरह से अपना विस्तार किया उसके कारण कई विशेष पहलू हमें देखने को मिलते हैं।

1) 1880 और 1890 के दौरान अमरीका ने एक तरह के ओद्योगिक साम्राज्य के द्वारा अपना विस्तार किया, और लगभग 5000 कम्पनियों को 300 ट्रस्टों में तब्दील किया। इस तरह के ओद्योगिक गठबंधनों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे ऐसी योजना और तन्त्र का निर्माण करें जो अपनी बाजार की क्षमताओं के अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाहर के बाजारों की तलाश करें। अपने घरेलू बाजारों से एकत्र किए हुए विशाल लाभांश ने बाहर के देशों में उत्पादन की ईकाइयों को खोलने का दबाव तैयार किया। यदि शुरुवात में इस तरह की ईकाइयों को खोलने में घाटा भी हुआ तो वह घाटा अमरीकी सरकार द्वारा एक कानून बनाकर पूरा किया गया कि विदेशो में खोली गई इकाइयों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।

2) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका द्वारा 1948-52 के बीच यूरोप की आर्थिक उन्नति के लिए 17 बिलियन डालर का एक मार्शल प्लान तैयार किया गया। जिसके कारण युद्ध से छिन्न भिन्न हुए यूरोप की प्रतिव्यक्ति आप अगले दो दशक में इतनी तेजी से बढ़ी कि किसी को भी आश्चर्य हुआ। जिसके कारण अमरीकी सामानों की माँग तेजी से बढ़ गई। इस मार्शल प्लान की सहायता से अमरीकी कम्पनी आसानी से यूरोपीय मार्केट में स्थापित हो गई। इस बारे में रेमण्ड वर्मन ने लिखा हे कि 'मार्शल प्लान सैद्धान्तिक रुप से एक राजनैतिक हथकण्डा था जिसके द्वारा अमरीकी सरकार ने कमजोर हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में करने में सफलता हासिल की'।

3) युद्ध के तुरन्त बाद यूरोप और एशिया के कई देशों, विकसित और अविकसित दोनो तरह के, के बीच अमरीकी कम्पनियों को अपने यहाँ बुलाने की होड़ शुरु हो गई। वे यह चाहने लगे कि अमरीकी कम्पनियां उनके यहाँ आकर उनका विकास करें। जो देश अंग्रेजों, डच और पुर्तगालियों के गुलाम रहे थे उनके मन में अंग्रेजो, डच व पुर्तगालियों के प्रति घृणा का भाव था इसलिए भी वे अमरीकी कम्पनियों को अपने यहाँ बुलाने के लिए आतुर थे। इन देशों के बीच अमरीकी कम्पनियों को बुलाने की जो प्रतिस्पर्धा थी उसके कारण अमरीकी कम्पनियों को मोलभाव करने का मौका मिला जिसके कारण उन्हें अपनी

ईकाइया स्थापित करने के लिए लचीले कानून और अधिकतम मुनाफा कमाने की शर्तो को मनवाने में आसानी हो गई।

4) कई वर्षो तक यूरोपीय सरकारों के पास विदेशी विनयम की कमी थी जिसके कारण वह वहाँ के देशों में निवेश नहीं कर पा रहे थे।

5) द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद पाउण्ड स्टर्लिंग की स्थिति बाजार मे डालर की तुलना में एक दम से गिर गई। लेकिन 1960 तक यूरोप में डालर की बहुत तंगी थी। अमरीकी कम्पनियां विदेशों में अपना साम्राज्य बढाना करना चाहती थीं और उन्हें अमरीकी सरकार द्वारा सभी तरह की विस्तार मदद दी जा रही थी। यूरोप को वापिस आर्थिक पटरी पर लाने के काम में और आर्थिक सहायता करने के लिए अमरीकी सरकार खुद सीधे खुलकर सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि अमरीकी सरकार द्वारा किया गया सीधा निवेश कई तरह की बाधायें उत्पन्न कर सकता था। इसलिए अमरीकी सरकार का मानना था कि अमरीकी कम्पनियां ही सबसे अच्छा माध्यम हो सकती हैं यूरोपीय बाजार अपना पर अपना अधिपत्य जमाने के उद्देश्य के लिए। इसलिए सभी देशों ने अपनी अमरीकी कंपनियों को स्थापित करवाने के लिए प्रयोगात्मक कदम उठाये और सभी देशों की सरकारों को इसके लिए बाध्य किया गया कि वे अमरीकी कम्पनियों को काउण्टर गारन्टी दें और कर प्रणाली में राहत दें।

6) इन अमरीकी कम्पनियों के ऊपर स्थानीय देशों की सरकारों द्वारा जो कर और कोटा प्रतिबन्ध लगाये जाते थे। वह सारे प्रतिबन्ध इन कम्पनियों द्वारा वहाँ पर ईकाई स्थापित करने के बाद स्वत: ही खत्म हो जाते थे।

7) 'द एन्टी ट्रस्ट' कानून और शेरमेन तथा क्लेटोन कानून अमरीकी कम्पनियों को यह दिशा निर्देश भी देते थे कि वह किस तरह विदेशों में अपने को संचालित करें। 'एन्टी ट्रस्ट कानून' के अतिरिक्त अनुच्छेद विदेशी समझौतों तक पहुँचें। इससे पहले ही यह देखने में आया कि यह दोनों कानून अमरीकी कम्पनियों को अपने घर में स्थापित करने की तुलना में विदेशों में अच्छे ढ़ंग से स्थापित करने में मदद करवाता था।

8) जब यूरोपीय इकोनोमिक मार्केट और यूरोपीय इकोनोमिक कम्युनिटी अमरीकी कम्पनियों की पहुँच से दूर होता था। तब यह कारण स्थानीय देशों में इन कम्पनियों के प्लांट स्थापित करने में मदद करता था। आपस में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर पूरा का पूरा यूरोपीय मार्केट सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध होता था। अमरीकी कम्पनियों के लिए एक स्थिर बाजार व्यवस्था, स्थिर राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता के साथ सभी आर्कषक सुविधाएं उपलब्ध होती थीं।

9) इन अमरीकी कम्पनियाँ द्वारा विदेशों में अपनी ईकाईयां स्थापित करने के पीछे एक और उद्देश यह भी था कि इन अविकसित देशों में

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

तुलनात्मक रुप से लागत मूल्य कम होती थी और सस्ते दर पर श्रमिक मिल जाता था।

10) 'सोवरेनिटी एट बे' नामक अपनी किताब में रेमण्ड वरनान ने कई कम्पनियों के बारे में लिखा हैं - काल्ट, सिंगर, आई.टी.टी, वेस्टिंग हाऊस, ईस्टमेंन कोडक, पार्क डेविस, और यूनाईटेड शूज जैसी कुछ कंपनियों ने विदेशों में अपनी ईकाईयां सिर्फ इसलिए स्थापित की थी कि उन्हें उत्पादन की लागत कम पडती थी।

11) 1950-1970 के बीच में विज्ञान और तकनीकी में अमरीका ने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके कारण दुनिया के व्यापार में अमरीका सबसे आगे आया था। रेमण्ड वरनान ने लिखा है कि - "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और यूरोप ने भी उनकी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा वित्त घोषित और निर्देशक शोध और विकास कार्यक्रमों ने दुनिया भर में उनके प्रभुत्व को स्थापित करने में मदद की। इस मत के अनुसार सेना और युद्ध आधारित शोधों ने अमरीकी कंपनियों को सर्वोच्च स्थान दिलवाने में विशेष रुप से मदद की है। आधुनिक ओद्योगिक इतिहास में पूर्व की तुलना में इस काल में बड़ी आसानी से अमरीकी कम्पनियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ।"

विशेष रुप से ध्यान देने की बात यह है कि 1951 से 1969 के बीच में भौतिकी में 31 नोबल पुरस्कारों में से 21 नोबल पुरस्कार सिर्फ अमरीका को मिले हैं। रसायन विज्ञान में 37 में से 9, और दवा और सामाजिकी में 40 में से 23 नोबेल पुरस्कार भी अमरीका को ही मिले है। 1960 में मध्य में अमरीका द्वारा शोध और विकास के क्षेत्र में खर्च किया गया पैसा तत्कालीन समय में जर्मनी द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा का पचास गुना अधिक, युनाईटेड किंगडम का दस गुना, पश्चिमी यूरोप द्वारा खर्च किया गये धन का तीन गुना अधिक था।

शोध और विकास के मद में अचानक से इतना अधिक पैसा, व्यक्तिगत रुप से खर्च करने का विचार, यद्यपि थोडा बहुत अमरीकी सरकार ने भी खर्च किया था, सिर्फ 1974 की IBM को आय-व्यय पत्रक मे से ही देखा जा सकता है। IBM ने इस प्रकल्प के लिये कुल 890 मिलियन डालर खर्च किये थे। शोध और विकास के मद में इतना अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी, अमरीकी लोग तकनीकी विकास को व्यावसायिक उद्देशों में जल्दी ही से जल्दी अपनाना चाहते थे। अधिकांश जापानी और यूरोपीय व्यापारी, जो नई तकनीकी उपलब्धियों और आविष्कारों से परिचित थे फिर भी उन्हे अपनाने में धीरे चल रहे थे। अमरीकी कम्पनियों और यूरोपीय व जापानी कम्पनियों के बीच में यही अन्तर है कि दोनों ही नई तकनीकों में वाकिफ थे लेकिन अमरीकी कम्पनियां नये, ज्ञान और तकनीकों के प्रयोग में काफी आगे थीं। 1970 के

दशक की शुरुवात में यही एक बहुत बड़ा कारण है (उपर लिखा हुआ) कि अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी आगे थीं। युनाइटेड नेशन के एक दास्तावेज "विश्व के विकास में बहुराष्ट्रीय कंपनियां" में। कुल 656 कम्पनियों की सूची बनाई गई है। जिसमें 358 कम्पनियां अमरीका की है बाकी 74 जापान की, 61 कम्पनियां युनाईटेड किगंडम की, 45 संयुक्त जर्मनी की है। 4 तरह की श्रेणियों में कम्पनियों को अलग से सूचीबद्ध किया गया है। जिनकी कुल विक्री 76,131 मिलियन डालर है। इनमें तीन यूरोप की हैं। 12 कम्पनियों में से 9 अमरीका की हैं जिनकी कुल विक्री 77,807 मिलियन डालर है, 295 में से 115 अमरीका की है जिनकी कुल विक्री 380,000 मिलियन डालर से अधिक है।

स्पष्ट रुप से दिखाई देता है कि 211 कम्पनियों में से 127 कम्पनियां जो अमरीकी हैं उनकी वार्षिक बिक्री 1 बिलियन डालर से अधिक है। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो, कई देशों की आर्थिक सत्ता से कहीं अधिक बड़ी हैं। निश्चित रुप से कुछ शक्तिशाली ताकत के रुप में देखी जाती हैं।

अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में अमरीकी कंपनियों की यह बढत 1973 में भी जारी थी। तीस से अधिक देशों के 9481 विदेशी समझौतों में 2567 समझौते सिर्फ इन 113 अमरीकी कम्पनियों के पास थे।

अमरीका के मामले में लेनदेन सबसे ऊपर की श्रेणी में था। 1973 के साल में 4530 कम्पनियों की गिनती की गई। जिनमें 1199 अमरीकी कम्पनियां की वार्षिक बिक्री 680.135 बिलियन डालर थी। 1975 में कई अमरीकी कम्पनियों की वार्षिक बिक्री 1 बिलियन डालर से बढ़कर 210 बिलियन डालर हो गई थी। अमरीका की सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जो दुनियां में अधिकतम व्यापार कर रहीं थीं। पूरी दुनियां में 1971 में इन कंपनियों का सीधा पूँजीनिवेश 158 बिलियन डालर था जो 1975 में बढ़कर 259 बिलियन डालर हो गया था और प्राथमिक रुप से 1976-77 में यह आंकड़ा 278 बिलियन डालर हो गया था।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियां : विकसित और विकासशील देशों में

अधिकाशंत: बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित देशों की होती हैं। सिर्फ जापान की छोड़ कर अधिकांश कंपनियों की मूल ईकाईयां अपने देशों में स्थापित होती हैं यह बात ध्यान रखने की है कि मूलत: विकसित देशों की यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने देशों की तरह अन्य विकसित देशों में अपना

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

सीधा पूँजी निवेश करने के लिए आतुर रहती हैं। जिसके लिए वे सबसे पहले बाजारों में अपना उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया को विकसित करती हैं। कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था विदेशी कम्पनियों द्वारा दी जा रही किसी भी तरह की धुडकी से डरती नहीं है।

पश्चिम के देशों में इन कम्पनियों की मजबूती को इसी बात से समझा जा सकता है कि इन देशों में राजनैतिक स्थिरता और इनकी उत्पादन ईकाइयां सुचारु रुप से चलती रहती हैं। इन कंपनियों को सीधे पूँजी निवेश का 3/4 हिस्सा अमरीका, इग्लैण्ड, कनाडा, जर्मनी जैसे विकसित देशों में होता है और 1/4 पूँजी निवेश विकासशील देशों को जाता है। यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि आनुपातिक रुप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अधिकांश गतिविधियां विकसित देशों में ही होती हैं। जैसा की आगे के पेराग्राफ में पढ़ सकते हैं यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों कई रुपों में अपना काम करती है जैसे फ्रेन्चाइजिंग, सब कान्ट्रेक्टिंग और अलग-अलग तरह से तकनीकी स्थानंतरण के रुप में यह कम्पनियां लाभांश के अलावा अतिरिक्त धन कमाती हैं। दूसरा तुलनात्मक रुप से 66 बिलियन डालर की छोटी सा पूँजी निवेश विकसित देशों में इसलिए किया गया कि इन कम्पनियों की स्थिति सर्वोच्च हो सके। चाय के बागानों में, सिगरेट निर्माण में और विस्फोटक तथा दवा उद्योग में। इसी तरह से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाई है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन की नवीनतम प्रवृत्ति

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन में अभी हाल में कुछ नयी प्रवृत्तियां देखने में आई हैं। उनका संचालन सुनिश्चित प्रणाली के होता है जो इन प्रवृत्तियों की प्रांसगिकता को स्वीकार करती हैं।

1) सेवा क्षेत्र में घुसपैठ

पिछले दशक में जो प्रवृत्तियां देखने में आई वह यह कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सेवा क्षेत्र में अपनी घुसपैठ बनाना शुरु किया है। बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, विज्ञापन एजेन्सी, परामर्श सेवाएं आदि के जरिए यह सेवा क्षेत्र में घुस रही हैं। इन क्षेत्रों में घुसने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विश्व के स्तर पर इन सेवाओं का मानकीकरण होगा जिससे बिना किसी परेशानी और गलत प्रचार के केन्द्रीकृत संचालन और निर्देशन के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। 1971 से 1976 के बीच 50 बड़ी बैंकों ने अपनी 3000 विदेशी शाखायें खोली जिनमें 10

बड़ी बैंके तो अमरीका की हैं। इन 10 बड़ी बैंकों ने, जो 1065 शाखाओं को संचालित करती हैं, जिनमें 646 शाखायें विकासशील देशों में खोली हैं। उनकी कूल पूँजी 348 बिलियन डालर है। इस मजबूत गठबंधन की उपस्थिति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ओद्योगिक और व्यावसायिक रुप में बहुत मजबूत आर्थिक ताकत प्रदान करती है। विश्व की 25 सबसे बड़ी विज्ञापन एजन्सिया इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में हैं। जिसमें से 4 बड़ी एजेन्सियां तो अमरीका की ही हैं। उनकी वार्षिक आय 13 बिलियन डालर है। अधिकांश विज्ञापन एजेन्सियों की 50 प्रतिशत से अधिक आय विदेशी बिलों के माध्यम से आती है। इन विदेशी अर्थव्यवस्थों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को भारी दबाव के साथ स्थापित करने में यह विज्ञापन एजेन्सियां ही मदद करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन शक्तिशाली विज्ञापन एजेन्सियों को स्थापित करने के कारण इस स्थिति में आ जाती हैं कि वे अपनी प्रतिद्वन्दी स्थानीय कम्पनियों को हरा सकें। ऐसा अधिकांश विकासशील देशों में होता है। मध्यमवर्गीय उपभोक्ता के ऊपर किये गये ICSR के सर्वेक्षण के अनुसार वीको वज्रन्दन्ती की तुलना में कालगेट टुथपेस्ट को अधिकांश लोगों ने प्राथमिकता दी थी, सिर्फ इस आधार पर कि इसका प्रचार सब जगह है और पारम्परिक रुप में इसे ही प्राथमिकता दी जा रही है।

2) समन्वयकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति जो बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। वह बड़े-बड़े समन्वय बनाना है, जिसमें कि आर्थिक साम्राज्य को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। 1966 से 1975 के बीच 180 अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 7624 ईकाइयां खोली जिन में 2378 इकाईयां विकासशील देशों में थी। राष्ट्रीयकरण जैसे अन्य विषयों के कारणों के कई कम्पनियां खत्म हो गई थी लेकिन इस तरह की समन्यकारी प्रवृत्तियों के कारण केन्द्रीक्रत ढाँचे को मजबूती से स्थापित किया जा सका। यह सब प्रवृत्तियां अमरीका के 'एन्टी ट्रस्ट लॉ' और उसके ही जैसे अन्य कानूनों से बहुत दूर थी। यह सब कितनी खूबसूरती से हुआ कि इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है।

3) उत्पाद विवधीकरण

उत्पाद विवधीकरण भी एक प्रवृत्ति है जो धीरे-धीरे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में फैल रही है अपनी आर्थिक ताकत को बरकरार रखने के लिए विदेशी समझौतों में और अपने लाभ को लगातार बढ़ाने के लिए यह प्रवृत्ति काम में आती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नये क्षेत्रों को ढूंढ रही है निवेश करने के लिए। खाना बेचने और बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां रसायन उद्योग में घुस रही हैं। रसायन

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

उद्योगवाली कम्पनियां खाने में और अभियांत्रिकी में घुस रही हैं। इसके कारण विकासशील देशों को यह निर्णय लेने में परेशान हो रही है कि सुरक्षित क्षेत्र किसे बनाया जाये। इस कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थानीय बोर्ड कोई निर्णय नहीं ले पाता और अपने मूल बोर्ड की ओर से आदेश की प्रतिक्षा करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय समझौते आन्तरिक वित्त बाजार में संचालन करते हैं और मात्र कम्पनी के स्तर पर संसाधनों का बँटवारा करते हैं। यह प्रवृत्ति भारत में काफी तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। जिसमें युनियन कार्बाइड, इन्डियन टोबेको कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर और विमको आदि कम्पनियां अपने मूल क्षेत्र से हटकर, या जिसका वे उत्पाद करती हैं उन क्षेत्रों से हटकर अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही हैं।

4) ग्लोबल शहरों का उदय

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने साथ अपनी समृद्धि लाती हैं और ग्लोबल शहरों को बढ़ाने में मदद करती हैं। इन ग्लोबल शहरों में ही यह कंपनियां अपने मुख्यालय स्थापित करती हैं। लेटिन अमरीका में कोटल घालेस, यूरोप में पेरिस, पेसीफिक देशों में होनो लूलू, पूर्व में मनीला, सिंगापुर और भारत में मुम्बई जैसे शहरों में यह कम्पनियां अपना कार्यालय खोलती हैं। यह शहर इन कंपनियों के मुताबिक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की व्यापारिक और वित्तीय सुविधायें और तन्त्र मुहैया कराते हैं। इसके अलावा इन शहरों में विदेशी संस्कृति और जीवन पद्धति का भी आयात होता है जो इन कम्पनियों के अधिकारी और कर्मचारीयों द्वारा दोषित होती है। इन शहरों में उच्चतम कर संग्रह, उपभोगक्तावादी खर्चे और रोजगार के साधन तो मुहैया होते ही है। लेकिन उसके साथ-साथ आर्थिक और पर्यावरणीय कचरा और अपसंस्कृति भी आती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए घरोंदे हैं विकासशील देश

अभी हाल के वर्षो में जो प्रवृत्ति उभरकर आ रही है वह यह कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विकासशील देश घर जैसे हो गये हैं। मलेशिया, हाँगकाँग, फिलीपीन्स, भारत, कोरिया, ब्राजील, थाइलैण्ड, मेक्सिको, जापान आदि देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए घर बन गये हैं। पश्चिम की इन कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश की तुलना में इन देशों का निवेश बहुत कम और महत्वहीन है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह निवेश अधिकांश अर्न्त-क्षेत्रीय है। अनुच्छेद IV में दिये गये आंकड़े अर्न्तक्षेत्रीय निवेश में इन देशो की स्थिति बताते हैं। जिसमें हम देख सकते है कि भारत सबसे नीचे के स्थान पर है। इसी निवेश में विदेशी सम्बन्धों को नहीं नकारा जा सकता। फिलीपीन्स की अधिकांश

कम्पनियां विदेशों में निवेश करती हैं जबकि वे अमरीकी वित्त और तकनीकी से संचालित होती हैं।

समाजवादी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां

समाजवादी देशों ने अन्तर- सरकारी समझौतों द्वारा विकासशील देशों के ऊपर दबाव बनाना शुरु किया है। इनकी गतिविधियां सामान्यरुप से आर्थिक सहयोग के समझौतों के ही अनुरुप होती हैं। समाजवादी देशों में उत्पादित होने वाले सामानों की तकनीकी और विज्ञान ओद्योगिक क्षेत्रों में बिक्री के लिए यह हमेशा संयुक्त गठबंधन और निर्यात इकाईयों को ही प्राथमिकता देती हैं जो संयुक्त रुप से पश्चिमी कम्पनियों और समाजवादी देशों की कम्पनियों द्वारा संयुक्त रुप से वित्त प्रदप्त होती हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1976 में विकसित और विकासशील देशों के बाजार में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश और USSR की लगभग 700 उत्पादन और व्यापारिक कम्पनियां काम कर रहीं थी। 1989 में यह संख्या बढ़कर 1400 हो गई। स्थानीय सरकारों के साथ विशेष समझौतों के माध्यम से यह कम्पनियां अपने लाभाशं और लाभ को अलग रखती हैं लेकिन इसके अलावा तकनीकी ज्ञान, मशीन और तकनीकी स्थानांतरण द्वारा यह कम्पनियां और भी मुनाफा कमाती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझोते होने के कारण जो वाणिज्यिक ईकाइयाँ हैं वह कानूनी रुप से काफी परेशानी महसूस करती हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि इन समाजवादी देशों ने अपने दरवाजे पश्चिम की कम्पनियों के लिए इस शर्त पर खोले है कि किसी भी तरह के न्याय के लिए न्याय क्षेत्र उन कंपनियों का देश ही होगा। बल्गारिया, हंगरी जैसे देशों ने वाणिज्य, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में USSR में अपनी कम्पनियों के प्रतिनिधि कार्यालय भी खोले हैं। 1976 में पूर्व और पश्चिम का कुल व्यापार 44 बिलियन डालर था। जो 1989 में बढ़कर 98 बिलियन डालर हो गया। "1972 में निक्सन-व्रेझनेव समझौते के तहत, एक अमरीका-सोवियत व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अर्न्तगत आयात-निर्यात बैंक सुविधायें उपलब्ध करवाई गई। पूर्व-पश्चिम व्यापार ब्यूरों के ऊपर एक वित्त विभाग बैठाया गया और निर्यात को नियंत्रित किया गया। जबकि, अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग से अपना व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए आर्थिक और व्यापारिक द्विपक्षीय समझोते कर रही थीं।" इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह कि पश्चिमी व्यापार तन्त्र को काऊण्टर गारण्टी दी जाने लगी है। इसके कई तरीके दी परन्तु जो सामान्य तरीका है। वह यह है कि पश्चिमी ठेकेदार, यंत्र, मशीनें, सामान और ईकाइयों की स्थापना के लिए भी साम्यवादी देशों में

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

काऊण्टर गारन्टी दी जाने लगी है। कंपनियां अपनी प्रोजेक्ट कास्ट के बराबर मूल्य का उत्पादन लंबे समय में करने के लिए तैयार हो रही है। प्रोजेक्ट कास्ट का 20% कम से कम और कभी कभी 100% के बराबर काऊण्टर गारन्टी लेती हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि सहउत्पादन ठेका भी दिया जा रहा है। जिसके तहत सोवियत देश पश्चिमी देशों के लाइसेंस के तहत उत्पादन करते हैं और उपयुक्त दामों पर निर्यात करते हैं।

लाइसेंस और तकनीकी की बिक्री

बढ़ते हुए व्यापार में हमें यह दिखाई देता है कि विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाइसेंस और तकनीकी की बिक्री इसलिए की जाती है क्योंकि इस प्रकार लाइसेंसिग और तकनीकी की बिक्री के भारी मुनाफा होता है। इसके अलावा इससे इन देशों में अपनी इकाईया स्थापित करने में आसानी हो जाती है और सीधे पूँजी निवेश द्वारा लाभांश और लाभ में बढ़ोत्तरी हो जाती है। तकनीकी स्थानान्तरण से विदेशी पूँजी के विरोध में राष्ट्रीयकरण की समस्या भी खत्म हो जाती है। इसीलिए 1965 के साल में तकनीकी स्थानान्तरण के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अचानक से 11,000 मिलियन डालर से बढ़कर 27000 मिलियन डालर की बढ़ोत्तरी हुई और 1985 में यह व्यापार 85000 मिलियन डालर का था। सीधे निवेश द्वारा अधिकतम लाभांश कमाने का यह व्यापार तेजी से बढ़ा है। विकासशील देशों ने इस तकनीकी स्थानान्तरण के सौदों में इन कम्पनियों को लगभग 2 बिलियन डालर चुकाये हैं। जिसमें के 845 मिलियन डालर सिर्फ अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गये हैं। इसलिए पूँजी निवेश की समस्यों की तुलना में तकनीकी स्थानान्तरण की समस्या कुछ अलग किस्म की है। कदाचित तकनीकी स्थानान्तरण में किसी भी तरह के नियंत्रण या न्याय क्षेत्र की समस्या या उत्पादन की समस्या नहीं है। बल्कि तकनीकी स्थानान्तरण में नियंत्रण अधिक अच्छे ढंग से रखा जा सकता है बल्कि कई मामलों में तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से रखा जा सकता है। तकनीकी बेचने वाली कोई भी कम्पनी किस तरह अपने विश्वव्यापी तंत्र में लाइसेंस के जरिए नियंत्रण रखती है ठीक उसी तरह वह किसी भी खरीददार को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बाध्य कर सकती है और उत्पादन, मशीन के उपयोग, निर्यात से बिक्री तक सभी पर नियंत्रण रख सकती है। जैसा कि वाल्टेर हेमिल्टन ने कहा है पेटेन्ट धारक और लाइसेंस लेने वाले के बीच ठीक वैसा ही रिश्ता होता है जैसा सामन्ती व्यवस्था में भगवान और दास के बीच।

फ्रेन्चाइजिंग

कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां फ्रेन्चाइजिंग के तरीके भी अपनाती है जो एकदम नये तरीके का व्यापार है। जिसमें नियंत्रण आंशिक रुप से कानूनी और आंशिक रुप से उत्पादन की पद्धति पर निर्भर करता है। फ्रेन्चाइजिंग की परिभाषा निम्न लिखित कही जा सकती है "ऐसे सम्बन्धों को लगातार बनाये रखना जिसमें एक फ्रेन्चाइजर किसी भी फ्रेन्चाइजी को एक सीमा तक व्यापार करने के लिए और उस पूरे तन्त्र को उपयोग करने के लिए जो फ्रेन्चाइजर उसे देता है लाइसेंस प्रदान करता है"। अन्तरराष्ट्रीय होटल व्यवसाय, में यह फ्रेन्चाइजिंग सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अभी हाल मेंITCने, जो पंचतारा होटलों को चलाती है, भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें वह शेरेटन को फ्रेन्चाइजी देना चाहती है। पेप्सी कोला और कोका कोला के फ्रेन्चाइजी समझोतों मे क्वालिटी नियंत्रण समझोते और निर्यात प्रतिबन्ध भी शामिल है। अंकताड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रेन्चाइजर का मुख्य उद्देश्य इस बहाने अपनी दुकानें स्थापित करना है जहाँ वे अपने ब्रान्ड के सामान चला सकें। इसलिए फ्रेन्चाइजी समझौते इस तरह के होते है जिसमें फ्रेन्चाइजर को यह सुरक्षा रहती है कि उसके पास नियंत्रण के सभी तरीके सुरक्षित हैं।

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

युनाइटेड किंगडम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी पूँजी निवेश का प्रमुख जोर भारत पर है क्योंकि भारत अंग्रेजों की पराधीनता में रहा है। जे. एड. आयेलेवी का कहना है कि विकासशील देशों में विदेशी पूँजी निवेश का एक पहलू यह भी होना चाहिए कि इन देशों की राजनैतिक-आर्थिक जीवन अभी भी पश्चिमी देशों की सरकारों के नियंत्रण में है और वह नियंत्रण अब बहुराष्ट्रीय निवेशकों के पास जा रहा है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आजादी के पूर्व से लेकर आज तक भारत में ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमरीकी कंपनियों ने भारत में अपने पैर जमाना शुरु कर दिया था। ईस्ट इण्डिया कंपनी के क्रियाकलायों के बारे में जानकारी होने के बाद भी विश्व युद्ध से पहले और आजादी के बाद भारत में शेष ब्रिटिश व्यावसायिक पूँजी की स्थितिका आंकलन बाकी है।

प्रारम्भ में ब्रिटिश कम्पनियां सार्वजनिक उपक्रमो में और खनिज उद्योग में प्रभावशाली भूमिका में थी इसके अलावा जूट, चाय और रबर जैसी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले कृषि क्षेत्रों में भी ब्रिटिश कम्पनियां हावी थीं। गुलाम भारत में रेल्वे सबसे प्रमुख क्षेत्र था ब्रिटिश एकाधिकार को स्थापित

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

करने में। 1942 में लंदन में हुये 'ब्रिटिश भारत के लिए सांख्यकी सर्वेक्षण' के अनुसार 1938-39 में भारत में इग्लैण्ड का कुल पूँजी निवेश 8478.2 मिलियन रुपये था। जिसपर 359.6 मिलियन का लाभ मिलता था। 1943-44 में यह निवेश बढ़कर 8585.3 मिलियन था और लाभ ठीक दो गुणा 852.1 मिलियन था। 1923 में अन्य ब्रिटिश कम्पनियों का जो भारत में काम कर रही थी पूँजी निवेश 300 मिलियन पाउण्ड था। जिसमें भारत की दो बड़ी खनिज संशोधन कम्पनियां इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी और स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 30 जून 1948 को भारत में कुल विदेशी व्यापारिक निवेश का मूल्य (उत्पादन, खनिज खनन, दैनिक उपभोग, व्यापार, यातायात, व्यापारिक वृक्षारोपन, और अन्य ओद्योगिक क्षेत्रों में) 3204 मिलियन रुपये था जिसमें 2301 मिलियन रुपये केवल ब्रिटिश व्यापारिक निवेश का गिना गया था। अमरीका का पूँजी निवेश 179.7 मिलियन रुपये का था। यह पूँजी निवेश दोनो तरह का था। सीधे पूँजी निवेश और पोर्टफोलिया इत्यादी के रुप में। 1948-55 के बीच में ब्रिटिश पूँजीनिवेश और भी बढ़ा था। मुख्य रुप में उत्पादन और वृक्षारोपण उद्योग में बढ़ा था। उस समये के कुछ प्रांसगिक आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं।

भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश 1948-1955 (रु. मिलियन में)

व्यापार का क्षेत्र	30.6.1945	31.12.1953	13.12.1955	48 से 55 के बीच
उत्पादन	533.4	1048.4	12829	+ 759.5
खनन	97.8	79.8	93.1	- 4.7
व्यापार	490.0	694.0	735.9	+ 245.9
व क्षारोपन	422.5	715.0	862.3	+ 339.8
वित्तीय	49.1	190.1	219.1	+ 170
यातायात	234.3	481.3	500.8	+ 266.5
अन्य	172.4	228.7	225.8	+ 53.4
कुल	2099.5	3472.8	3919.9	1830.4

बड़ा बाजार, कम उत्पादन लागत और सस्ता श्रम, इन तीनों कारणों ने भारत में ब्रिटिश निवेश को आकर्षित किया। उत्पादन और वृक्षारोपन उद्योग, मुख्यत: सिगरेट, तम्बाकू, खाद्यसामग्री, जूट, जूट प्रधान उद्योग, बिजली उपकरण, दवाई और दवाक्षेत्र तक केन्द्रित था।

मार्च 1970 के अन्त तक विदेशी कम्पनियों की उपईकाईयों और सीधे विदेशी नियंत्रण की कंपनियों का सीधा विदेशी पूँजी 7350 मिलियन रुपये का था। 1972-73 के अन्त तक भारत में 740 विदेशी कम्पनियां काम कर रहीं थीं। जिनमें 538 सीधे मूल कम्पनी की शाखा के रुप में कार्यरत थीं और 202 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपईकाईयों, अमरीका की कम्पनियों की 88 शाखायें और 28 उपईकाइयां, स्विटजरलैण्ड की 21, जापान की 18, प.जर्मनी की 17 और स्वीडन की 14 शाखायें काम कर रहीं थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की इन सभी शाखाओं और उपईकाइयों की कुल सम्पन्ति अनुमानत: 29220 मिलियन रुपये थी, जिसमें से UK की कम्पनियां का हिस्सा 18180 मिलियन रुपये था और अमरीका की कंपनियों का 5420 मिलियन रुपये था। हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश कम्पनियों की स्थिति लगातार ऊँची दिखाई दे रही है। जबकि अमरीकी कम्पनियां एक ही स्थिति बनाये हुए हैं। 1967-69 से लेकर 1972-73 के दौरान UK की कम्पनियों की कुल सम्पत्ति में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह 200 मिलियन रुपयों की है। जबकि अमरीका की कम्पनियों की कुल सम्पत्ति मात्र 150 मिलियन बढ़ी है। यदि इस बढ़ोत्तरी को कुल सम्पत्ति के प्रतिशत में गिना जाये तो, अमरीकी कम्पनियों की बढ़ोत्तरी महत्वपूर्ण है और यह दिशा बतलाती है कि बहुत ज्यादा तो नहीं परन्तु यह बढ़ोत्तरी ब्रिटिश कम्पनियों को पीछे छोड़ देगी।

शाखाओं के सम्बन्ध में 357 शाखाओं की कुल सम्पन्ति 1969-70 में 823 मिलियन रुपये थी जो 1972-73 में बढ़कर 10840 मिलियन हो गई। जबकि शाखाओं की संख्या 357 से घटकर 320 हो गई थी। 1969-70 में अमरीकी कम्पनियों की शाखायें 84 थी जबकि 1972-73 में 88 शाखायें हो गई थी। और कुल सम्पन्ति 2370 मिलियन से बढ़कर 3500 मिलियन हो गई थी। यहाँ फिर से अमरीका का व्यापार बढ़ गया था। उद्योगों में निवेश के बँटवारे से सम्बन्धित, इस तथ्य से हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि विदेशी पूँजी निवेश हमारे देश की आवश्यकताओं और विकास के अनूरुप विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहा था, अभी भी अधिकांश पूँजी निवेश दवाक्षेत्र और दवा निर्माण में ही हो रहा था। मुख्यत: सिग्रेट, पेट्रोलियम, परिशोधन उसके बाद व्यापार और वित्त में 11580 मिलियन पूँजी निवेश था जिसमें से होलसेल व्यापार और बीमा कम्पनियों का 1830 मिलियन रुपये का निवेश था। यह आसानी से देख सकते हैं कि

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

विदेशी पूँजी निवेश प्राथमिक रुप से उन क्षेत्रों में ही हुआ था जहाँ छोटी-छोटी पूँजी की आवश्यकता थी और जहाँ स्थानीय श्रम का शोषण हो सकता था और कच्चा माल व उद्यमशीलता आसानी में उपलब्ध हो सकती थी।

ऐजेन्सी तन्त्र का मॅनेजमेंट

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने व्यापार के संचालन के लिए एक तरह के नये एजेन्सी तन्त्र का विकास किया है जो मूलत: ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा बनाया गया था जिसमें पूँजी के खतरे को कम करते हुए उद्योग पर अपना नियंत्रण कायम करना था। एजन्सी तन्त्र एक एजेन्ट को नियंत्रित करता है एक ऐसी निजी लि. कम्पनी या फर्म या व्यक्तियों का समूह ऐजेन्ट बनता हैं। जो मेनेजर या प्रशाशकीय नियंत्रन में रहता है और प्रतिष्ठान की पूँजी या व्यापारी रिस्क को कम से कम करते हुए वित्तीय सहायता करता है। इस तरह इस एजेन्सी तन्त्र द्वारा एक बहुत बड़े समुदाय के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है और शेयरधारकों को सभी तरह के खतरों से बचाता है।

1972 में किए गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटिश मेनेजमेन्ट एजन्सी के अर्न्तगत 701 कम्पनियां थी और एक ब्रिटिश इण्डियन मेनेजिगं ऐजेन्सी के अर्न्तगत 32 कम्पनियां थी। ब्रिटिश मेनेजिंग एजेन्ट में से कुछ प्रसिद्ध एजेन्ट इस प्रकार हैं।

1) एन्ड्रफ यूले एण्ड कम्पनी
2) मेकलियाईड एण्ड कम्पनी
3) मार्टिन एण्ड कम्पनी
4) बर्न एण्ड कम्पनी
5) डन्कन ब्रर्दस एण्ड कम्पनी
6) ओक्टावियस स्टील एण्ड कम्पनी
7) जिलेण्डर्स अर्बुथनाट एण्ड कम्पनी लि.
8) शॉ वालेस एण्ड कम्पनी लि.

इनमें एन्ड्रफ यूले एण्ड कम्पनी सबसे बड़ी कम्पनी थी। यह यूनी कारपोरेट व्यापारिक कम्पनी के रुप में स्थापित हुई जिसे 1853 में एन्ड्रफ और जार्ज नाम के व्यक्तियों ने बनाया था और 1919 में *संयुक्त स्टाक कम्पनी* के रुप में परिवर्तित

हो गई थी। 1940 के मध्य तक इस कम्पनी के अर्न्तगत 55 कम्पनियां काम करती थीं। एक मात्र ऐजन्ट कम्पनी के अर्न्तगत काम करनेवाली 55 कम्पनियों के साथ यह सबसे बड़ी कम्पनी थी। यद्यपि कुछ कम्पनियों के ऊपर से इसका नियंत्रण खत्म हो गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध तक, ब्रिटिश कम्पनियों की स्थिति उँची थी। भारत में अमरीकी कम्पनियों का प्रभाव भी कम नहीं था। युद्ध की समाप्ति पर भारत में अमरीका का निवेश, जिसमें वर्मा और श्रीलंका भी शामिल है, 140 मिलियन के आसपास था। युद्ध के बाद अमरीकी निवेश में बढ़ोत्तरी हुई। शुरुआत में यह पारम्परिक क्षेत्रों में जैसे आयात निर्यात के मामलों में हुई जिसमें मुख्यता तेल के आयात और तेल सम्बन्धी सामानों में हुई जो स्टेण्डर्ड वेक्युम और केलटेक्स कम्पनियाँ द्वारा हुई।

1945 के बाद भारत में अमरीकी निवेश प्रमुख रुप से ओटोमोबाईल उद्योग में हुआ। जिसमें जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कम्पनियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। कुछ निवेश जूट और टायर बनाने वाली कम्पनियों में भी हुआ। मुम्बई में फायर स्टोन स्टैण्डर्ड कम्पनी ने टायर बनाने का कारखाना खोला और कार्यालय में लगने वाले टाईपराइटर के क्षेत्र में रेमिगंटन कम्पनी ने कलकत्ता में अपना कारखाना खोला। कुछ अमरीकी कम्पनियां भारत में कनाडा की उप ईकाईयों के रुप में स्थापित हुई। द मेलन कम्पनी कनाडा की एलुमिनियम कम्पनी के साथ बाजार में आई जिसमें आधी आधी पूँजी दोनों कम्पनियों की थी।

1951 से जब भारत के ओद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी के निवेश की नीति घोषित की गई तब अमरीकन कम्पनियों ने विशेष रुचि दिखाई जिसके तहत स्टैण्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी ने भारत सरकार के साथ समझौता करके भारत में 30 नवम्बर 1951 को बम्बई में तेल परिशोधन का कारखाना लगाने की घोषणा की। इसी के साथ केल्टेकम कम्पनी ने भी तेलशोधन में अपनी शुरुवात की। द सिनेमिड कम्पनी ने 'सल्फर' बनाने का कारखाना खोला और क्लोरोमाईसिटिन बनाने के लिए पार्क डेविस ने मुम्बई में एक कारखाना खोला।

विदेशी संयुक्त उपक्रम : प्रवेश का एक नया तरीका

भारतीय अर्थव्यवस्था में घुसने का एक नया तरीका बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निकाला है। वह है वित्तीय और तकनीकी समझौते। इस तरह के समझौतों से इन कम्पनियों को काफी फायदा होता है। वह कई तरह से होता है

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

1) रायल्टी और तकनीकी फीस के द्वारा उच्चतम लाभ होता है जिस पर न्यूनतम टेक्स लगता है।

2) केन्द्र सरकार की अनुमति से, भारतीय आयकर के कुछ निश्चित प्रावधानों के अर्न्तगत मशीनरी और प्लान्ट की तकनीकी आयात करने के लिए कम दर का ऋण मुहैया करवाने का आश्वासन दिया जाता है।

3) प्रोसेस लाइसेंस के ऊपर स्थानीय लाइसेंस के लिए सभी तरह की सुविधायें मिलती हैं।

4) उसी लाइसेंस के आधार पर कच्चा माल मशीनरी और प्लान्ट और उसके अन्य कलपुर्जे किसी भी विदेशी कम्पनी या उनकी सबसीडियरी से ऊँचे दामों पर खरीदा जा सकता है।

5) निर्यात किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है और कम्पनी इसके द्वारा विश्वव्यापी नियंत्रण प्राप्त कर सकती है।

1977 के अन्त तक भारतीय उद्योग जगत में 5498 विदेशी संयुक्त उपक्रम थे जिनमें दवा और रासायनिक क्षेत्र में 662, बिजली के उपकरण में 705, ओद्योगिक मशीनरी में 759, और यातायात के क्षेत्रों में 382 संयुक्त उपक्रम थे। अधिकांश संयुक्त उपक्रमों में विदेशी कम्पनियां किसी भारतीय सह उपक्रम के माध्यम से घुसी हुई थीं। इसलिए विदेशी कम्पनी लाभांश और तकनीकी फीस दोनों ही भारतीय कम्पनी से वसूलती थी। संम्पूर्ण निर्णय का अधिकार और भारतीय सबसीडियरी की सभी गतिविधियों पर इन विदेशी कम्पनियों का ही अधिकार होता था।

यहाँ जो लिस्ट दी जा रही है यह उन विदेशी कम्पनियों की है जो हमेशा ही भारतीय कम्पनियों के साथ संयुत्त उपक्रम के द्वारा भारतीय बाजार में घुसती हैं। अगस्त 1976 में 50 अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में से 23 कम्पनियां भारत में सीधे काम कर रहीं थी जो अपनी शाखाओं या उपक्रमों के माध्यम से घुसी थी 1974-75 में निम्न कम्पनियां काम कर रही थीं।

दुनिया के 50 बड़े संयुक्त कम्पनियों में से आधी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। यदि यह सच्चाई सामने आती है कि इनमें से प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सालाना बिक्री भारत सरकार के सालाना बजट से अधिक है तो हमें यह आश्चर्य लगेगा और कोई भी इनकी ताकत और शक्ति का अंदाज लगा सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह सभी कम्पनियां भारत में हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इनके अलावा कुछ अन्य और बहुराष्ट्रीय कंपनियां है जिनका सालाना आय व्यय 1 बिलियन डालर से अधिक है और जो हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करती हैं।

एक्सोन	शाखा	44.86 बिलियन डालर
जनरल मोटर्स	शाखा	35.72 बिलियन डालर
ब्रिटिश पेट्रोलियम	उपक्रम	17.28 बिलियन डालर
यूनी लीवर	उपक्रम	15.01 बिलियन डालर
आई.बी.एम	शाखा	14.43 बिलियन डालर
गल्फ आयल	उपक्रम	14.26 बिलियन डालर
आई.टी.टी.	शाखा	11.36 बिलियन डालर
फिलिप्स	उपक्रम	10.74 बिलियन डालर
हास्ट	उपक्रम	8.46 बिलियन डालर
ई.एन.आई	शाखा	8.33 बिलियन डालर
बेंज	शाखा+संयुक्त उप.	8.19 बिलियन डालर
बी.ए.एस.पी	उप+संयुक्तउप	8.15 बिलियन डालर
बेयर	उपक्रम	7.72 बिलियन डालर
नेस्ले	शाखा+उपक्रम	7.08 बिलियन डालर
आई.सी.आई.	उपक्रम	6.88 बिलियन डालर
ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको	उपक्रम	6.14 बिलियन डालर
हिताची	उपक्रम	5.91 बिलियन डालर
युनियन कार्बोईड	उपक्रम	5.66 बिलियन डालर
गुड ईयर टायर	उपक्रम	5.45 बिलियन डालर
जनरल इलैक्ट्रिक	उपक्रम	13.39 बिलियन डालर
सीमेन्स	उपक्रम	7.75 बिलियन डालर
वेस्टिगं हाउस	शाखा	5.86 बिलियन डालर
मित्सुबिशी	उप+संयुक्त उप	5.69 बिलियन डालर

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

उन विदेशी कम्पनियों की सूची जो भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम/समझौते में शामिल हैं।

	Name of Indian Subsidary	MNC	Paid up Capital (1974)	Amount of Capital Hold MNC (1974)
1	**Ashok Leyland**		778.85	463.94
	(i) Leylanb Motors Ltd. Lancashire, U.K.			
	(ii) Commonwelth Development Finance Co. Ltd.			
2	**Atlas Copco**		80.02	48.20
	(i) Atlas Copco Aktiblag			
	(ii) Sandcikens Gernverks Aktibolag, Sweden			
3	**Avery India Ltd.**		168.51	101.40
	Avery Limited Sono foundry Birmingham, England			
4	**Bata India Ltd.**		300.00	200.00
	(i) Bata Development Ltd.,			
	(ii) Bata Ltd., Toronto, Canada			
	(iii) Leader A.G. of St. Movitz Switzerland			
5	**Choloride India Ltd.**	The Choloride Electrical	401.20	239.00
6	**Dunlop Rubber Co.**	Dunlop Co. Ltd., U.K.	1170.00	563.64
7	**Food Specilities Ltd.**		184.99	128.28
	(i) Nestle Holding Ltd.			
	(ii) Nestle Product India Ltd., New Delhi			
8	**Hindustan Ferodo Ltd.**		248.17	145.00
	(i) Ferodo Ltd.			
	(ii) Turner & New All Group Co. U.K.			
	(iii) Turner Brothers Asbestor Co. Ltd.			
	(iv) J.W. Roberts Ltd.			
	(v) Turner Asbestor Cement Co.			
9	**Indian Aluminium**		2080.25	1172.47
	(i) Alcan Aluminium Ltd. London Co. Ltd.			
	(ii) Alcan Research & Development Ltd.			
10	**International Computers**		50.00	30.00
	International Computer Ltd. London			
11	**Lucas-**	TNS Ltd. Lucas of U.K.	382.00	229.20
12	**The Metal Box Co. of India Ltd.**			
	Metal Box Co. Ltd. London(Metal Box Group)		694.13	400.20
13	**Motor Industries Co. Ltd.**		822.10	431.25
	(i) Robert Bosch			
	(ii) G.M.B.A. , Stuttgart, West Germany			
14	**Relkitt & Colman of India Ltd.**		249.85	175.00
	Relkitt Colman Groups, U.K.			
15	**Roneo Vickers India Ltd.**		35.00	35.00
	(i) Roneo Ltd. U.K.			
	(ii) Vickers Ltd. U.K.			
16	**Sandvik Asia Ltd.**		132.00	79.20
	Sandvikens Jernverks Ab. Sandvikens			
	Sweden (Now Known as Sandvik Aktibolag)			
17	**Simens India Ltd.**		240.00	122.40
	(i) Simens And Hals ka Ag.			
	(ii) Siments Schwkertwerke			
	(iii) Siemens Reiniger A.G.Erlangenn, West Germany			
18	**Tube Investment of India Ltd.**		375.00	196.87
	(i) Miller & Co. Ltd.Birmingham, England			
	(ii) Tube Investment Ltd. Birmingham, England			
19	**Western India Match**		620.00	333.76
	Swedish Match Co. Sweden Co. Ltd.(Wimco)			
20	**Boots Company India Ltd.**		77.50	45.00
	Boots Pure Drug Co. Sweden			
21	**Ciba of India Ltd.**		487.50	316.87
	Ciba Ltd. Basle Switzerland			
22	**Glaxo Laboratories**	**Glaxo U.K.** and Other Companies India Ltd. of this Group	799.82	620.00
23	**Pfizer Ltd.**	**Chas Pfizer & Co.** INC New York USA and its Subsidiaries	550.10	420.00
24	**Richardson Hindustan Ltd.**	Richardson Marrell INC. New York	110.02	60.50
25	**Sandoz India Ltd.**	Sandoz Ltd. Switzerland	150.00	90.00

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

उपभोक्ता क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

हमारे गाँव/शहर के मध्यम वर्ग और निम्नवर्ग के दैनिक जीवन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का जो प्रभाव है उस पर बहुत मुश्किल से ध्यान जाता है कि वह प्रभाव किस तरह से और किस हद तक उन्हें एक गुलाम मानसिकता की ओर ले जाता है। उसका पूरा जीवन विदेशी सामानों से घिरा हुआ है। यद्यपि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादन हमारे देश में ही होता है और सरकारी लाइसेंस के द्वारा ही होता है फिर भी उनका लक्ष्य एक गुलाम मानसिकता तैयार करना होता है। उन्हें अपने जीवन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उनके प्रभाव का एक मापदण्ड यह भी है कि यह बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। इस संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत में कुल प्राथमिक पूँजी की तुलना अन्य निजी और सरकारी कम्पनियों के साथ करें तो उसमें बहुत असमानता दिखाई देती है। दोनों के अनुपात में जमीन आसमान का अन्तर है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकाशंत: उपभोक्ता बाजार में ही अपना व्यापार करती हैं। जो कि बहुत बड़ा बाजार है और निवेश बहुत कम है तथा आमदनी बहुत ज्यादा है। इकोनोमिक टाइम्स के एक आंकलन के अनुसार यह दिखाई देता है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत कम लागत में सामान का उत्पादन करती हैं और अधिकतम मुनाफा कमाती हैं। कभी कभी तो यह मुनाफा लागत का कई सौ गुना रहता है।

कालगेट के उदाहरण में प्राथमिक लागत पूँजी 150,000 रुपये थी जबकि 31 दिसम्बर 1973 को उनका कुल व्यापार 170,050,402 रुपये का था। सेवा क्षेत्र में ग्रिन्डलेज बैंक ने 1 मिलियन रुपये के निवेश से शुरुवात कर के 1973 तक 70.4 मिलियन पाउण्ड की कुल सम्पन्ति पैदा की है। हिन्दुस्तान लीवर के मामले में जब 1933 में यह भारत आई तब इसकी प्राथमिक निवेश पूँजी 20 मिलियन रुपये थी जबकि 1974-75 में इसकी कुल सम्पन्ति 170 मिलियन रुपये थी। भारत में यह लीवर ब्रदर्स के नाम से काम करती है और इसने साबुन, पावडर, खाने के तेल, दूध पावडर, अन्य खाद्य सामग्री के उत्पाद बनाकर भारत के अधिकांश बाजार पर कब्जा किया है। कम्पनी ने चाय उद्योग के क्षेत्र में भी घूसने का मन बनाया है। सल्फ्युरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड बनाना भी शुरु किया है।

इसी तरह दवा कम्पनियां भी बहुत कम लागत मूल्य में दवा बनाकर कई हजार गुना मुनाफा कमाती हैं। फाईजर कम्पनी 2,923,000 रुपये के पूँजी निवेश से 1975 में 3,47,600,000 रुपये का व्यापार करती है जिसमें शुद्ध मुनाफा 16,600,000 रुपये का है। उसकी कुलबिक्री का 70: विदेशी क्षेत्र का है। देश में 10 बहुराष्ट्रीय

कम्पनियां 100 प्रतिशत पूँजी के साथ व्यापार कर रही हैं जिनमें से 6 कम्पनियां अपने फार्मूलों पर उत्पादन करती हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनमें से अधिकांश बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों का निवेश मूल कम्पनी के द्वारा संचालित उत्पादों को बेचने और व्यापार करने की गतिविधियों में ही लिप्त है। दूसरी तरफ लघु उद्योग के स्तर पर भारतीय दवा कंपनियां यांत्रिक फार्मूलों के आधार पर दवा बनाती हैं तो उन्हें अधिक मात्रा में दवायें प्राप्त करने में परेशानी होती है। हमें यह समझना होगा कि भारत की जरुरत विटामिन और दर्द निवारक दवाकों उत्पादन करना नहीं है बल्कि साधारण बीमारियों जैसे - शुगर, मलेरिया, टी.बी., कोढ, जैसी घातक बीमारियों की पर्याप्त मात्रा में सस्ती दवायें बनाना है जिसके सबसे अधिक रोगी हैं। सभी विदेशी कम्पनियां इस क्षेत्र में दवा बनाने से बचना चाहती हैं।

भारत सरकार द्वारा नियंत्रण

विदेशी कम्पनियों के संदर्भ में भारत सरकार ने 1 जनवरी 1974 को लागू होने वाले डत्ज्च एक्ट की धारा 29 के तहत अपने पास काफी शक्ति लेकर रखी हुई है। इन कम्पनियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश तय किए गये है। वह इस प्रकार हैं

1) विदेशी कम्पनियों की सभी शाखायें अपने आपको भारतीय कम्पनियों के रुप में बदल लेंगी और अपनी गतिविधियों की प्रकृति के अनुरुप 26-60 प्रतिशत के बीच भारतीय बाजार में भागीदारी करेंगी।

2) ओद्योगिक गतिविधियों में संलग्न सभी कम्पनियां 1973 के ओद्योगिक लाइसेंस पोलिसी की धारा 1 के तहत मानी जायेगी। निर्यात आधारित उद्योग में लगी हुई कम्पनियां या उत्पादन की गतिविधियों में लगी कम्पनियां जिनको अति आधुनिक तकनीकी चाहिए उन सभी को उनकी वर्तमान उत्पादन के लिए अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा गैर निवासी ब्याज 74% तक ला सकेंगी।

3) वे सभी शाखायें और कम्पनियां जो उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न हैं और अपने लक्ष्य का 60% से कम उत्पादन नहीं करती है। उन्हें अपने निर्यात के लिए 51% पर अपने अत्याधुनिक उत्पादकों द्वारा अनिवासी ब्याज वापिस लाने की अनुमति है।

4) वे कम्पनियां जो व्यापार और गैर-उद्देश पूर्ण क्षेत्रों में संलग्न हैं। उनको अपना गैर-निवासी ब्याज 40% तक कम कर देना चाहिए।

यह दिशा निर्देश लागू किये गये थे जिनको वैधानिक ताकत प्राप्त थीं।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

जो भी कम्पनी इनका पालन नहीं करेगी उनको लाभांश और अन्य तरह की फीसों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। अन्यथा FERA 1973 की धारा 50 और 56 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि विदेशी कम्पनियों की पकड़ को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को पूरा न कर पाने के कारण 13 विदेशी कम्पनियों ने, जिनमें कोका कोला, एक्सपोर्ट कारपोरेशन, कोलम्बिया ग्रामोफोन, वर्ड ट्रेड कारपोरेशन, बेनसरिन्स इण्डिया लि. प्यूमेटिक टूल कम्पनी लि. इत्यादी शामिल है, अपने प्रतिष्ठान बंद करने का फैसला लिया था। यह भी जानना जरुरी है कि IBM, ICC और कोका कोला जैसी कम्पनी ट्रान्सफर प्राईजिंग के धंधे में रंगे हाथों पकड़ी गई थी।

नई कम्पनियों के लिए 'फेरा' लागू नहीं होता

फेरा कानून उन्हीं कम्पनियों के ऊपर लागू होता था। जो भारत में 1974 से पहले से अपने उत्पादन में लगी हुई थी। जब फेरा कानून लागू हुआ तो वह नई आने वाली विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं होता था क्योंकि वे कम्पनियां तो पहले से ही भारत सरकार की ओद्योगिक नीति के अनूरुप आ रही थीं। क्योंकि यह ओद्योगिक नीति 23 दिसम्बर 1977 को लोकसभा में पारित हुई थी। इस नीति में विदेशी तकनीकी और विदेशी निवेश से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण नीतियां थी जिसमें घोषणा की गई थी कि "- स्वदेशी तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी उच्च तकनीकी और सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, जिनमें भारतीय कौशल्य और तकनीकी उतना विकसित नहीं है, तकनीकी के लगातार संवर्धन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इस सभी क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि वह विश्व की बेहतरीन तकनीकों को खरीदे और राष्ट्र की आवश्यकता के लिए इन तकनीकों को उपयोग करें।" उन सभी भारतीय कम्पनियों को जिनको विदेशी तकनीकी आयात करने की अनुमति मिली थी उन्हें इन आयातित तकनीकों के ऊपर शोध करने और उन्हें विकसित करने के लिए बाध्य किया गया। ताकि विदेशी तकनीकी को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सके। सरकार इन विदेशी समझोतों को संचालित करने के लिए विदेशी निवेश आयोग के अर्न्तगत एक राष्ट्रीय परिषद भी बनायेगी जो लगातार इन प्रयासों का निरीक्षण करेगी।

सरकार ने भारतीय उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूँजी निवेश और विदेशी कम्पनियों के बारे में एक नीति की घोषणा की, जिसका सम्बन्ध सीध वर्तमान की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से है जिनके ऊपर फेरा के प्रावधनों को सख्ती से लागू किया गया था। इस कानून के अर्न्तगत विदेशी कंपनियो के निवेश में थोडा कमी आने के बाद कम्पनियों का सीधे गैर-निवासी निवेश 40: से अधिक नहीं होता था। उन्हें भारतीय कम्पनियों जैसी ही सुविधायें दी गई और भविष्य में उनके विकास के लिए दिशानिर्देश वही तय किए गये जो भारतीय कंपनियों के लिए तय थे।

भारत सरकार ने यह तय कर लिया था कि भारत के ओद्योगिक विकास के लिए आवश्यक तकनीकी और विदेशी निवेश इसी शर्त पर स्वीकार किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में तकनीकी आवश्यकता नहीं थी उन क्षेत्रों में काम करने वाली कम्पनियों/समझोतों को नविनीकृत नहीं किया गया। और इन क्षेत्रों में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों को फेरा कानून के अनुसार गतिविधियां करने तथा अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उद्यमियों को दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने उन सभी क्षेत्रों की सूची दुबारा से प्रकाशित की जिनमें स्वदेशी तकनीकी पूरी तरह से विकसित थी और जिनमें किसी भी तरह के विदेशी पूँजी निवेश और तकनीकी की आवश्यकता नहीं थी। सरकार द्वारा पास किये गये सभी विदेशी निवेशों के लिए लाभ, रोयल्टी या लाभांश को तय करने का पूरी आजादी होगी और पूँजीगत विषयों को तय करने की भी आजादी होगी। सभी के लिए एक समान कानून और नियम होगे। नियम के अनुसार प्रभावशाली नियंत्रण और स्वामित्व मुख्य रुप से भारतीयों के हाथों में होना चाहिए यद्यपि सरकार उच्च निर्यात वाली कम्पनियों को और उच्च तकनीकी की वाले क्षेत्र में कुछ छूट दे सकती है। 100: निर्यात करने वाली मामलों में सरकार पूरी तरह से विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनी को स्वीकार कर सकती है।

दवा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित सरकार के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हैं। 29 मार्च 1978 को पेट्रोलियम और रसायन तथा खाद मंत्री ने लोकसभा में यह कहा कि "सरकार ने यह तय किया है कि थोक दवा बनाने वाली कम्पनियाँ जो बहुत उच्च तकनीकी के क्षेत्र में नहीं है। या जो दोनों में है उन्हें अपनी विदेशी इक्विटी 40: तक कम करनी होगी और बाकी की 60: इक्विटी, जो अभी वर्तमान मे विदेशी शेयर धारकों के हाथ में है, को सरकारी वित्तीय या सार्वजनिक संस्थानों में विनिवेश किया जायेगा। और बाकी की भारतीय निवेशकों के लिए रखी जायेगी। विशेष रुप से उन कम्पनियों में काम करने वाले भारतीय लोगों को शेयर धारक बनने की प्राथमिकता दी जायेगी।

विदेशी कम्पनियां घरेलू दवाईया बनाने के काम में लगी हुई हैं। जिसमें किसी भी तरह के विस्तार की जरुरत नहीं होती और नहीं वे इसके अतिरिक्त कोई गतिविधि को हाथ में लेती है।

विदेशी कम्पनियों के लिए लघुउद्योग क्षेत्र पूर्णत: वर्जित होगा। किसी

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

भी विदेशी कंपनी को दवा क्षेत्र में लोन लाइसेंस नहीं मिलेगा। वर्तमान के लोन लाइसेंस के आधारपर किसी भी विदेशी कम्पनी की कुल आयव्यय अनुच्छेद 1 में नहीं गिनी जायेगी बल्कि पूर्णत: व्यापारिक गतिविधि के रुप में माना जायेगा। केवल बड़ी मात्रा में दवा बनाने के लिए ही विदेशी कंपनियों के आवेदन को स्वीकार किया जायेगा।

अभी हाल के वर्षो में विदेशी कम्पनियों के लिए भारत सरकार द्वारा इस तरह की कठोर नीति को अपनाने का अर्थ यह है कि भारतीय उद्योग जगत को स्वालंबी बनाने की दिशा में कदम उठाये गये है। इस तरह की नीतियों की घोषणा से एक अच्छा वातावरण बना था। उदाहरण के लिए उच्च प्राथमिकता वाली चाय उद्योग के वर्गीकरण में विदेशी पूँजी की स्थिति 74: तक कम की गई जबकि यह तथ्य सामने था कि 1951 की ओद्योगिक नीति के पहले वर्ग में चाय कम्पनियां उत्पादक ईकायों के रुप में सूची बद्ध नहीं थी।

मिल्कियत के सवाल पर भारत सरकार का पक्ष यह दिखाता है कि विदेशी चाय कम्पनियां दुनियां के बाजार में अपना हिस्सा रखती थी। उनके साथ समझौते की आवश्यकता है लेकिन उनको यह आश्वासन देना होगा कि विश्व चाय बाजार में भारत का भी हिस्सा होगा।

दूसरा अधिकांश मामलों में फेरा के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत, कुल इक्विटी के संदर्भ में इक्विटी में हिस्सा कम करने के लिए आवश्यक प्रतिशत जरुरी है। इनमें से अधिकांश कम्पनियां जिनको इक्विटी कम करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था उन्होंने भारत सरकार से अपनी विस्तार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी उनका यह विस्तार मानो सुरक्षित पूँजी बढाकर करना था या फिर नई गतिविधियों के लिए पूँजी निवेश करने का था। उदाहरण के लिए- ब्रिटानिया बिस्किट कम्पनी जिसको अपना गैर निवासी गतिविधियां कम करने के लिए कहा गया था उसे 18 मिलियन डालर की पूँजी नई इक्विटी के रुप में प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। जिसके कारण, एक शोध सर्वेक्षण के अनुसार, विमको लि., मुल्लैर, फिलिप्स, डयू फाइन्टर फ्रेन लि., रेकेट एण्ड कोलगेट लि., हिन्दुस्तान डयू ओलीवर लि., हिन्दुस्तान लीवर इण्डिया, फोइल्स, ब्रिटानिया बिस्किट कम्पनी, एशिया लि., केडबरी इण्डिया लि. आदि कम्पनियों ने अपना पूँजी आधार बढ़ा लिया। और पूँजी कम करने के प्रावधान के बाद लांभाश देने में बढ़ोत्तरी कर दी। ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कम्पनी ने विजार सुल्तान टोबेको और भारतीय ईकाई ने अपनी विदेशी इक्विटी 65.1: से घटाकर 34.8: कर दी थी। जिसके लिए उन्होंने 1.77 मिलियन शेयर 10 के आधार मूल्य पर 6 रुपये के प्रीमियम के साथ बाजार में उतारे। जिसमें से 87: शेयर आम आदमी ने खरीदे और 3: कम्पनी के डायक्टर और कर्मचारियों ने खरीदे।

इसी तरह युनियन कार्बाइड ने, युनिकार्बाइड इण्डिया लि. में 50.9 प्रतिशत पूँजी कम की ओर 3,294,500 शेयर (10 रुपये) 6 रुपये की प्रीमियम पर बाजार में निकाले।

भारत सरकार की इस नीति का कई अर्न्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। मुख्य रुप से बिजनेस इण्टरनेशनल कोरपोरेशन के अध्यक्ष मि. ओरविले, एल. फ्रीमेन ने जार्ज फर्नान्डिज की इस नीति का विरोध करते हुए कहाँ और एक धमकी जैसी दी थी कि भारत को विदेशी कम्पनियों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए उसके जवाब में जार्ज फर्नान्डिज ने जो कहा वह इस प्रकार है - "जब वे पैदा भी नहीं हुए थे उसके काफी पहले से विदेशी कम्पनियां साबुन, तेल, और हर तरह के उपभोक्ता सामान बनाती है। प्रांसगिक प्रश्न यह है कि आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार रखते है। पुरानी विदेशी कम्पनियां यहाँ है और नई कम्पनियां आ रही है। लेकिन यदि हमारे राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह से चोट होगी तो हम सहन नहीं करेंगे। नई अर्थनीति एक तरह के राजनैतिक और आदर्शवादी सिद्धातों के आधार पर देश के ओद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई है।"

इस नीतिगत वक्तव्य से विदेशी पूँजी निवेश को लचीला बनाये रखने की दिशा मिलती है। 1 मार्च 1978 में भारतीय रिजर्व बैंक की एक बुलेटिन में जो आंकड़े दिये गये उनसे यह दिखाई देता है कि इस निर्णय के बाद भारत में विदेशी पूँजी निवेश में वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 1974 के अन्त तक सीधा पूँजी निवेश 1973 करोड़ रुपये हुआ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 95 करोड़ ज्यादा था। लोकसभा में दिए गये उत्तर में भी यह कहा गया कि 31-3-78 तक भारत में काम करने वाली सभी विदेशी कम्पनियों की कुल सम्पत्ति 41,300 मिलियन रुपये थी। यह आंकड़े गलती से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी की पकड़ शीर्षक के तहत किये गये सर्वेक्षण में से निकल कर आते है। यदि फेरा के दिशा निर्देशों के साथ अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विदेशी पूँजी निवेश को जोड दे तो यह आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ जाता है। 1977 में लागू की गई इस नई आद्योगिक नीति ने विदेशी कंपनियों के ऊपर एक नकेल का काम किया था। लेकिन 1980 के बाद जब नई सरकार आई तो फिर से इन नीतियों को उलट कर विदेशी कंपनियों को लाभ देनेवाली नीतियां अपनाई गई।

1991 में नरसिम्हाराव की सरकार ने तो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति के तहत विदेशी कंपनियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिये है जिसके तहत विदेशी कंपनियों की बाढ़ आ गई। रुपये के अवमूल्यन ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी नीचे गिरा दिया कि हमारे ऊपर विदेशी कर्जा लगातार बढ़ता गया।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

4.

युद्ध की राजनीति और हथियारों का व्यवसाय

युद्ध कभी भी राजनीतिक कारणों के लिये नहीं बल्कि आर्थिक कारणों के लिये ही लड़े जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बात एकदम शीशे की तरह साफ नजर आती है कि इन विशालकाय कम्पनियों के आपसी हित जब टकराते हैं तो उसका परिणाम पूरी मानव जाति को झेलना पड़ता है। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में दखल देने का निर्णय तभी लिया जब उसने देखा कि अमरीकी कम्पनियों के आर्थिक हित चौपट होते जा रहे हैं।

सन् 1914 तक अमरीकी कम्पनियों का यूरोपीय देशों के साथ कुल व्यापार 16.9 करोड़ डालर (वर्तमान समय में लगभग 3.42 अरब रूपये के बराबर) का, जो 1916 तक आते-आते मात्र 11.59 लाख डालर (वर्तमान समय में लगभग 2.08 करोड़ रूपये) रह गया था। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में आयी भारी गिरावट से अमरीकी कम्पनियों को बहुत अधिक घाटा हुआ। अब अमरीकी कम्पनियों ने इस घाटे को पूरा करने के लिये अन्य मित्र देशों में सेंध लगाना शुरू किया और इसमें वे काफी सफल भी रहे। 1914 तक यूरोपीय देशों के बाहर दुनिया के अन्य देशों में अमरीकी कम्पनियों का प्रति वर्ष का कारोबार 82.4 करोड़ डालर था, जो 1916 में बढ़ कर 321.4 करोड़ डालर हो गया था। इस व्यापार में एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री का शामिल था। क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था और अमरीकी कम्पनियों ने अब हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया था। युद्ध के हालातों में अमरीकी कम्पनियों को हथियारों के व्यापार से अकूत फायदा हुआ। सन् 1916 के बाद हर बड़ी कम्पनी ने अपनी कुल पूँजी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के उत्पादन में लगा दिया था।

इस घटना के बाद तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने जर्मनी के खिलाफ यह कहकर कि अधिकार शान्ति से अधिक मूल्यवान हैं" युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे युद्ध के दौरान 375 अरब डालर के हथियार कम्पनियों द्वारा विभिन्न देशों को बेचे गये। अब कम्पनियों के मुँह हथियारों का खून लग चुका था, अत: अब कम्पनियों द्वारा हथियार उत्पादन में सबसे अधिक पूँजी निवेश किया जाने लगा। कई कम्पनियों ने अपने पुराने उत्पादों को बनाना बन्द करके हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया। कई और कम्पनियों ने उपभोक्ता सामग्री के साथ-साथ हथियारों के उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा। युद्ध के बाद कम्पनियों के कार्य करने के तरीके में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कम्पनियों ने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिये आपस में मिलकर 'कार्टेल' (कई कम्पनियों को मिलाकर एक समूह) बनाना शुरू कर दिया। बाजारों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता से बचने के लिये कम्पनियों ने यह कदम उठाया। प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इतिहास में 'कार्टेलाईजेशन' के नाम से मशहूर है। अर्थात् शक्तियों का और अधिक केन्द्रीकरण होता गया। पूँजी कुछ केन्द्रों में ही सिमटती गयी। तकनीकी पर कुछ चुनी हुयी कम्पनियों का ही अधिकार होता गया। इस दौर की कुछ प्रमुख कम्पनियाँ जो हथियार उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही थीं और जिन कम्पनियों ने कई अन्य कम्पनियों को अपने में मिलाकर कार्टेल बनाये थे निम्न थीं :-

जनरल मोटर्स (General Motors), फोर्ड (Ford), स्टैन्डर्ड आयल (Standard Oil), ड्यूपान्ट(Dupont), आई.सी.आई. (I.C.I), एलाइड केमिकल्स (Allied Chemicals), रेमिंगटन (Remington), कैंटर पिलर ट्रैक्टर (Cater Pillar Tractor), क्राइसलर कार्पोरेशन फायर स्टोन (Fire Stone), जनरल इलैक्ट्रीकल्स कार्पोरेशन (General Electricals Corporation), इन्टरनेशनल हार्वेस्टर (International Harvester), कोल्ट (Colt), कोका-कोला (Coca Cola), आई. बी.एम. (I.B.M.), आदि।

द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी रूपरेखा हेड्रिख मुल्लैर द्वारा बनायी गयी थी जिसके तहत पालैण्ड के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किया गया। हैड्रिख मुल्लैर, हिटलर के दाहिने हाथ के रूप में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पद पर जर्मन सेना के संचालन के लिये नियुक्त हुआ था।

इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हैड्रिल मुल्लैर द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुख्यात बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई.टी.टी. का प्रमुख था। यह बहुराष्ट्रीय

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

कम्पनी युद्ध के समय में फासिस्ट गुट को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। इसके अलावा अपनी सहयोगी कम्पनी 'फोके बुल्फ एयर क्राफ्ट कार्पोरेशन' के साथ मिलकर बमवर्षक विमानों की आपूर्ति फासिस्ट गुट को कर रही थी। सम्पूर्ण युद्ध के दौरान आई.टी.टी. की संचार सेवाओं ने नाजी युद्ध तन्त्र को सीधी सहायता की थी। पर युद्ध समाप्त होते ही यह कम्पनी अमरीकी सेना की भी प्रमुख ठेकेदार बन गयी और इसके अधिकारी मित्र राष्ट्रों के गुप्तचरों के साथ मिलकर घनिष्ठता से काम करने लगे। मजेदार बात यह थी कि आई.टी.टी दोनों ओर से युद्ध में लड़ रही थी। फासिज्म के खिलाफ यह कम्पनी अमरीका व सोवियत संघ को मदद कर रही थी तथा दूसरी ओर नाजी सेनाओं को मदद कर रही थी।

यह अत्यन्त ही विचित्र लगता है कि युद्ध समाप्ति के 30 वर्ष बाद आई.टी.टी. कम्पनी को अमेरिकी सरकार की ओर से 2 करोड़ 60 लाख डालर इस बात की क्षति पूर्ति के लिये प्राप्त हुये कि अमेरिकी विमानों ने जर्मनी में कम्पनी (आई.टी.टी.) के प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुँचाया था। इस प्रकार आई.टी.टी. ने एक युद्ध के मैदान से तीन-तीन आर्थिक फसलें काटीं। दो बार अपने मुख्यालय के माध्यम से अमेरिका से और एक बार अपनी सहायक कम्पनी के माध्यम से जर्मनी से। यह गौर किया जाना चाहिए कि युद्ध के पूर्व भी इस कम्पनी के जर्मन सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख गोयरिंग से अत्यन्त ही मधुर सम्बन्ध थे, जिसके कारण कम्पनी के हिटलर के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध बने थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद अमेरिका की 23 बड़ी कम्पनियों ने नाभिकीय हथियारों को बनाना शुरू किया। इन हथियारों के परीक्षण स्थल बने अफ्रीका व एशिया के गरीब व छोटे देश। हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगीं। अब यह हथियारों का व्यवसाय कम्पनियों के फलने-फूलने का आधार बना। जो आगे चलकर वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, ईरान-ईराक युद्ध व कई अन्य छोटे युद्धों में और अधिक तेजी से फैलता गया।

ईरान के शाह और प्रतिक्रियावादी अरब हुकूमतों ने हथियारों को खरीदने में सैकड़ों अरब डालर खर्च किये हैं। इजरायल, चीन और मिस्र की सरकारें भी हथियारों के बढ़ाव को कायम रखने में सक्रिय रही हैं। इजरायल-मिस्र समझौते के बाद मध्य-पूर्व में अमरीका के सैनिक औद्योगिक समुच्चय के लिये मुनाफे कमाने की नयी संभावनायें पैदा हो गयी। ईरान व अफगानिस्तान की

घटनाओं से भी उन्हें ऐसे ही मौके मिले। जापान और चीन के बीच सम्पन्न तथाकथित शान्ति समझौते ने जिसमें माओवादियों ने, नायकत्ववाद के बारे में एक विरोधी लाबी तैयार की, मित्शूविशी, कावासाकी, हिताची, जोसेन और अन्य विशालकाय जापानी उद्योगों के मुनाफों में भारी वृद्धी कर दी। पीकिंग के दूत कर्जों और हथियारों की तलाश में पश्चिम में सारे देशों को छाने डाल रहे हैं।

अभी हाल में अमरीकी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने लाकहीड, मेकडोनाल्ड-डगलस और बोइंग जैसे दर्शनीय स्थानों में रूचि दिखायी है। उनको श्लेसिंगर, नन और जैकसन जैसे बदनाम युद्धवादियों के द्वारा सैर करायी गयी। बोलीबिया, ब्राजील, चिली, यूनान और इंडोनेशिया में दक्षिणपंथी षड्यन्त्रकारियों को अमरीका सरकार की सलाहकार निगमों ने सहायता पहुँचायी और इसके बदले में इन देशों के सेनाध्यक्षों ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करायी हैं। थल सेना और नौ सेना के लगभग 500 प्रमुख अड्डों और सैनिक हस्तक्षेप के दर्जन से उपर नियंत्रणकारी चौकियों पर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अमरीकी झंडा गाडा गया है, वहाँ अमरीकी कंपनियाँ घुस गयीं। विश्वव्यापी सैनिक साम्राज्य का निर्माण करना इनके लिये एक अच्छा धंधा रहा है। जबकि इन कंपनियों के समर्थकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मूलत: एक शान्तिपूर्वक समाज की स्थापना के लिये सुंदर-सुंदर चीजों का निर्माण करने में लगी हुई हैं। इन कंपनियों का बचाव करने के लिये कितने ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल क्यों न किया जाय, और यह प्रमाणित करने के लिये कितनी ही जी-तोड़ मेहनत क्यों न करें, कि दुनिया में स्थायित्व पैदा हो गया है और राष्ट्रों की हालत में सुधार हो गया है, सैनिक खर्चों में कटौती की गयी है, लेकिन तथ्य उल्टा ही प्रमाणित करते हैं। हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि हथियारों का उत्पादन करने और कानूनी तौर पर उनका निर्यात करने में अमरीका की एक हजार से ज्यादा कंपनियाँ लगी हुई हैं। उनमें वे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जो दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये जाने जाते हैं। युद्ध सामग्री के निर्माण में एक्सोन (तेल), जनरल मोटर्स (मोटर), आई.बी.एम. (कम्प्यूटर), आर.सी.ए. (टी. वी. सैट), गुडईयर (टायर), डूयूपोंट (रसायन), सिंगर (सिलाई की मशीनें), वेस्टिंग हाउस (बिजली के सामान) और गल्फ आयल जैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं। इन निगमों की कारगजारियों के कारण स्थायी शांति नहीं रह पाती। बल्कि सच तो यह है कि ये निगमें लगातार दुनिया को युद्ध के कगार पर खड़ा करने की कोशिश में लगी रहती हैं।

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण ने विशेष तौर पर, उन भ्रांतियों को अधिक धक्का पहुँचाया जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा फैलायी गयी थीं। वियतनामी जनता के लिये इस युद्ध के भयंकर परिणाम सर्वविदित हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अमरीकी लोगों को भी हिन्द-चीन के जंगलों में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फायदा हुआ केवल इन बहुराष्ट्रीय निगमों को।

1955 से लेकर वियतनाम युद्ध की समाप्ति तक इन निगमों को हथियारों के 75 प्रतिशत आर्डर प्राप्त हुये। उस काल में अमरीकी सेना की शस्त्रों की आपूर्ति करने वालों की सूची काफी कुछ कहती है-

बोईग	-	1800 करोड़ डालर
जनरल डायनामिक्स	-	1400 करोड़ डालर
नार्थ अमेरिकन एवियेशन इन कार्पोरेशन	-	1330 करोड़ डालर
यूनाईटेड एयर क्राफ्ट	-	1160 करोड़ डालर
जनरल मोटर्स	-	1050 करोड़ डालर
डगलस	-	850 करोड़ डालर
आई.टी.टी.	-	710 करोड़ डालर
मार्टिन मारिये	-	660 करोड डालर
ह्यूग्स	-	470 करोड़ डालर
मेक्डोनेल	-	570 करोड़ डालर
स्पेरी रेंड	-	560 करोड़ डालर
रिपब्लिक	-	530 करोड़ डालर
ग्रुमेन	-	420 करोड़ डालर
बेनडिक्स	-	410 करोड डालर
वेस्टिंग हाउस	-	390 करोड़ डालर
कर्टिस राइट	-	380 करोड डालर
रेथियोन	-	330 करोड डालर
आई.बी.एम.	-	320 करोड़ डालर

इन निगमों को युद्ध सामुग्री के आर्डरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस सदस्यों और सीनेटरों की मदद से मिला था।

इजरायल भी इस बात को स्वीाकरने लगा है कि "मिसाइलों का व्यापार संतरों से अधिक लाभदायक है" - ये शब्द वहां के प्रधानमंत्री ने हाल में ही व्यक्त किये है। इजरायल हथियारों को बेचने में समर्थ है। वहाँ इन हथियारों का उत्पादन 'राकवेल', 'लाकहीड', 'वानिया', 'जेनिथ', 'वेस्टिंग हाउस', 'मफीनबोल',

'मेग्रावोक्स', 'एयरोजोट', 'जनरल न्यूक्लियोनिक्स', 'लिंग-टेक्को-वोग्ट' आदि निगम कर रहे हैं। इजरायल के शस्त्र उद्योग के संरक्षकों में ड्यूश बैंक भी शामिल है जो पश्चिम जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक हैं। यह बैंक वहाँ के निगमों को वित्त मुहैया कराता है। पिछले 10-12 वर्षों में यहाँ के निगमों के निर्यात में 50 गुना वृद्धि हुई है। आज यह निर्यात 1000 करोड़ यूरो को पार कर चुका है। ये निगम जेट (लड़ाकू बमवर्षक), आस्टंड - 1124 (समुद्र तटीय गश्ती विमान), फौगा - माजिस्टर (बमवर्षक), अरावा (सैनिक परिवहन विमान), जहाज से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र, 155 एम.एम. तोपें, प्रक्षेपास्त्र ढोने वाले जहाज तक बेचते है। प्रिटोरिया की सरकार इनके मुख्य ग्राहकों में से एक हैं।

नाभिकीय हथियारों को बनाने की प्रौद्योगिकी को बेचना विशेष रूप से विनाशकारी है। दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य में नाभिकीय हथियारों का विकास इन निगमों की सहायता से किया जा रहा है। ये जनता की माँग को अनदेखा करके उनके उत्पादन में जुटे हैं। ये निगमें उन मानदण्डों तक का उल्लंघन करती हैं जिनको सरकारें मानती हैं अभी हाल में अर्जेटीना को एक निगम द्वारा नाभिकीय संयंत्र और प्रोद्योगिकी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अर्जेटीना की सरकार इस बात की समुचित गारंटी नहीं दें रही थी कि उक्त संयंत्र का उपयोग सैनिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जायेगा, पर फिर भी पश्चिम जर्मनी के निगम ने उस सरकार को प्रौद्योगिकी व रियेक्टर दोनों बेचे।

दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार के बाद पश्चिम जर्मनी में सामरिक राकेटों के विकास करने और इनके निर्माण करने पर रोक लगा दी गयी थी परन्तु ओ.टी.आर.ए.जी. कंपनी की पारराष्ट्रीयता का लाभ उठाते हुये इस निगम से कुछ नहीं कहा गया। फिर पश्चिम जर्मनी को यह विचार आया कि प्रक्षेपास्त्र व्यापार किसी अन्य देश की धरती से किया जा सकता है, अत: इस कंपनी ने जायरे में एक क्षेत्र की रियासत हासिल कर ली और प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र का विकास कर लिया। जनता के सामने इस पूरे सौदे को व्यापारिक कह कर प्रस्तुत किया गया। अब जायरे के उस क्षेत्र का इस्तेमाल सारे अफ्रीका को धमकाने के लिये किया जा रहा है। हथियारों का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नीति का एक मूल अंग है। वे इसको मेहनतकश जनता की कीमत पर मुनाफों का एक स्थायी स्रोत मानती हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से लेकर 1969 के बीच अमेरिकी कम्पनियों का विश्व व्यापारी पूँजी निवेश 72 अरब डालर से बढ़कर लगभग 708 अरब डालर हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर के कुल पूँजी निवेश का

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

65 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी कम्पनियों के पास हो गया।

इसके अतिरिक्त सन् 1952 के बीच में अमेरिका में बनी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को अपने बाजारों को विकसित करने हेतु 17 अरब डालर की अतिरिक्त अमेरिकी सहायता दी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप की प्रति व्यक्ति आय नाटकीय तरीके से बढ़ गयी। मार्शल योजना की यह सफलता थी, जिसके कारण यूरोपीय बाजार में अमरीका की वस्तुओं की मांग और अधिक बढ़ गयी। अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का वास्तविक रूप सन् 1952 में देखने को मिला। विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता गरीब देशों में बाजार पैदा करने के काम आती है, न कि उन देशों का विकास करने में। यूरोपीय अर्थशास्त्री रेमन्ड वर्नोन ने योजना पर टिप्पणी करते हुये कहा था । "अमेरकिा के लिये मार्शल योजना एक ऐसा राजनीतिक हथियार है, जिससे वह अपने देश की कम्पनियों को यूरोप में चल रहे आर्थिक युद्ध मे सम्पूर्ण विजय की ओर ले जा रहा है और दुनिया में अमेरिकी आर्थिक-आधिपत्य की जड़ों को मजबूत कर रहा है। इस मार्शल योजना के दूरगामी परिणाम होंगे। दुनिया के अन्य गरीब देश भी अमेरिकी मदद पाने क लिये एक दूसरे से होड़ करेंगे जिसकी वजह से उनका सही विकास अवरूद्ध होगा और वे एक ऐसे विकास के रास्ते पर धकेल दिये जायेंगे जहां से वापस लौटना उन गरीब देशों के लिये फिर असम्भव होगा।"

सन् 1960 के आते-आते रेमन्ड बर्नोन द्वारा की गयी भविष्यवाणी अक्षरश: सत्य सिद्ध हुयी। एशिया व अफ्रीका के देशों में विदेशी मदद के बहाने अमेरिकी व अन्य यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ बढ़ने लगी। अब गरीब देशों को आर्थिक मदद देना अमेरिका की रणनीति बन गयी। आने वाली अमेरिकी सरकारों ने इस परम्परा को लगातार आगे बढ़ाया। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन इसी दशक में हुआ। जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनियों के यूरोप में बढ़ते प्रभाव को कम करने तथा यूरोपीय कम्पनियों को आगे बढ़ाने के लिये था। इसमें यूरोपीय देश आंशिक रूप से सफल रहे। क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशों के पास विदेशी मुद्रा (डालर) का अभाव था। लेकिन यूरोपियन आर्थिक समुदाय के गठन के बाद यूरोपीय बाजार आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौर के बाद स्थिर होने लगा इसी दौर में यूरोपियन कम्पनियों का उदय हुआ।

5.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आपसी विलय

पश्चिम की बाजारू संस्कृति का एक प्रमुख सिद्धान्त है- प्रतियोगिता। अर्थात् कम्पनियों में यदि आपसी प्रतियोगिता होगी तो माल की गुणवत्ता उच्चस्तरीय होगी, दाम कम होगा और अन्ततः उससे उपभोक्ता को ही फायदा होगा। बाजार में एकाधिकार को रोकने के लिये जरूरी है कि कम्पनियों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता हो जिससे कि कोई कम्पनी बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित न करे। इसके लिये आवश्यक है कि एक से आधिक कम्पनियाँ बाजार में हों जो एक सी वस्तुओं का उत्पादन करती हों, जिससे उपभोक्ता को वस्तुओं के चयन, मूल्य व गुणवत्ता आदि का समुचित अधिकार मिल सके। वह अपनी पसन्द से चीजों को खरीद सके। कम्पनियों की स्वस्थ प्रतियोगिता से बाजार के भी आर्थिक हितों में वृद्धि हो।

आधुनिक बाजार सिद्धान्त की ये बातें एकदम बेबुनियाद हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मुनाफाखोरी की संस्कृति ने इन सभी बुनियादी सिद्धान्तों को नकारा है। आपसी प्रतियोगिता से बचने के लिये ये कम्पनियाँ आपस में समझौते करती हैं। मुनाफाखोरी को अधिकतम बनाये रखने के लिये कम्पनियाँ बाजारों पर एकाधिकार रखती हैं। इस एकाधिकार व मुनाफे को उच्चतम बिन्दु तक पहुँचाने के लिये ये कम्पनियाँ किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक दूसरे से गलाकाट प्रतियोगिता में लिप्त रहने वाली ये कम्पनियाँ आपस में विलय भी कर सकती हैं। अधिकांश चर्चित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जन्म इसी विलय की प्रक्रिया से चलते हुआ है। उदाहरण के लिये :-

1- ब्रिटिश लीलैण्ड मोटर कार्पोरेशन (British Leyland Corporation)
2- इन्टरनेशनल कम्प्यूटर लिमिटेड (International Computer Limited)
3- द फ्रेन्च इलैक्ट्रीकल कम्पनी (The French Electrical Company)

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

fcfV'k yhy.M eksVj dkiksjs'ku dk tUe

bUVju'kuy dEI;wVj dk tUe

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr iklr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

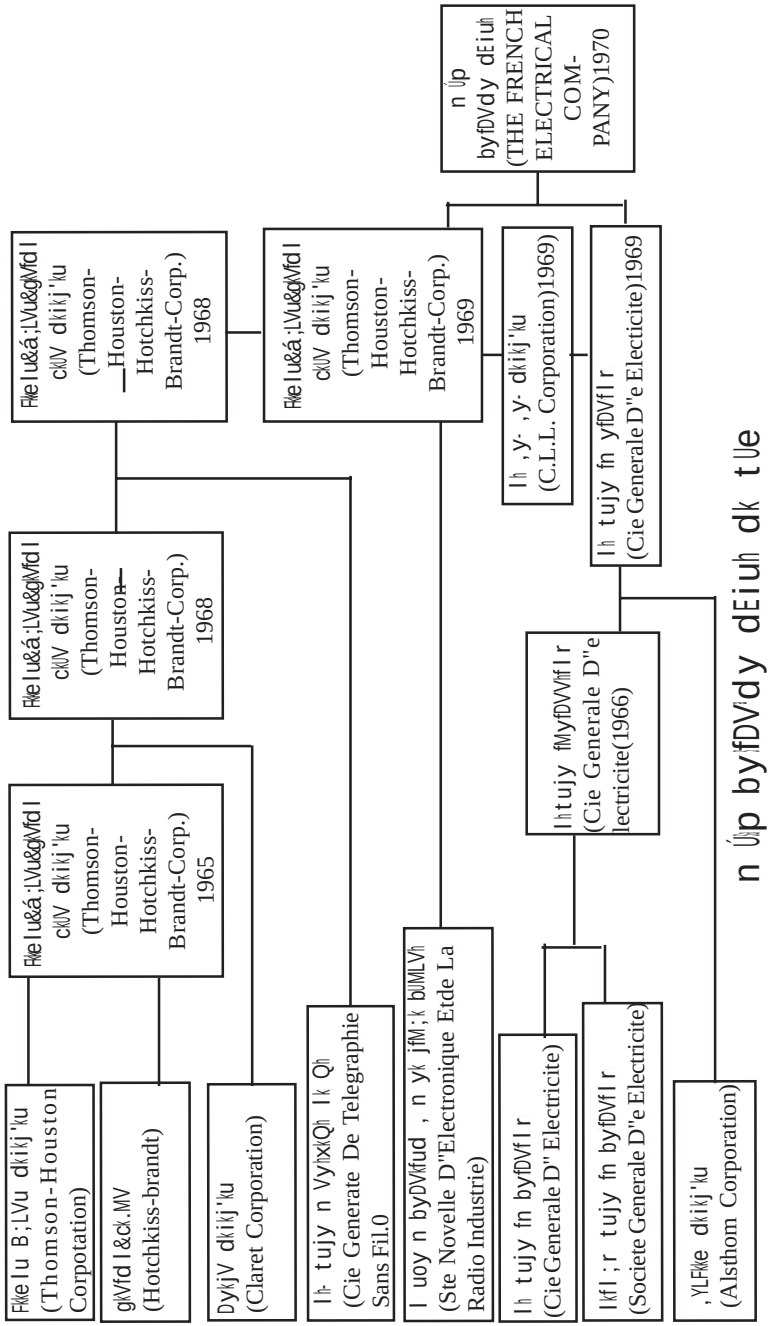

6.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में प्रवेश

भारत में विदेशी कम्पनियाँ तीन तरीके से कम कर रही हैं। पहला, सीधे अपनी शाखायें (Branch) स्थापित करके, दूसरा अपनी सहायक कम्पनियों (Subsidiaries) के माध्यम से, तीसरा देश की अन्य कम्पनियों के साथ साझेदार कम्पनी (Colaboration) के रूप में।

जून 1995 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3500 से कुछ अधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, अपनी शाखाओं या सहायक कम्पनियों के रूप में देश में घुसकर व्यापार कर रही हैं। 20,000 से अधिक विदेशी समझौते देश में चल रहे हैं। औसतन 1000 से अधिक नये विदेशी समझौते प्रतिवर्ष देश में होते हैं।

सन् 1972 के अन्त तक देश में कुल 740 विदेशी कम्पनियाँ थीं। जिनमें से 538 अपनी शाखायें खोलकर व 202 अपनी सहायक कम्पनियों के रूप में काम कर रही थीं। इनमें सबसे अधिक कम्पनियाँ ब्रिटेन की थीं। लेकिन आज सबसे अधिक कम्पनियाँ अमेरिका की हैं। समझौते के अन्तर्गत काम करने वाली सबसे अधिक कम्पनियाँ जर्मनी की हैं। 1977 में विदेशी कम्पनियों की संख्या 1136 हो गयी। आज सन 2008 में 4500 से कुछ अधिक कम्पनियां भारत में काम कर रही हैं।

आजादी के पूर्व सन् 1940 में 55 विदेशी कम्पनियाँ देश में सीधे कार्यरत थीं। आजादी के बाद सन् 1952 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटेन की 8 विशालकाय कम्पनियों के सीधे नियन्त्रण में 701 कम्पनियाँ भारत में व्यापार कर रही थीं। ब्रिटेन की अन्य 32 कम्पनियाँ, भारतीय कम्पनियों के साथ किये गये समझौतों के तहत कार्यरत थीं। ये 8 विशालकाय ब्रिटिश कम्पनियाँ सन् 1853 से ही भारत

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

में घुसना शुरू हो गयी थीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत लायी गयी ये कम्पनियाँ सन् 1860 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय उपमहाद्वीप के शोषण के लिये धारदार हथियार बन चुकी थीं। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित हो जाने के बाद ये कम्पनियाँ दुनिया के अन्य दूसरे देशों में शोषण करने चली गयीं।

ये 8 ब्रिटिश कम्पनियाँ निम्न थीं :-

1. एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी
2. मेक्लाइड एण्ड कम्पनी
3. मार्टिन एण्ड कम्पनी
4. बर्न एण्ड कम्पनी
5. डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी
6. आक्टेवियस स्टील एण्ड कम्पनी
7. गिलैण्डर अर्बुदनाट एण्ड कम्पनी
8. शा वालेस एण्ड कम्पनी

भारत में जैसे-जैसे विदेशी पूँजी का निवेश बढ़ता गया वैसे-वैसे विदेशी कम्पनियों की संख्या बढ़ती गयी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक आश्चर्यजनक सत्य यह है कि जिन विदेशी कम्पनियों ने भारत में पूँजी निवेश किया उनमें से अधिकांश कम्पनियों ने अपने निवेश करने के अगले वर्षों में ही अपनी निवेश की हुयी पूँजी के बराबर या उससे अधिक पूँजी कमा ली। बाकी अन्य कम्पनियों ने अधिकतम 5 वर्षों में अपनी निवेश की हुई पूँजी को कमा लिया।

हर क्षेत्र में घुसी हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

आज देश का छोटा-बड़ा प्रत्येक क्षेत्र इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं हैं, जिसे ये कम्पनियाँ न बनाती हों। दैनिक उपयोग के सामानों का उत्पादन करके ये विदेशी कम्पनियाँ घर-घर में घुसी हुयी हैं। खेती के काम में आने वाले जहरीले कीटनाशकों, खादों अन्य उपकरणों का उत्पादन करके इन विदेशी कम्पनियों ने हमारी आत्मनिर्भर खेती को अपना गुलाम बना लिया है। उद्योगों के क्षेत्र में रद्दी तकनीकी का इस्तेमाल करके वातावरण को विषैला कर दिया है। हवा, पानी और

मिट्टी भी अब प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं।

नीचे उन क्षेत्रों की सूची दी गयी है जिनमें घुसकर इन विदेशी कम्पनियों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया है-

कुछ प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र, जिनमें विदेशी कम्पनियाँ घुसी हुई हैं।

1. दैनिक उपभोग की सामग्री के क्षेत्र में
2. दवा उद्योग के क्षेत्र में
3. खाद, कीटनाशक, दवायें व खेती उपकरणों के क्षेत्र में
4. रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में
5. मोटर-गाड़ियों के उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में
6. भारी इंजीनियरिंग सामानों के उत्पादन के क्षेत्र में
7. इलेक्ट्रानिकी व इलैक्ट्रीकल सामानों के उत्पादन के क्षेत्र में
8. सैनिक रक्षा सामग्री के क्षेत्र में
9. फूड प्रोसेसिंग व प्लांटेशन (चाय, कॉफी, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ, चॉकलेट)
10. वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान में
11. सीमेन्ट उद्योग में
12. तेल शोधन व उत्पादन के क्षेत्र में
13. धातुओं के खनन तथा निष्कर्षण क्षेत्र में
14. जूट उद्योग में
15. सिले हुये (रेडीमेड) कपड़ों के उत्पादन क्षेत्र में
16. जूते व अन्य खेल सामानों के उत्पादन क्षेत्र में
17. रबर इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में
18. बच्चों के खिलौने व अन्य प्लास्टिक सामानों के उत्पादन में

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ताकत

भारत में इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कितनी ताकत है ? इनकी ताकत का एक अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी विशालकाय (Giants) 100 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चुनी गयीं हैं। जिनके बारे में 'फारचून' पत्रिका के जुलाई 2008 के अंक में एक टिप्पणी छपी थी :-

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

"पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर चुनी गयी 500 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। जितनी तरल परिसम्पत्ति इन 500 कम्पनियों के पास हैं, उसमें जरा सी भी हेर-फेर कर देने पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है" इन सभी कम्पनियों की शाखायें दुनिया के 125 से भी अधिक देशों में हैं। इन 500 कम्पनियों में से 100 कम्पनियाँ भारत में काम कर रही हैं। इन 100 में से 50 कम्पनियों का (प्रत्येक का) वार्षिक कारोबार भारत सरकार के वार्षिक बजट से अधिक है।

वर्ष 2008 में इन कम्पनियों की विश्व भर में बिक्री मुनाफा और कुलपूंजी तथा भारत में ये कम्पनियाँ किस रूप में कार्य कर रहीं हैं; इसका विवरण नीचे दी गयी तालिका में दिखाया गया है :-

अमेरीकन एम.एन.सी. (2008) American M.N.C.'s

एम.एन.सी.	रेवेन्युज	प्राफिट	असेटस
1. एक्सॉन (शाखा)	44285	45220	22805
2. वॉलमार्ट (शाखा)	405607	13400	163429
3. केवरॉन	263159	23931	116165
4. कोनोकोफिलीप्स	230764	17410	142865
5. जी.एम.	148979	30860	797769
6. जी.ई. (शाखा)	183270	17410	91047
7. फोर्ड (शाखा)	146227	14672	218328
8. ए.टी. एन्ड टी. (शाखा)	124082	12876	265245
9. हेलवेट पेर्कड (शाखा)	118364	8329	113331
10. वालेरोएनर्जी	118298	1131	34417
11. बैंक आफ यु.एस.ए. (शाखा)	113106	4008	1817943
12. सिटी ग्रुप (संयुक्त)	112372	27684	1938470
13. वर्कशायर हाथवे	107786	4994	267399
14. आई.बी.एम. (शाखा)	103630	12334	109524
15. मेलसन	101703	990	24603
16. जे.पी.मॉरगन	101491	5605	2175052
17. वेरीझॉन कम्युनीकेशन	97354	6428	202352
18. कार्डीनल हेल्थ	91091	1300	23448
19. सी.व्ही.एस. केअर मार्क	87471	3212	60959
20. प्राक्टर ऑण्ड गेम्बल (शाखा)	83503	12075	143992
21. युनाइटेड हेल्थ ग्रुप	81186	2971	55815
22. क्रोजर	76000	1249	23211
23. मॅराथान ऑइल	73504	3528	42686
24. कास्टको होलसेल	72483	1282	20682
25. होम डेपो	71288	2260	41164
26. जॉन्सन ॲन्ड जॉन्सन	63747	12949	84912
27. मोरगन सटानली	62262	1707	658812
28. स्टेट फार्म इन्स्युरंस	61343	541.8	172092
29. वेल पॉइंट	61251	2490	48403
30. डेल	61101	2478	26500
31. बोईंग (शाखा/संउद्योग)	60909	2672	53779
32. माइक्रोसॉफ्ट	60420	17681	72793
33. युनाइटेड टेक	58681	4689	56469
34. डाऊ केम	57514	579	45474
35. मेट लाईफ	55085	3209	501678
36. गोल्डमॅन सॅच	53579	2322	884547
37. वेल्स फारगो	51652	2655	1309639
38. सनको	51651	776	11150
39. यु.पी.एस.	51486	3003	31879
40. कॉटर पीलर	51324	3557	67782
41. मेडको हेल्थ सोलूशन्स	51258	1102	17010
42. फिजर	48296	8104	111148
43. टाइम वारनर	46984	103402	113896
44. पेप्सी को. (शाखा/संउद्योग)	43251	5142	35994
45. क्राफ्ट फूड्स	42867	2901	63078
46. लॉक हिड मारटीन	42731	3217	33439
47. कीसका	39540	8052	58734
48. वॉल्ट डिसनी	37843	4427	62497
49. ॲपल	32479	4834	39572
50. कोकाकोला	31944	5807	40159

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

7.

विदेशी पूँजी का धोखा

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जब भी दुनिया के किसी देश में व्यापार करने के लिये जाती हैं तो वे उस देश के लिये भारी सिर दर्द बन जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के किसी भी देश में काम करने से ऐसा नहीं है कि मात्र आर्थिक दुष्प्रभाव ही पड़ते हों अपितु उस देश में इन कम्पनियों के व्यापक और गहरे प्रभाव नजर आते हैं। क्योंकि इन कम्पनियों का चरित्र ही ऐसा है कि ये देश की नीतियाँ बदलवाने के लिये सीधे राजनैतिक हस्तक्षेप करती हैं। सामाजिक जीवन भी इन कम्पनियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहता है।

जब ये कम्पनियाँ काम करने के लिये अन्य देशों में जाती हैं तो उनके पीछे कुछ मिथ्या धारणायें काम करती हैं जैसे ये अपने साथ पूँजी लायेंगी, आधुनिक तकनीक देंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करायेंगी, देश का निर्यात बढ़ायेंगी, देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति को चुस्त-दुरूस्त रखेंगी, देश की आर्थिक संसाधनों में और अधिक वृद्धि करेंगी आदि-आदि। लेकिन असलियत ठीक इन सभी दावों से उल्टी होती है।

विदेशी कम्पनियों के पक्ष में सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश में पूँजी की बड़ी कमी होती है और पूँजी के अभाव में विकास नहीं हो सकता। इसलिये विदेशों से पूँजी आमन्त्रित करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है।

लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये विदेशी कम्पनियाँ बाहर से बहुत कम पूँजी लाती है, अधिकांश पूँजी यहां के बैंकों से कर्ज लेकर, यहाँ

की जनता से कर्ज लेकर और उनको शेयर बेचकर एकत्रित करती हैं। देश में जितनी भी विदेशी कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं, वे औसतन 5 प्रतिशत तक पूँजी ही बाहर से लाती है। बाकी 90 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक पूँजी ये भारतीय स्रोतों से ही एकत्रित करती हैं।

कितनी पूँजी, कितना धोखा भारत में व्यापार कर रही 45 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जब व्यापार शुरू किया तो कितनी पूँजी लगायी थी, इसके बारे में कुछ तथ्य नीचे आगे जा रहे हैं :-

बहुराष्ट्रीय कम्पनी	आने का वर्ष	लायी गयी पूँजी
शालीमार पेन्टस लि.	1901	63 लाख रुपये
बी.एस.टी. इंन्डस्ट्रीज लि.	1930	1.85 करोड़ रुपये
बाटा इण्डिया लि.	1931	70 लाख रुपये
हिन्दुस्थान लीवर लि.	1933	24 लाख रुपये
युनियन कार्बाईड इण्डिया लि.	1934	8.36 करोड़ रुपये
क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लि.	1937	3 करोड़ रुपये
न्यू इन्डीया इंडस्ट्रीज लि.	1942	27 लाख रुपये
बूट्स कंपनी इंडिया लि.	1943	1.10 करोड़ रुपये
जॉफ्रीमॅन कंपनी लि.	1943	5 लाख रुपये
क्लोराइड इंडिया लि.	1946	2.11 करोड़ रुपये
ब्यूको वुल्फ इंडिया लि.	1947	39 लाख रुपये
बेकेलाईट हायलम लि.	1947	1 करोड़ रुपये
हिन्दुस्थान सीबा गायगी लि.	1947	4.57 करोड़ रुपये
सायनामिड इंडिया लि.	1947	1.39 करोड़ रुपये
कोटस् इंडिया लि.	1947	38 लाख रुपये
जर्मन रेमेंडीज लि.	1949	64 लाख रुपये
मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लि.	1951	3.35 करोड़ रुपये
ओटीस वलीवेटर कंपनी लि.	1953	72 लाख रुपये
कार्बोरेंडम युनीव्हर्सल लि.	1954	1.06 करोड़ रुपये
फेनर इंडिया लि.	1955	64 लाख रुपये
हेक्स्ट इंडिया लि.	1956	2.72 करोड़ रुपये
केबल कार्पोरेशन इंडिया	1956	3.40 करोड़ रुपये

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

इंग्लिश इलेक्ट्रीक कंपनी	1956	2.25 करोड़ रुपये
सीमेन्स इंडिया लि.	1956	2.40 करोड़ रुपये
पॉलीकेम लीमिटेड	1956	56 लाख रुपये
डॉ. बँक अँन्ड कंपनी लि.	1956	16 लाख रुपये
जॉन्सन अँन्ड जॉन्सन लि.	1957	24 लाख रुपये
कलर केम लि.	1957	1.25 करोड़ रुपये
बायर इंडिया लि.	1957	3.59 करोड़ रुपये
फूड स्पेशॅलिस्ट लि.	1958	4.51 करोड़ रुपये
डेव्हीर्चड ब्राउन ग्रिव्हज लि.	1959	36 लाख रुपये
ॲटलास कापको इंडिया लि.	1959	1.33 करोड़ रुपये
के. एस. बी. पंप्स लि.	1959	86 लाख रुपये
मॅथर अँड प्लँट लि.	1959	1.83 करोड़ रुपये
फिलिप्स कार्बन ब्लॅक लि.	1959	1.57 करोड़ रुपये
सँडविक एशिया लि.	1960	1.17 करोड़ रुपये
ऑडको इंडिया लि.	1961	12 लाख रुपये
किर्लोस्कर कमिन्स लि.	1961	50 लाख रुपये
आय. डी. एल. केमीकल्स लि.	1961	1.07 करोड़ रुपये
गेस्ट कीन विलियम्स लि.	1962	7.69 करोड़ रुपये
सुन्दरम क्लोटन लि.	1962	1.96 करोड़ रुपये
रिचर्डसन हिंदुस्थान लि.	1964	1.17 करोड़ रुपये
नीडल रोलर बेअरिंग कंपनी	1965	10 लाख रुपये
विडिया इंडिया लि.	1965	45 लाख रुपये
सेन्चूरी एन्का लि.	1965	2.97 करोड़ रुपये

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूँजी निवेश मात्र एक धोखा है। हिन्दुस्तान लीवर, कालगेट, सीबागाइगी जैसी सैकड़ों विदेशी कम्पनियों ने मात्र कुछ लाख रूपये से भारत में व्यापार शुरू किया। लाभ कमा-कमा कर बोनस शेयर के रूप में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी शेयर पूँजी कराड़ों रूपये में कर ली। अब ये कम्पनियाँ रॉयल्टी, शुद्ध लाभ और टेक्नीकल फीस के रूप में अरबों रूपये भारत से बाहर ले जा रही हैं। इस बात की गंभीरता का अहसास इसी से हो जाता है कि 1976-77 में जहाँ भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियाँ 121.54

करोड़ रूपये देश से बाहर ले गयीं, वहीं 1986-87 में यह राशि बढ़कर 494.6 करोड़ रूपये हो गयी। पिछले 11 वर्षों में ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैधानिक रूप से 3244.15 करोड़ रूपये भारत से बाहर ले जा चुकी हैं, जबकि अवैधानिक तरीके से ये कम्पनियाँ इससे कई गुनी अधिक राशि देश से बाहर ले जा चुकी हैं। 2006-2007 में विदेशी कम्पनियों ने लगभग 33000 करोड़ रू. भारत से विदेशों में वैधानिक तरीकों से भेज दिये। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारत में शेयर पूँजी लगभग 675 करोड़ रूपये मात्र है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ देश के खून-पसीने की कमाई विदेशी मुद्रा का निर्यात अपने मूल देशों को कर रही हैं। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पूँजी के नाम पर कैसा मकड़जाल इस देश पर फैलाया है, इसका अनुमान दो-तीन उदाहरणों से लगाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान लीवर ने भारत में सन् 1933 में जब व्यापार शुरू किया तब इसकी मूल कम्पनी यूनीलीवर ने मात्र 24 लाख रूपये लगाये। 1933 में प्रारम्भ हुयी इस कम्पनी ने ऐसा जाल बिछाया कि 1990 में इसकी मूल कम्पनी यूनीलीवर की शेयर पूँजी 47.59 करोड़ रूपये हो गयी। इसमें से 44.51 करोड़ रूपये की शेयर पूँजी बोनस के रूप में जुड़ी। 1975 से 1990 तक के बीच हिन्दुस्तान लीवर ने 80.18 करोड़ रूपये लाभांश के रूप में भारत से बाहर भेज दिये। यह रकम रायल्टी और तकनीकी शुल्क के अतिरिक्त है। यहाँ पर 2007 में कुछ कंपनियों के आंकडे दिये जा रहे है कि वह उनकी प्रारम्भिक पूंजी कितनी थी, ओर शुरू मुनाफा कितना था।

	कम्पनी	**वर्ष**	**प्रारंभिक पूंजी करोड**	**बिक्री करोड**	**लाभ करोड़**
1.	एच.सी.एल.	2007	217.75	14740.51	1925.47
2.	कोलगेट	2007	135.99	1385.38	231.71
3.	सीबा गायगी	2008	15.98	559.70	94.46
4.	फिलिप्स	2007	70.30	2890.60	190.30
5.	गुडईयर	2007	23.7	979.61	40.23
6.	बायर इण्डिया	2008	39.50	1250.82	56.63
7.	ग्लाक्सो इण्डिया	2007	84.70	1712.84	537.66
8.	ग्लाक्सो स्मीत्थलाइन कन्ज्युमर हेल्थकेअर	2007	42.06	1395.51	162.68
9.	अबॉट इंडिया	2007	14.47	636.00	68.43
10.	आय.टी.सी.	2008	378.86	21355.94	3120.10

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

इसी तरह कालगेट-पामोलिव कम्पनी ने सन् 1937 में मात्र 1.5 लाख रूपये से अपना कारोबार शुरू किया। 1989 के आते-आते अमरीकी कम्पनी कालगेट-पामोलिव की शेयर पूँजी बढ़कर 12.57 करोड़ रूपये हो गयी। इसमें 12.56 करोड़ रूपये की पूँजी बोनस शेयर के रूप में जुड़ी। कालगेट-पामोलिव कम्पनी 1977 से 1989 के बीच में 18.42 करोड रूपये लाभांश के रूप में भारत से अमरीका ले गयी।

स्विस कम्पनी सीबा गाइगी ने 1947 में 48.75 लाख रूपये से कारोबार शुरू किया। 1991 में इस कम्पनी की शेयर पूँजी बढ़कर 13.54 करोड़ रूपये हो गयी। इलैक्ट्रानिक उद्योग में लगी फिलिप्स कम्पनी ने 1956 में सिर्फ 10 लाख रूपये में अपना कारोबार शुरू किया, सन् 1974 में इस कम्पनी ने 10 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में भारत से होलैण्ड भेज दिया। रिजर्व बैंक की 1992 की रिपोर्ट के अनुसार 1987-88 में 326 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शेयर पूँजी 1445.23
करोड़ रूपये थी, इनमें 60 प्रतिशत हिस्सा भारतीय लोगों का हुआ था, 610 करोड़ रूपये बैंकों के थे और 50 करोड़ सरकार के थे।

सामान्यत: बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जितनी पूँजी लेकर आती है, उससे कई गुना अधिक पूँजी तो वे एक ही वर्ष में देश के बाहर भेज देती हैं। उदाहरण के लिये गुडईयर कम्पनी ने भारत में 1 करोड़ रूपये पूँजी का निवेश किया। यह पूँजी निवेश इस कम्पनी ने भारत में अपना कारोबार शुरू करने पर किया था। लेकिन 1989 में गुडईयर ने 7.33 करोड़ रूपया भारत से बाहर मुनाफे के रूप में भेज दिया। अर्थात् एक ही वर्ष में पूँजी निवेश का सात गुना देश से बाहर भेज दिया। इसी तरह बायर इंडिया का भारत में आरम्भिक पूँजी निवेश 8.29 करोड़ रूपये था, लेकिन 1989-90 में ही इस कम्पनी ने 13.3 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में भारत से बाहर भेज दिये। ग्लैक्सो इंडिया की भारत में चुकता पूँजी 2.88 करोड़ रूपये की है, लेकिन इस कम्पनी ने 1989-90 में 3.93 करोड़ रूपये मुनाफे के रूप में देश से बाहर भेज दिये। अमरीकी कम्पनी फाइजर ने, भारत में जब अपना कारोबार शुरू किया तो मात्र 5 लाख रूपये लगाये और कारोबार शुरू होने के पहले ही वर्ष में फाइजर ने 4.83 करोड़ रूपये भारत से अमरीका भेज दिया। इसी तरह अमरीकी कम्पनी एबट लेबोरेटरीज ने मात्र 1 लाख रूपये की पूँजी से कारोबार शुरू करके, अगले ही वर्ष में 23 लाख रूपये भारत से अमरीका भेज दिया। ग्रेशम एण्ड कविन कम्पनी अपनी चुकता पूँजी का 7.65 गुना मुनाफा हर साल विदेश ले जाती है। सिगरेट बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई.टी.सी. अपनी कुल चुकता पूँजी पर लगभग 11364 प्रतिशत मुनाफा कमा रही है। लगभग सभी अमरीकी

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी चुकता पूँजी का 860 प्रतिशत मुनाफा भारत से कमा रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मुनाफे, लाभांश, रॉयल्टी और तकनीकी फीस के रूप में कितना धन देश से बाहर ले जा रही है, इसकी जानकारी के लिये नीचे तालिका दी गयी है :-

कितना लूट कर ले जा रही हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

वर्ष	मुनाफे के रूप में (करोड़ रू.)	लाभांश के रूप में (करोड़ रू.)	रायल्टी के रूप में (करोड़ रू.)	तकनीकी फीस के रूप में (करोड़ रू.)
1965-66	13.50	19.40	2.95	6.98
1966-67	14.47	28.77	5.13	10.43
1967-68	15.95	32.70	4.32	14.68
1968-69	12.96	30.25	4.78	17.97
1969-70	12.72	31.14	5.80	13.05
1970-71	13.12	43.48	5.23	20.63
1971-72	09.94	38.87	5.86	13.90
1972-73	15.54	39.08	7.33	11.33
1973-74	21.91	37.51	6.21	14.08
1974-75	07.19	18.46	8.46	12.56
1975-76	20.36	24.84	10.49	25.66
1976-77	19.39	48.47	15.88	37.88
1977-78	10.13	68.01	19.50	28.14
1978-79	10.24	54.35	12.65	55.52
1979-80	14.37	50.92	9.53	43.97
1980-81	12.10	55.92	8.88	104.93
1981-82	12.16	58.92	15.99	270.70
1982-83	19.12	70.31	39.72	258.58
1983-84	20.00	62.11	27.60	314.89
1984-85	16.68	74.58	28.49	300.90
1985-86	11.80	75.20	23.50	367.90
1986-87	10.60	85.50	40.10	358.40

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रिपोर्ट 1989 और 2008

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

सन् 1978 में भारत में कुल विदेशी पूँजी का निवेश 1800 करोड़ रूपये था जो भारत में कुल पूँजी निवेश (नीजि तथा सरकारी क्षेत्रों में) का मात्र 8 प्रतिशत था। जबकि दूसरी ओर इसी वर्ष दो के 1929 करोड़ रूपये बाहर चला गया इन कम्पनियों के लाभ, रायल्टी, तकनीकी फीस, इत्यादी के रूप में।

नीचे दी गयी तालिका सन् 1981 में देश में विदेशी पूँजी निवेश तथा साथ ही साथ उसी वर्ष में देश से बाहर जाने वाली पूँजी का आंकड़ा दिया गया है :-

वर्ष	विदेशी पूँजी निवेश	भारत से बाहर गया धन
1981	108 करोड़ रूपये	114 करोड़ रूपये
1982	628 करोड़ रूपये	641 करोड़ रूपये
1983	618 करोड़ रूपये	590 करोड़ रूपये
1984	1130 करोड़ रूपये	1169 करोड़ रूपये
1985	1260 करोड़ रूपये	1181 करोड़ रूपये
1986	1066 करोड़ रूपये	1265 करोड़ रूपये
1987	1077 करोड़ रूपये	1193 करोड़ रूपये
1988	2397 करोड़ रूपये	2542 करोड़ रूपये
1989	3166 करोड़ रूपये	5235 करोड़ रूपये
1991 से 1995 तक	25,479 करोड़ रूपये	34240 करोड़ रूपये

ऊपर दिये गये आंकड़ो से एकदम स्पष्ट है कि वर्ष 1983 व 1985 को छोड़कर शेष वर्षो में देश को घाटा ही रहा है। जितना पूँजी निवेश हुआ, उससे कहीं अधिक धन देश से बाहर चला गया। अत: स्पष्ट है कि विदेशी पूँजी निवेश का सौदा देश के लिये घाटे का सौदा रहा।

वर्ष (Year)	एफ.डी.आय. नं. (F.D.I. No.)	राशी (करोड़) (Amount)
2005	526	192991
2004	1551	147814
2003	2574	97364
2002	3904	162184
2001	2339	160711

2000	(1991 से 2000 15483)	
1999	11	
1998	11	132692
1997	11	129898
1996	11	87522
1995	11	64854
1994	11	31122
1993	11	18620
1992	11	6912
1991	11	3535
1990	694	2372
1989	605	2143
1988	926	2020
1987	853	1936
1986	957	1853

Actual Inflow

वर्ष (Year)	रकम (Amount) करोड़
1991-1992	409
1992-1993	1094
1993-1994	2018
1994-1995	4312
1995-1996	6916
1996-1997	9654
1997-1998	13548
1998-1999	12343
1999-2000	10311
2000-2001	10368
2001-2002	18486
2002-2003	13711
2003-2004	11789
2004-2005	14653
2005-2006	24613

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

8.

भुगतान सन्तुलन और निर्यात का भ्रम

विदेशी कम्पनियों को देश में बुलाने के पीछे एक ताकतवर तर्क होता है कि भारतीय उत्पाद अपनी घटिया गुणवत्ता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पाता, अत: आधुनिक तकनीक से बेहतर उत्पादन करने से निर्यात में तेजी आयेगी और देश में भुगतान सन्तुलन की स्थिति अच्छी रहेगी अर्थात् निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विदेशी कम्पनियों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस तर्क का खोखलापन नीचे दी हुयी तालिका प्रदर्शित कर देती है :-

वर्ष	विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा
1938	4-5%
1950	2-2%
1955	1-5%
1960	1-2%
1965	1-00%
1970	0-7%
1975	0-5%
1980	0-1%
1990	0-05%
1991	0-045%
1992	0-042%
1993	0-04%
1994	0-38%

देश के निर्यात की घटती हुयी दर से अनुमान लगाया गया है कि सन् 1995 के समाप्त होने तक विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा मात्र 0.03% रह जायेगा।

निर्यात में लगातार घाटे से, देश एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है जो आतंकवाद से भी अधिक भयावह है क्योंकि इससे देश में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता तथा अराजकता का खतरा पैदा हो गया है। यह संकट विदेशी मुद्रा की तंगी अर्थात् भुगतान संतुलन (निर्यात में कमी तथा आयात में बढ़ोत्तरी) की प्रतिकूलता से उत्पन्न हुआ है। देश के धुरंधर अर्थशास्त्री एवं योजना शास्त्री पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी रणनीति को खोजने में लगे हुये हैं जिससे इसका सामना किया जा सके।

भुगतान संतुलन का संकट भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है। पिछले लगभग 60 वर्षों के विकास काल में भारत को कई बार इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह संकट सर्वप्रथम 1957 में पैदा हुआ था, जब भारत को अपने व्यापक औद्योगीकरण के लिये निर्यात से अधिक आयात करना पड़ा था।

सन् 1966 में ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पुन: उत्पन्न हुयी तो संकट पर काबू पाने के लिये तथा निर्यात बढ़ाने के बाहरी दबाव के चलते भारत ने अपनी मुद्रा का 57.5% अवमूल्यन कर दिया। बाद में 1970 के आरम्भ होने वाले दशक में पेट्रोलियम की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण भारत संकट में फंस गया। किसी तरह खाड़ी के देशों से प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गयी धनराशि से भारत इस संकट से बच गया।

परन्तु 1985 के बाद से स्थिति एकदम बदल गयी है। भारी व्यापार घाटों तथा विदेशी कर्जों ने देश की कमर तोड़ दी है। विदेशी मुद्रा का खजाना खाली हो गया है।

विदेशी कम्पनियों को लगातार व्यापारिक घाटों को पूरा करने के लिये बुलाया जा रहा है लेकिन व्यापार घाटे लगातार बढ़ रहे हैं। 1983-84 में 5,871 करोड़ रूपये का घाटा हुआ, जो 1985-86 में बढ़कर 9,586 करोड़ रूपये तक पहुँच गया। 1985-86 से 1987-88 तक औसतन व्यापार घाटा 9,412 करोड़ रूपये रहा। 1995 के अन्त तक व्यापार घाटा 7,500 करोड़ रूपये तक पहुँच जायेगा। सन 2008 तक व्यापार घाटा लगभग 1,25,000 करोड़ रू. तक हो चूका है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

इस घाटे का मूल कारण देश में अपनायी जाने वाली उदारीकरण की नीति है। तकनीकी को उन्नत बनाने के इरादे से अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को न्यौता दिया जा रहा है। कम्पनियों की संख्या देश में बढ़ रही है। और उसी अनुपात में आयात बढ़ रहा है जबकि निर्यात में लगातार कमी आ रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर पाने में असफल सिद्ध हो रही हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान ही 293 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी हैं। 2008 तक कोई भी विदेशी कम्पनी अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायी।

इन सबके बावजूद सरकार विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में, निर्यात बढ़ाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुली छूट दे रही है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 0.5% ही रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मार्च 1992 की रिपोर्ट के अनुसार 326 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 1987-88 में केवल 810.37 करोड़ रूपये का निर्यात किया, जबकि इस वर्ष में भारत का कुल निर्यात 15,674 करोड़ रूपये के लगभग था। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ निर्यात बढ़ाने के नाम पर आती हैं लेकिन इनकी नीयत भारतीय बाजार पर कब्जा करने की रहती है। "पॉलिटिकल इकॉनामी ऑफ इण्डिया" की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ रूपये से अधिक की चुकता पूँजी वाली 144 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 1986-87 में केवल 412.71 करोड़ रूपये का निर्यात किया जबकि इन कम्पनियों की कुल बिक्री 9,879.77 करोड़ रूपये थी। अर्थात् इन 144 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 1986-87 में अपनी कुल बिक्री का मात्र 4.18 प्रतिशत ही निर्यात किया। इसी रिपोर्ट के अनुसार 1985-86 में इन 144 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 8,997 करोड़ रूपये की कुल बिक्री की, लेकिन निर्यात मात्र 384.67 करोड़ रूपये का ही किया। अर्थात् कुल बिक्री का 4.23 प्रतिशत मात्र। सन 2008 तक भी स्थिति वही है। देश के कुल निर्यात में विदेशी कम्पनियों का निर्यात 5.6 प्रतिशत ही है।

सरकार ने विश्व बैंक और मुद्राकोष के दबाव में जुलाई 1991 में रूपये का लगभग 25 प्रतिशत अवमूल्यन किया। इसके लिये वित्तमंत्री का तर्क था कि देश का निर्यात और अधिक बढ़ाने के लिये अवमूल्यन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद 1990-91 के मुकाबले 1991-92 के निर्यात में 15 प्रतिशत की कमी आयी। जबकि इसके पहले के 5 वर्षों में निर्यात में 16.8 प्रतिशत औसतन बढ़ोत्तरी हुयी। इ. 5 वर्षो में निर्यात 9.7 अरब डालर से बढ़कर 18.1 अरब डालर तक हो गया। परन्तु 1991-92 में निर्यात घटकर 17.8 अरब डालर रह गया।

सन् 1988 बाद घाटे में और तेजी से वृद्धि हुयी है। औसतन भारत की निर्यात आया, आयात भुगतान का 60 प्रतिशत है।

वर्ष	निर्यात (करोड़ रू.)	निर्यात (करोड़ रू.)	घाटा (करोड़ रू.)
1979-80	6,418	9,143	2,725
1980-81	6,576	12,544	5,967
1981-82	7,766	13,887	6,121
1982-83	9,137	11,913	1,776
1983-84	10,169	16,039	5,871
1984-85	11,959	18,680	6,721
1985-86	11,578	21,164	9,586
1986-87	13,315	22,669	9,354
1987-88	16,396	25,633	9,296
1988-89	20,646	34,202	13,556
1989-90	28,234	41,173	10,640
1990-91	32,553	43,193	10,640
1991-92	44,042	47,851	3,806
1992-93	14,921	52,205	10,284
1993-94	55,824	57,649	1,825
1994-95	65,482	71,247	5,765
2003-04	296969	359108	
2004-05	375340	501065	
2005-06	456418	660409	
2006-07	451168	680941	
2007-08	552168	675580	

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

9.

कर्ज और आर्थिक सहायता की राजनीति

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई.एम.एफ), विश्व बैंक जैसी संस्थायें जब देशों को कर्जा देती हैं तो वह उन देशों के विकास के लिये नहीं होता है, बल्कि इस बात के लिये होता है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पनपने न दिया जाय। यह कर्जा इसलिये दिया जाता है कि उन देशों में आत्म निर्भरता न आने पाये और उन देशों की गरीबी कभी भी दूर न हो।

विश्व बैंक गरीब देशों को जो मदद देता है वह अमीर देशों से नहीं आती बल्कि अमीर देशों को मदद तथाकथित तीसरी दुनिया से जाती है। जाहिर है कि विकासशील और अविकसित देशों की मदद के नाम पर चलने वाले इस प्रवाह को रोकने में और उसे सचमुच विकासशील और अविकसित देशों की बेहतरी के लिये लगाने में विकसित देश कोई रूचि नहीं रखते। अगर उनकी रूचि है तो गरीब व अविकसित देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ पोषक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जोड़े रखने में। ताकि वे अपनी इस्तेमाल की हुई प्रौद्योगिकी और बेकार हुये संयंत्रों को इन देशों को बेच सकें और इस तरह ये अविकसित व गरीब देश प्रौद्योगिकी के स्तर पर हमेशा पिछड़े रहें और उनके कर्जदार भी बने रह सकें। इसलिये विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आदि संस्थाओं से जो भी मदद दी जाती है वह उन देशों को पिछड़ा रखने का एक साधन है।

विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आंकड़े बताते हैं कि अमीर देशों से गरीब देशों को मदद मिलने की बजाय 50 अरब डालर (2500 अरब रूपये) का कच्चा माल और उत्पादन उल्टे इन्हीं देशों को प्रतिवर्ष मुनाफे के तौर पर उपलब्ध हो जाते हैं। यानि ये अमीर देश हमारी मदद नहीं करते बल्कि हम ही

प्रकारान्तर से उनकी मदद करते आ रहे हैं। अगर हर साल मिलने वाली नयी सहायता की रकम घटा दी जाय, तो लगभग 40 अरब डालर (2000 अरब रूपये लगभग) है, तो भी 10 अरब डालर की रकम विकासशील और अविकसित देशों से इन विकसित अमीर देशों में जाती रहती है। यह है इन देशों की हमारे विकास के लिये मदद और यह है विकासशील देशों की सरकारों की विकास संबंधी अवधारणा।

अमीर देशों की दृष्टि से देखा जाय तो उनको कई स्तरों पर लाभ होता है - पहला यह कि विकासशील और अविकसित देश उनके द्वारा प्रयुक्त और बेकार प्रौद्योगिकी और संयंत्र लेने लायक हो जाते हैं, यानि जिस प्रौद्योगिकी और संयंत्रों से वे पहले ही लाभ उठा चुके हैं और जो अब उनके लिये बेकार हो गये हैं, उसे विकासशील या अविकसित देशों में ऊँची कीमत में पटकने का इंतजाम हो जाता है।

दूसरा लाभ यह है कि इस तरह से सहायता प्राप्त करने वाले देश प्रौद्योगिकी के मामले में तो पिछड़े रहते ही हैं, वे भारी कर्जदार भी बने रहते हैं और यह कर्जदारी साल-दर साल बढ़ती रहती है। इस तरह वे देश इन पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओ से जुड़े रहने को मजबूर बोझ ऊपर से लद जाता है। पश्चिमी देशों के इस दुष्चक्र में फंसकर इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होने की स्थिति में पहुँच जाती है।

तीसरा फायदा अमीर देशों को गुप्त पूँजी पलायन से मिलता है। तीसरी दुनिया के शासक वर्ग अपने कालेधन को चोरी-छिपे बाहर ले जाकर पश्चिमी बैंकों में जमा करते हैं और इस तरह पश्चिम के उद्योगों को बिना ब्याज की पूँजी उपलब्ध कराते हैं। ज्ञात रहे कि कालेधन पर ब्याज नहीं मिलता है, चोरी का धन जमा करने वाली बैंक केवल उस कालेधन की सुरक्षा की गारंटी देती है। पश्चिम की जो सम्पन्नता आज है वह उसी पूँजी के कारण है। अगर वह पूँजी मिलना बन्द हो जाये तो उसकी सम्पन्नता आधी रह जायेगी।

अमीर देशों के पास तीसरी दुनिया के देशों की कर्जदारी बढ़ाने का एक जरिया और भी है; और वह है गरीब देशों के कच्चे माल की कीमत विश्व बाजारों में गिरा देना। अमीर देश जब देखते हैं कि गरीब देशों की सम्पन्नता बढ़ रही है तो कच्चे माल की खरीद पर रोक लगा दी जाती है और आपूर्ति मांग के नियम के मुताबिक मांग कम होने पर चीजों के भाव हमेशा गिरते है। इस तरह कच्चा माल बेचने वाले इन देशों में गरीबी और बेरोजगारी फैलती है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

कर्जे का दुष्चक्र

विकास का जो ढाँचा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने देश को दिया है वह लगातार देश को कर्जे के जाल में फँसाता चला जा रहा है। कर्जदारी में वृद्धि के साथ ही सूद भुगतान भी बढ़ रहा है। 1984 में यह 1.5 अरब डालर (28. 5 अरब रूपये लगभग)था, जो 1990 के अन्त तक 4 अरब डालर (76 अरब रूपये लगभग) हो गया। सन् 1991 में यह सूद 4.6 अरब डालर (87.4 अरब रूपये लगभग) तक पहुँच गया।

जुलाई 1995 तक देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज 4,53,397 करोड़ रूपये हो चुकी है। सन 2008 तक यह विदेशी कर्जा 6,80,000 करोड़ रू. हो चुका है। इस कर्जे के ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 49,508 करोड़ रूपये चुकाने पड़ रहे हैं। इस विदेशी कर्जे में वह हिस्सा शामिल नहीं है जो सरकार द्वारा विदेशी सहायता और साफ्ट लोन के रूप में लिया जाता है। यदि इसे भी शामिल कर लिया जाय तो कुल कर्जा लगभग 6,91,511 करोड़ रूपये के बराबर बैठता है। इस समय भारत दुनिया में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। पिछले वर्ष तक भारत की स्थिति दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कर्जदार देश की थी। भारत से पहले मैक्सिको और ब्राजील देशों का नम्बर आता था, लेकिन 1995 में विदेशी कर्ज के मामले में भारत ने मैक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया है।

विदेशी कर्जे पर चुकाया जाने वाला ब्याज तथा सरकार द्वारा कम समय के लिये लिया गया कर्ज, यदि दोनों को मिला दिया जाय तो तस्वीर बहुत ही भयावह है। केन्द्र सरकार पर घरेलू कर्ज और देनदारियों में भी खूब बढ़ोत्तरी हो रही है। देनदारियाँ ऐसे कर्ज को कहते हैं, जिस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। 1980-81 में केन्द्र सरकार पर घरेलू कर्ज और घरेलू देनदारियाँ 48,451 करोड़ रूपये थी, जो 1990-91 में बढ़कर 2,83,033 करोड़ रूपये हो गयी। मार्च 95 तक ये 4,83,545 करोड़ रूपये के बराबर हो गयीं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार पर विदेशी देनदारियाँ 1980-81 में 11,298 करोड़ रूपये थीं जो 1990-91 में 3,21,525 करोड़ रूपये के बराबर हो गयीं। इसी तरह कुल देनदारियाँ (घरेलू कर्ज सहित), जो 1980-81 में 59,749 करोड़ रूपये थी, वह मार्च 1995 में 5,33,053 करोड़ रूपये हो गयी। इन देनदारियों में यदि विदेशी कर्ज को जोड दिया जाय तो स्थिति अत्यन्त ही भयावह दिखती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक विदेशी कर्ज तथा देनदारियों का आंकड़ा बैठता है। देश का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 48,00,000 करोड़ (सन 2008) रूपये के बराबर है, लेकिन विदेशी कर्ज ओर देनदारियाँ 18,00,000 करोड़ (सन 2008)। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विदेश कर्ज और देनदारियों पर ही निर्भर हो गयी है। विदेशी कर्ज और देनदारियों के दुष्चक्र में फंस कर लैटिन अमरीका, अफ्रीका और एशिया के कई देश बुरी तरह बरबाद हो चुके हैं। कई देशों की हालत तो ऐसी है कि वे यदि अपनी पूरी सम्पत्ति बचे भी दें तो भी विदेशी कर्जे को नहीं चुका सकता हैं। कई देशों के हालात ऐसे हो गये हैं कि उन्हें पुराने कर्ज चुकाने के लिये नया कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह कर्जे का फन्दा ऐसे देशों के गले में कसता ही जा रहा है।

इस समय स्थिति यह है कि देश की निर्यात से होने वाली आय का 50 प्रतिशत अंश प्रतिवर्ष सूद को चुकाने में खर्च हो जाता है। शेष 50 प्रतिशत निर्यात आय, प्रतिवर्ष होने वाले आयात का मात्र 42 प्रतिवर्ष ही पूरा कर पाती है। विकास की उल्टी दिशा के कारण देश कर्ज के दुष्चक्र में फंस गया है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

10.

उच्च विदेशी तकनीक का झूठ

विदेशी उच्च तकनीक को लाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यापार की खुली छूट दी जाती है। भारत में आने वाली सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशी उच्च तकनीक देने के समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। लेकिन वास्तव में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसे क्षेत्रों में व्यापार कर रही है, जहाँ विदेशी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। 80 के दशक में सरकार की ओर से एक नीति बनायी गयी थी। इस नीति के अनुसार 850 ऐसी वस्तुयें हैं, जिसके उत्पादन को लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जितनी भी विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं, वे सभी इन्हीं उत्पादों के व्यापार में लगी हुयी हैं। लघु उद्योगों के लिये आरक्षित उत्पादों के क्षेत्र में घुसपैठ से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उच्च विदेशी तकनीक लाने की बात एकदम झूठ साबित होती है। देश में व्यापार कर रही कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ के बारे में नीचे तालिका दी जा रही है कि ये कम्पनियाँ 'जीरो तकनीक' के क्षेत्र में व्यापार कर रही हैं अर्थात् ऐसे सामान बना-बेच रही हैं जिनमें विदेशी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। कुछ उदाहरण देखें :-

कम्पनी का नाम	क्या सामान बना/बेच रही हैं ?
बाटा इण्डिया	जूते, मोजे, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के थैले आदि।
बर्जर पेन्ट्स	पेन्ट्स, तरह-तरह के रंग आदि।
ब्रुक बाण्ड इण्डिया लि.	चाय, कॉफी, रसोई घर के मसाले आदि।
कैडबरी इण्डिया लि.	चॉकलेट, बिस्कुट, आईसक्रीम आदि।
कोलफैक्स लेबोरेटरी इ.	शेविंग क्रीम, आफ़्टर शेविंग लोशन आदि।
कालगेट-पामोलिव	टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ ब्रश, साबुन, शेविंग क्रीम
कार्न प्रोडक्ट्स इण्डिया	दही पाउडर, जैली, मक्के के दोन पैक करके बेचना आदि।
क्राम्पटन ग्रीव्ज	घरेलू पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि।
ड्यूफार-इन्टरफैन	सौंदर्य प्रसाधान के सामान, साबुन आदि।
एस.के.एफ. लि.	दर्द निवारक मलहम तथा स्प्रे आदि।
फिस्कर्स इण्डिया	कैंची, चाकू आदि।
फनस्कूल इण्डिया	बच्चों के खिलौने।
जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी	घरेलू पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट, बिजली मोटर आदि।
ज्यौफ्री मैनर्स	टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, साबुन आदि।
ग्लैक्सो इण्डिया	बेबी फूड, ग्लूकोज के पैक, दवाएं आदि।
गाडफ्रे फिलिप्स	सिगरेट, चाय आदि।
गुडलस नेरोलेक	तरह-तरह के पेन्ट्स।
ग्रामोफोन इण्डिया	रिकार्ड, कैसेट आदि।
गेस्टकीन विलियम	सेफ़्टी पिन, बटन, नट-बोल्ट आदि।
हिन्दुस्तान लीवर	साबुन, टुथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेन्ट आदि।
सीबा-गायगी	टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, क्रीम, टूथ ब्रश, दवाएं।
एच.एम.एम. लि.	दूध पाउडर, बालों की क्रीम, बिस्कुट, टॉफी आदि।
आई. सी. आई.	पेन्ट्स तथा रासायनिक रंग आदि।
इन्डिया फोटोग्राफिक कम्पनी	कैमरा, कैमरा-रील आदि।
इन्डियन स्वीइंग मशीन कम्पनी	सिलाई मशीन, रसोई घर केबरतन आदि।
इन्डो-मत्सुशिता कम्पनी	प्रेशर कुकर, घरेलू बरतन आदि।
ऑयन एक्सचेंज इण्डिया	वाटर फिल्टर्स
आई. टी. सी.	सिगरेट, होटल व्यवसाय, वनस्पति तेल आदि।
जे. एल. मॉरीसन	टूथपेस्ट, दूध की बोतल, फेस क्रीम।
जे. के. हेलन क्रूटिस	सौंदर्य प्रसाधन के सामान।
जॉनसन एण्ड जॉनसन	साबुन, टेल्कम पाउडर, सेनेटरी नेपकिन्स, बड्स।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

किसान प्रॉडक्ट लि.	जैम, स्क्कैश, बिस्कुट, चटनी आदि।
कोठारी जनरल फूड्स	कॉफी, साफ्रट ड्रिंक, पान मसाला आदि।
लखनपाल नेशनल	ड्राई सैल।
लिप्टन इण्डिया लि.	चाय, साफ्रट ड्रिंक, वनस्पति तेल।
मदुरा कोट्स	धागे (सिलाई के लिये)।
मेटल बाक्स	प्लास्टिक के बर्तन आदि।
बास्किन राबिन्स	आईसक्रीम
नेस्ले इण्डिया	साबुन, टेल्कम पाउडर, कोल्ड क्रीम
प्राक्टर एण्ड गैम्बिल	बाम, टॉफी, साबुन, चॉकलेट आदि।
रेकिट एण्ड कोलमैन	बूट पॉलिश, साबुन, डिटर्जेन्ट, लोशन आदि।
विमको लिमिटेड	माचिस (दियासलाई), नमक आदि।
कोका कोला	साफ्ट ड्रिंक
लोटस चॉकलेट्स	बच्चों की चॉकलेट, बिस्कुट आदि।
रिगले	चॉकलेट, टॉफी आदि।
रफेम इण्डिया	चॉकलेट, टॉफी, लैमनचूस
यार्डल	सौंदर्य प्रसाधन और साबुन
बाकारोज परफ्यूम्स	सुगंधित सेन्ट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन
लेबोरेटरीज गार्नियर	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन के सामान
रीबुक इण्डिया	जूते, चप्पल आदि।
जिलेट इण्डिया	सेफ्टी रेजर, ब्लेड आदि।
विल्टेक इण्डिया	सेफ्टी रेजर, ब्लेड आदि।
स्टीफेन केमीकल्स	डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन आदि।

विदेश से आयी टेक्नोलॉजी (?)

दुनिया के विकसित-अमीर देशों के द्वारा दी गयी टेक्नोलाजी के बदले प्रतिवर्ष लगभग 8500 करोड़ रूपया रायल्टी के रूप में हमारे देश से बाहर जा रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि इन विकसित देशों द्वारा हमारे देश को कौन सी टेक्नोलाजी दी गयी है ? किस देश ने किस प्रकार की टेक्नालोजी दी है, इसके कुछ उदाहरण :

टेक्नोलॉजी	कहाँ से आयी
नमक	स्विट्जरलैण्ड
बच्चों के कपड़े	नीदरलैण्ड
केले की चटनी	डेनमार्क
चाकलेट-टॉफी	ब्रिटेन
साफ्ट ड्रिंक	अमरीका
चीनी-मट्टी के बर्तन	जापान, इटली, स्वीडन
कांच का सामान	अमरीका, बेल्जियम
बाल प्वाइंट पेन व रिफिल	स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, जापान, अमरीका, फ्रांस
छाता	जापान, ताईवान
प्लास्टिक के बर्तन	ब्रिटेन
स्कूल बैग	ब्रिटेन
मोटरकार की सीट	जापान
गहने-जेवरात	कनाडा
सुई	स्विट्जरलैण्ड
प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे व अन्य सामान	ब्रिटेन, अमरीका
खिलौने बनाने के लिए	अमरीका, जापान, इटली, कोरिया, हांगकांग
स्पोर्ट्स कैप	कनाडा
च्यूइंगम और बबलगम	दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन
आलू-चिप्स	अमरीका
टमाटर की चटनी	बुल्गारिया, अमरीका
घरेलू चाकू	नीदरलैण्ड
प्लास्टिक के फूल	अमरीका
सौन्दर्य प्रसाधन	अमरीका, फ्रांस
गैस लाइटर	स्पेन
कैंची	फिनलैण्ड
फास्ट-फूड	नीदरलैण्ड, अमरीका, स्विट्जरलैण्ड
तकिया	फ्रांस
हैण्ड बैग	अमरीका
लिपिस्टिक	अमरीका
बालों के शैम्पू एवं आफ्टर	शेव लोशन, फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

माल देशी, मुहर विदेशी

कई बार ऐसा भी होता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ न तो पूँजी लाती है और न ही कोई उच्च तकनीक। होता यह है कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कुछ भारतीय कम्पनियों के साथ 'फ्रेंचाइज एग्रीमेन्ट' करती हैं या 'सब कान्ट्रेक्टिंग एग्रीमेन्ट' करती हैं। इसके तहत उत्पादन का काम तो वह भारतीय कम्पनी करती है लेकिन उत्पादित माल पर नाम बहुराष्ट्रीय कम्पनी का ही होता है। अर्थात् बाजार में बिकने वाले माल की उत्पादक कोई स्वदेशी कम्पनी है लेकिन माल विदेशी कम्पनी के नाम से बिकता है। पूँजी लगाये स्वदेशी कम्पनी, तकनीक इस्तेमाल करे स्वदेशी कम्पनी, उत्पादन कराये स्वदेशी कम्पनी, लेकिन माल बिके विदेशी कम्पनी के नाम पर। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का यह गोरखधंधा इस देश में खूब चल रहा है।

नीचे ऐसी कम्पनियों की सूची दी जा रही है जिन्होंने न तो पूंजी लगाई, न कोई टेक्नोलॉजी लाये हैं और न ही कोई फैक्टरी लगाई है लेकिन माल उनके नाम से बिक रहा है और करोड़ों रूपये देश से बाहर जा रहा है।

सामान का नाम	भारतीय उत्पादक	बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी
जूते	आगरा, कानपुर, कलकत्ता, अन्य स्थानों से मोचियों द्वारा ठेके पर	बाटा (इण्डिया) लि.
कोलगेट टूथ पाउडर	क्रिस्टल कॉस्मेटिक्स, हैदराबाद	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
चार्मिस लोशन	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
हेलो शैम्पू	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
पामोलिव शैम्पू	एम.जी.साहनी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
कोलगेट टूथपेस्ट	सन शाइन कॉस्मेटिक्स	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
कोलगेट ब्रश	अडवानी इण्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	कोलगेट-पामोलिव इण्डिया
आयोडेक्स (बर्न स्प्रे)	अक्रा पैक इंडिया	एस्केफ इण्डिया लि.
सिबाका टूथ पाउडर	कैन्ट लैब्स, बम्बई	हिन्दुस्तान सीबा-गायगी लि.
सिग्रल टूथ पेस्ट	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
लिरिल फ्रेशनेश टेल्क्म	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
क्लीनिक शैम्पू	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
सनसिल्क शैम्पू	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
फेयर एण्ड लवल क्रीम	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट्स	हिन्दुस्तान लीवर लि.
टियारा शैम्पू	फियोरा कॉस्मेटिक्स	जे.के. हेलन करटिस लि.
निविया आफ्टरशेवलोशन	कॉस्मोपैक सिल्वासा	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
निविया टेल्कम	केवन कॉस्मेटिक्स	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
निविया क्रीम	केवन कॉस्मेटिक्स	जे.एल.मॉरीसन एण्ड जॉन्स लि.
क्यूटीकुरा टेल्कम	नीनन प्रॉडक्टूस	म्यूलर इण्डिया लि.
पामेड वैसलीन	जे. बी. अडवानी एण्ड कं.	पाण्ड्स इण्डिया लि.
पाण्ड्स सण्डल टेल्कम	इण्टरनेशनल हेल्थ केयर प्रॉडक्ट	पाण्ड्स इण्डिया लि.

11.

घटते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी

आँखे मूंदकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से, जब हम बनी-बनायी तकनीक का आयात करते है तो हम दरअसल दूसरे देशों के इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों को काम मुहैया कराते हैं। अर्थात् अपने देश से विकसित देशों को रोजगार का निर्यात करते हैं। इस तकनीकी आयात की प्रक्रिया में भारतीय इंजीनियरों व तकनीकी विशेषज्ञों को जो अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता था और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते थे, वे एकदम समाप्त हो जाते हैं। इससे हमारे देश के इंजीनियर व तकनीकी विशेषज्ञ बेकार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी विकसित औद्योगिक देश को, जहाँ की कम्पनी होती है, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जब बनी बनायी तकनीक का आयात होता है तो भारतीय इंजीनियरों का कार्य सिर्फ तन्त्र को चालू रखने का होता है। सर्वविदित है कि कारखानों के रख-रखाव के लिये किसी बड़ी प्रतिभा की जरूरत नहीं होती है। जबकि तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान नयी विधियाँ विकसित करने में और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान द्वारा विकास करने में होता है। इस प्रकार जो इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ देश में काम में लगे हुये हैं, उनकी प्रतिभा का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है।

औद्योगिक देशों को एक और बड़ा लाभ उस बुद्धि शक्ति के आयात से मिलता है जो सुनहरे भविष्य की खोज में भारत जैसे देशों से उनके यहाँ जाती है। प्रौद्योगिकी विज्ञान तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में विशेष शिक्षा पाकर जो लोग देश को उसका कुछ भी लाभ दिये बगैर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि चले जाते हैं वे उन देशों को न सिर्फ आर्थिक व बौद्धिक लाभ पहुँचाते हैं बल्कि ऐतिहासिक लाभ भी।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

'सेंटर फार प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन' (नयी दिल्ली) के अध्ययन के मुताबिक प्रतिभा पलायन के कारण भारत को अब तक 130 अरब का नुकसान हो चुका है और अगर यह नहीं रूका तो शताब्दी के अंत तक 75 लाख से ज्यादा कुशल और प्रशिक्षित भारतीय विदेशों में काम कर रहे होंगे। फिलहाल 2.5 करोड़ भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार भारतीय इंजीनियर विदेशी में 32 प्रतिशत, डॉक्टर 28 प्रतिशत और वैज्ञानिक 5 प्रतिशत हैं।

जब एक डॉक्टर भारत को छोड़कर अमेरिका जाता है तो देश को 3.5 करोड़ रूपये का नुकसान होता है लेकिन वह अमरीका में 60 करोड़ यानि 20 गुना धन कमा कर उस देश की समृद्धि में भागीदार होता है। जबकि दूसरी ओर भारत एक विकासशील देश है जहाँ डॉक्टरों का अभाव है, जहाँ शहर में 5 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है तथा गाँव में 45 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है।

भारत से निकलने वाली प्रतिभाओं की एक बड़ी संख्या अमेरिका चली जाती है। 1957 से 1965 तक अमेरिका में भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा इंजीनियरों की संख्या सिर्फ 1000 थीं वही 1966 से 1968 तक वह संख्या 4000 हो गयी। 1977 तक भारत में 16,849 वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर अमेरिका चले गये।

उदार आर्थिक नीतियों के चलते देश में विदेशी अनुबंधों की बाढ़ आ गयी है। जुलाई 2008 तक देश में 45,000 से अधिक विदेशी अनुबंध चल रहे हैं। जिनके चलते गैर जरूरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में संगठित क्षेत्रों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ व निजी देशी कम्पनियाँ) में सबसे अधिक विकास हुआ है जबकि इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वृद्धि दर मात्र 1.5 प्रतिशत रही है। यानि संगठित क्षेत्र में पूँजी निवेश सबसे अधिक हुआ है लेकिन रोजगार के अवसर उस तुलना में पैदा नहीं हुये।

दूसरी ओर देश का लघु उद्योग का क्षेत्र है जिसमें सबसे कम पूँजी का निवेश किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के जितने भी रोजगार हैं उनमें से 80 प्रतिशत इन असंगठित लघु उद्योगों में है। लघु उद्योगों में 1986-87 में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 10.1 करोड़ थी जो वर्ष 1987-88 में बढ़कर 10.7 करोड़ तक पहुँच गयी भारत में 2008 के अन्त तक लघु उद्योगों एवं गृह उद्योगों की कुल संख्या 5.8 करोड़ थी। इसमें से 6,40,000 लाख लघु इकाईयाँ इन विशालकाय कम्पनियों के बाजार में एकाधिकार के चलते बीमार हो गयी हैं और बन्द होने के कगार पर हैं।

चूँकि इन विदेशी कम्पनियों ने लघु उद्योग में बनने वाले हर सामान को

बनाने के क्षेत्र में घुसपैठ कर रखी है, अतः लगभग 10 लाख 30 हजार अन्य छोटी इकाईयाँ इनके सामने प्रतिस्पर्धा में धीरे-धीरे चल रही है। हर वर्ष देश में बीमार इकाईयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिससे लाखों लोग बेराजगार होते जा रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 84 लाख नये बेराजगार लोग पैदा हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश छोटी इकाईयों के बन्द हो जाने की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त इन विदेशी कम्पनियों ने विकास के नाम पर सैकड़ों वर्षो से चल रहे हमारे देशी कारोबार, हुनर और हस्त शिल्प को रौंदा है, जिसमें लगे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छिन गयी है। आधुनिकीकरण की सबसे ज्यादा मार पड़ी है कारीगरों, दस्तकरीं व कुटीर उद्योगों पर। जूता उद्योग का आधुनिकीकरण होगा तो कोन मारा जायेगा? मोची। कपड़ा उद्योग का मशीनीकरण होगा तो कौन बरबाद होगा? बुनकर। वस्त्र उद्योग का रेडीमेडीकरण (सिले सिलाये कपड़े) होगा तो कौन नष्ट होगा? दर्जी मिठाई बनाने के क्षेत्र में जब विदेशी कम्पनियाँ घुसेंगी तो कौन हैरान होगा? हलवाई कुल्हड़ की जगह विदेशी कम्पनियाँ प्लास्टिक के गिलास बनाने लगेंगी तो कुम्हार किस काम का रह जायेगा? फलों का रस डिब्बा बन्द करके बेचने के लिये विदेशी कम्पनियाँ आयेंगी तो कौन समाप्त होगा? फलों का रस बेचने वाले लोग। पानी बेचने के लिये भी विदेशी कम्पनियाँ आयेंगी तो आगे कहा नहीं जा सकता, हम लोग स्वयं सोच लें।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार सन् 2008 के अन्त तक देश में कुल बेरोजगारी की संख्या लगभग 20 करोड़ है। यह संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अपना पंजीकरण सरकारी कार्यालयों में करवा लिया है। इसके अतिरिक्त देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी इस तरह का पंजीकरण करवाने के लिये प्रस्तुत नहीं होते हैं। गाँव के अधिकांश युवक तो पंजीकरण करवाते ही नहीं हैं। इस तरह के लोगों को मिलाकर अनुमानित बेरोजगारों की संख्या 40 करोड़ से अधिक है।

एडीडास (Adidas), प्यूमा (Puma), ड्यूक (Duke), नाईक (Nike), लाट्टो (Lotto), आदि विदेशी कम्पनियों के भारत में सिले हुये (रेडीमेड) कपड़ों के क्षेत्र में घुस जाने से देश भर के लाखों दर्जियों की आजीविका छिनेगी। भारत में बहुत तेजी से सिले हुये कपड़ों का बाजार बनता जा रहा है।

एडीडास, प्यूमा, लोट्टो द्वारा भारत के खेल सामान बनाने वाले क्षेत्र में घुस जाने से, जालन्धर के खेल सामान उत्पादन के लघु उद्योग में लगे हुये 60 हजार कुशल कारीगरों के अस्तित्व को खतरा है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा दिल्ली में लगे हुये लगभग 1 लाख 80

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

हजार अन्य कुशल श्रमिकों का रोजगार भी खतरे में पड़ जायेगा।

ब्रिटानिया के चलते उ.प्र., बिहार, व मध्यप्रदेश के बेकरी उद्योग में लगे 1 लाख 22 हजार से भी अधिक श्रमिकों की रोजी-रोटी चौपट होने के कगार पर है।

बाटा व प्लास्टिक के जूतों के चलने से देश के लाखों मोचियों को बरबाद किया है। विमको ने बरेली व शिवाकाशी के माचिस उद्योग में लगे हजारों श्रमिकों को चौपट कर दिया है। पेप्सी कोला के आने से खाद्य सामग्री और पेय बनाने वाली देश की 2525 छोटी इकाइयों में से अधिकांश बंद हो गयी। लगभग 3 लाख 75 हजार कुशल कारीगर श्रमिक अपनी आजीविका के लिए दर-दर भटक रहे है।

12.

दवाओं के नाम पर लूट

अपने आप को शिक्षित व जागरूक समझने वाले किसी भी व्यक्ति से अगर कहा जाय कि वह मात्र कुछ पैसे खर्च करके 'मूंगफली की खली' बाजार से खरीद कर रोज दूध में डालकर या वैसे ही खाये तो वह व्यक्ति पहले कहने वाले की मूर्खता पर हँसेगा और नाक-भौ सिकोड़ते हुये अन्त में कहने वाले को भाषण पिलाकर दुरूस्त कर देगा। फिर किसी दिन बाजार से जाकर 'बूस्ट', 'हॉर्लिक्स', 'कॉम्प्लान', 'प्रोटीनेक्स' खरीद कर लायेगा और हर रोज दूध में डालकर डॉक्टर के बताये अनुसार दिन में तीन बार या दो बार पियेगा और अपने आप को तरोताजा व शक्तिशाली महसूस करेगा। उसे शायद यह नहीं मालूम, कि 'बूस्ट', 'प्रोटीनेक्स', 'हॉर्लिक्स', या 'कॉम्प्लान' आदि को ताकत का टॉनिक समझ कर वह विशुद्ध 'मूंगफली की खली' बाजार से उठा लाया है। बस अन्तर इतना ही है कि यह मूंगफली की खली आकर्षक पैकिंग में अच्छी खुशबू के साथ बन्द है। यह कहानी हममें से किसी की भी हो सकती है। प्रचार तन्त्र द्वारा दिखाये गये आकर्षक विज्ञापनों से हमें खूब अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है।

टेलीविजन पर दिखाया जाता है कि कपिल देव या सचिन तेन्दुलकर बूस्ट खाते हैं और उसी के कारण उन्हें क्रिकेट खेलेने की शक्ति मिलती है। इसका सच क्या है ? दूसरी ओर टेनिस का विश्व चैम्पियन पीट सम्प्रास या बोरिस बेकर विश्व स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता जीतने के लिये केला खाते हैं। 9 जुलाई 1995 को लंदन में खेले गये विम्बलडन के फाइनल मैच में अन्तराल के समय पीट सम्प्रास केला खा रहा था। पीट सम्प्रास चिल्ला-चिल्ला कर यह नहीं कहता कि अच्छा टेनिस खेलने के लिये उसे बूस्ट या प्रोटीनेक्स या

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

कॉम्पलान जैसे टॉनिकों की जरूरत होती है ? वह तो केला खाकर ही अपनी ऊर्जा की पूर्ति करता है। 200 किमी. की रफ्तार वाली गेंद को वापस उससे भी अधिक रफ्तार से भेजना ओर वह भी एक छोटे से मैदान में किसी विशेष कोने पर कितना कठिन काम है ? कितनी शक्ति की आवश्यकता है ? यह सारी शक्ति तात्कालिक रूप से पीट सम्प्रास और बोरिस बेकर जैसे खिलाड़ी मात्र केला खाकर ही पूरी कर लेते है। तब सोचने और समझने की बात है कि केले में अधिक शक्ति है या बूस्ट में ?

एक अनुमान के अनुसार इस देश में प्रतिवर्ष लगभग 2950 करोड़ रूपये के 'हैल्थ टॉनिक' खाये जाते है। लगभग 150 करोड़ रूपये से भी अधिक के 'हैल्थ फूड्स' बेचे जाते हैं। जबकि सच यह है कि हमें इन हैल्थ टॉनिकों या हैल्थ फूड्स की कतई जरूरत नहीं है। हमारे देश की 77 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है। इस आबादी की आमदनी इतनी कम है कि वह रोज संतुलित भोजन भी नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति जो अपने और अपने परिवार के लिये संतुलित भोजन का प्रबंध भी नहीं कर सकता उसके लिए किसी डॉक्टर द्वारा हैल्थ टॉनिक लिखना सरासर अन्याय है। जो लोग संतुलित भोजन लेते है या ले सकते हैं, उन्हें तो फिर हैल्थ टॉनिक की कोई जरूरत ही नहीं। आजकल इस बात का फैंशन हो गया है कि जरूरत न होने पर भी दवाओं को खाया जाय। 'बीकोसूल' या 'बीकोजाइम' का कोई कैप्सूल या टेबलेट खाने के कुछ समय के बाद, यह देखा जाता है कि पेशाब (मूत्र) का रंग पीला हो गया। जो 'बीकोसूल' या 'बीकोजाइम' खाया गया, उसे आंतों ने पचाया और आवश्यकता नहीं होने के कारण गुर्दे द्वारा पेशाब के रूप में बारह निकाल दिया गया। पैसे भी खर्च हुये, आमाशय, लीवर तथा गुर्दे को काम भी अधिक करना पड़ा और फायदा हुआ कम्पनी को। अधिकतम 20 रूपये की लागत वाले इन तथाकथित शक्तिवर्धक टॉनिकों को 40 रूपये से लेकर 200 रूपये तक में बेचा जाता है। इन टॉनिकों को बेचने वाली कम्पनियों के मुनाफे का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

भारतीय दवा उद्योग के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। इस समय भारतीय दवा बाजार में लगभग 84,000 दवायें हैं जिनमें से मात्र 117 दवायें हमारे काम की हैं, बाकी 59,750 दवायें एकदम बेकार हैं जो किसी काम की नहीं है। इन बेकार दवाओं को बेचकर ये विदेशी कम्पनियाँ 100 प्रतिशत अथवा 200 प्रतिशत का मुनाफा नहीं बल्कि 20,000 प्रतिशत तक मुनाफा कमा रही हैं। एक-एक दवा बाजार में 40 से अधिक नामों

से बिक रही है। कम्पनी का मुनाफा उतने ही गुना बढ़ता चला जा रहा है। 90 प्रतिशत ऐसे टॉनिक बनाकर बेचे जा रहे हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। इतना ही नही उल्टे वे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इन निरर्थक और नुकसाान देह दवाइयों के जरियें हर वर्ष करोड़ें रूपये देश से बाहर जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, इसके अलावा ये विदेशी कम्पनियाँ हमारे देश में उन दवाओं को बनाकर बेच रही हैं जो इनके अपने देश में विषैले प्रभावों के कारण जहर घोषित की जा चुकी है। दुनिया के अन्य देशों में कई वर्ष पहले प्रतिबन्धित की गयी दवायें हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं। मौत का व्यापार करने वाली इन विदेशी कम्पनियों ने जब देखा कि विकसित देश एक-एक करके जानलेवा जहरीली दवाइयों को प्रतिबन्धित करते चले जा रहे हैं, तब उनकी निगाह गई गरीब व विकासशील देशों की ओर। चूँकि उत्पादन बन्द करना उनके लिये आत्मघाती कदम होता, इसलिये वे विकासशील देशों में उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुये तथाकथित विकास का वहम फैलाने में सफल हो गये और खतरनाक कारखाने एक पर एक करके खोलते गये। इन गरीब देशों में कानूनी बंदिशें कागजी शेर के सिवा कुछ नहीं होती। इस बात का इन कम्पनियों ने पूरा फायदा उठाया। दिसम्बर 1984 में भोपाल में जो कुछ हुआ वह इन विदेशी कम्पनियों की करतूत का एक हिस्सा ही है। ये कम्पनियाँ लगातार भारत या अन्य विकासशील देशों में ऐसे प्रयोग करती रहती हैं जिनसे भयंकर बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

40 से अधिक दवा बनाने वाली कम्पनियों ने वर्ष 2007-2008 में मनमाने तरीके के आवश्यक दवाओं के दाम बढ़ाकर करोड़ें रूपये का मुनाफा कमाया। उपलब्ध सरकारी आँकड़ें (दवा-रसायन मंत्रालय) के अनुसार 'ग्लैक्सो'(Glaxo) ने 137 करोड़ रूपये, 'हेक्सट'(Hoechst) ने करोड़ रूपये व 'साइनामाइड इण्डिया' (Cynamid India) ने 30 करोड़ रूपये का अवैधानिक मुनाफा कमाया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इससे उपभोक्ताओं के हितों को चोट पहुँचती है। अत: सरकार ने इन कम्पनियों से कमाये गये इस अवैधानिक मुनाफे को डी.पी.ई. (ड्रग प्राइस इक्वलाइजेशन) में जमा करने को कहा है।

दूसरी ओर 'आर्गेनाइजेशन आफॅ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इण्डिया' जो बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिनिधित्व करता है, ने धमकी दी है कि यदि भारत सरकार ने अपनी यह नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में 'रिफामपिसिन', 'पैरासीटामोल', 'क्लोरोफेनिकोल', 'इथामब्यूटोल' और 'टेट्रासाइक्लीन'

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

जैसी दवाये बाजार से गायब हो जायेंगी। जिससे कुष्ठ रोग, टाइफाइड व टी. बी. आदि रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक दवाओं का अभाव हो जायेगा। ध्यान रहे ऊपर दी गयी दवायें इन रोगों में काम आती हैं।

2008 में अवैधानिक रूप से दवाओं के दाम बढ़ाकर जिन 10 विदेशी कम्पनियों ने 289.2 करोड़ रूपये कमाये वे निम्न है :-

1. जानवेथ (John Wyeth)
2. फाईजर (Pfizer)
3. पार्क-डेविस (Park-Devis)
4. सैन्डोज (Sandoz)
5. एबॉट लेबोरेटरी (Abbot Laborateries)
6. मेरिन्ड (Merind)
7. इथनोर (Ethnor)
8. फुलफोर्ड (Fulford)
9. गिफान लेबोरेटरी (Giffon Laborateries)
10. निकोलस लेबोरेटरी (Nicholas Laborateries)

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारतीय कानूनों का खुला उल्लघंन करती हैं। भारत सरकार ने 15 जून 1988 को विशेष गजट नोटिफिकेशन एक्स 11018/1/88 डी.एम. एस.पी.एफ.ए. जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत इस्ट्रोजन-प्रोजेस्ट्रॉन और क्लोराम्फेनीकॉल-स्ट्रेप्टोमाइसीन के संयोग से बनने वाली दवाओं को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया। लेकिन आज भी ये दवायें बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं और इन्हें बेचने का काम बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कर रही हैं। इन घातक दवाओं के प्रयोग से महिलाओं पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। यदि गर्भवती महिला को ये खाने को दी जायें तो अपंग बच्चे पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। इन दवाओं से महिलाओं के मासिक धर्म में भी गड़बड़ी पैदा होती है। ये खतरनाक दवायें-ई.पी.फोर्ट, मैस्ट्रोजन फोर्ट, ओरसेक्रोन फोर्ट तथा ओगल्यूटिन आदि नामों से बाजार में बेची जा रही हैं।

इसी तरह 23 जुलाई 1983 में केन्द्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन एक्स 11014/2/83/ डी.सी.एम.एस. एण्ड पी.एफ.ए. के तहत 27 प्रकार की मूल दवाओं का व्यापार प्रतिबन्धित किया। लेकिन इनमें से कुछ दवायें आज भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बेची जा रही है। इन दवाओं को सिनेल्जेसिक, एक्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, डेकाबोलिन, हिस्टाप्रेड, पेरोकॉर्ट, पेरोब्रन आदि नामों से बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।

26 दिसम्बर 1990 तथा 1991 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों द्वारा 15 जेनरिक दवाओं को प्रतिबन्धित किया गया लेकिन आज भी ये दवायें - ब्यूटा प्राक्सीवान, कार्ब्यटाईल, बालाजेसिक, वेगानिन, फोर्टजेसिक, मोन्टोरिप, डिकेरिस, जेफराल, ल्यूपीहिस्ट, टिक्सीलिक्स, कोरेक्स, ट्रब्यूसाइन, ड्रीस्ट्रान आदि नामों से बाजार में बेची जा रही हैं। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भंयकर और जानलेवा घोटाला दवा उद्योग में चल रहा है।

13.

गुलाम होती खेती

आजकल देश में एक नारा बहुत जोर शोर से इन कम्पनियों द्वारा दिया जा रहा है कि 'खेती को उद्योग बनाओ'। यानि अब खेत को कारखाना बनाने की साजिश देश में चल रही है। अब ये कम्पनियाँ खेती के बल पर और अधिक मालामाल होने के सपने देख रही है। हमें याद होना चाहिए कि आज से लगभग 45 वर्ष पहले इन्ही कम्पनियों द्वारा देश में 'हरित क्रान्ति' का नारा दिया गया था। खेती की उन्नति और विकास के नाम पर चले इस नारे ने भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था और उसके साथ जुड़ी हुयी, समाज व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। उसी तरह अब खेती की उन्नति के नाम पर खेती को उद्योग का दर्जा देने की बात भारत के सामान्य और बहुसंख्यक किसानों के लिये देश की बची खुची कृषि व्यवस्था के लिये घातक सिद्ध होगी।

इन कम्पनियों द्वारा निरंतर यह प्रचारित किया जा रहा है कि खेती में विदेशी पूँजी निवेश की अत्यधिक जरूरत है। जिसके बिना अब खेती का विकास नहीं हो सकता है। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वास्तव में खेती स्वयं ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें से पूँजी का निर्माण होता है, हरित क्रान्ति की नारे बाजी से खेती को ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में ला दिया गया है कि खेती को पूँजी की जरूरत हो। आज खेती को उद्योग बनाने की बात कहकर इस बात की कोशिश की जा रही है कि खेती का रोजमर्रा का सामान्य काम भी बिना पूँजी के न चल सके।

खेती के लिये मुख्य तौर से दो ही चीजें आवश्यक होती हैं- एक किसान की मेहनत और पशु की मेहनत; दूसरे धरती, बीज, खाद, पानी आदि प्राकृतिक साधन। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार खेती एक सम्पूर्ण स्वावलंबी धंधा है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

किसान एक बीज बोता है लेकिन इस बीज में से जो भी दाने प्राप्त होते हैं, उनमें से हर एक दाना फिर बीज का काम करता है। इस प्रकार खेती एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लगाये हुये मूल का कई सौ गुना प्रतिफल मिलता है और जिसमें से बचत हो सकती है और बचत से ही पूँजी बनती है। कारखाना किसी भी चीज का हो, न तो उसमें चीज सचमुच पैदा होती है, न ही उसका गुणाकार होता है। कारखाने में केवल कच्चे माल का रूपांतर होता है, नया उत्पाद नहीं। कारखानों में जिस कच्चे माल से चीजें तैयार होती है, वह कच्चा माल भी अधिकतर खेती से ही प्राप्त होता है।

यह एक विडंबना ही है कि वास्तव में उत्पादन और पूँजी का निर्माण करने वाला किसान खाद, बीज और कीटनाशकों के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम बन गया है। अपनी मेहनत जो खुद उसके पास है तथा प्राकृतिक तत्व जो सब जगह उपलब्ध है इन दोनो के संयोग से खुद उत्पादन करने वाले किसान को आज भिखारी बनाकर रख दिया है इन विदेशी कम्पनियों ने। वास्तव में खेती कोई धंधा नहीं है वह जीवन जीने की प्रक्रिया है। जो खेती को धंधा बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है कि जीवन जीने की इस स्वावलंबी शैली को परावलंबी बना दिया जाये ताकि किसान का और खेती का शोषण किया जा सके। स्वावलंबी समाज में लोग अपनी मेहनत पर जीने वाले होते है, दूसरे के शोषण पर नहीं। खेती को उद्योग का दर्जा देने का मतलब है किसान को गुलाम बनाना। जब खेती को उद्योग की तरह चलाया जायेगा तो अधिक अन्न उपजाने के लिये बीज, खाद, कीटनाशक दवायें और पानी खरीदने के लिये किसान को और अधिक बाध्य कर दिया जायेगा। इसके लिये उसे कर्जा दिया जायेगा। फिर उस कर्ज की अदायगी में उसकी फसल उससे ले ली जायेगी। इस प्रकार वह पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व बाजार का बंधुआ मजदूर बन जायेगा। बड़े-बड़े फार्म बनेंगे तो जमीन छोटे किसानों से खरीदी जायेगी। इस तरह जमीन का मालिक धीरे-धीरे इन कम्पनियों की कृपा से जमीन पर काम करने वाला मजदूर बन जायेगा; फिर वह किसान नहीं रहेगा।

बीज का धंधा

पश्चिम के देशों ने विकास की अपनी अवधारण को दुनिया के कमजोर देशों पर लादा है। विकास एक नये प्रकार की गुलामी का मन्त्र बन गया है। हरित क्रान्ति इस प्रकार के विकास का एक बेशर्म उदाहरण हैं। इस तथाकथित क्रान्ति की शुरूआत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे बीज तैयार करने के साथ हुई जिनसे उपज बढ़ जाती है। अत: ऐसे संकर बीजों का उत्पादन इन विदेशी कम्पनियों ने करना शुरू किया। इस बीज की दो प्रमुख विशेषतायें होती हैं जो विदेशी कम्पनियों के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुयीं। पहली विशेषता यह है कि इस संकर बीज से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये भारी मात्र में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है। इन बीजों से पैदा होने वाली फसलों पर कीड़ा भी बहुत जल्दी और अधिक लगता है। जब अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता हुयी तो इन कंपनियों ने खाद व दवाओं को बनाकर बेचना शुरू किया और हरित क्रान्ति के दौरान अकूत मुनाफा बटोरा।

इस संकर बीज की दूसरी विशेषता यह है कि सिर्फ एक बार ही फलता है। इस बीज से जो दाने पकते हैं, वे पुन: बीज का काम नहीं देते है, इसलिये किसान को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। अत: जैसे-जैसे संकर बीज का चलन बढ़ता गया वैसे-वैसे बीज का बाजार विदेशी कम्पनियों के लिये पैदा होता गया। भारत में एक वर्ष में (सन् 2007 में) इन कम्पनियों ने जो बीज बिक्री किए हैं उसका आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है :-

विदेशी कम्पनी का नाम	बीज की बिक्री
1. पायोनियर (Pioneer)	169.26 करोड़ रुपये
2. शेल (Shell)	66.50 करोड़ रुपये
3. सैन्डोज (Soondoz) सीबा गायगी	54.91 करोड़ रुपये
4. फाइजर (Pfizer)	28.19 करोड़ रुपये
5. अपजोन (Upjohn)	38.00 करोड़ रुपये
6. आई. सी. आई. (I.C.I)	30.40 करोड़ रुपये
7. लीमाग्रेन (Limagrain)	32.49 करोड़ रुपये
8. सीबा-गायगी (Ciba Geiga)	28.88 करोड़ रुपये
9. लाफार्ज (Lofarge)	28.50 करोड़ रुपये
10. वोल्वो (Volvo)	26.60 करोड़ रुपये
11. आई. टी. सी. (I.T.C.)	303 करोड़ 57 लाख
12. मोनसॉन्टो (Monsanto)	217.84 करोड़ रूपये
13. सान्डोज (Sandoz)	22.56 करोड़ रूपये
14. सनजेन्टा इंडिया (Sungenta India)	232.28 करोड़ रूपये
15. आई.टी.सी.(Indian Tobaco Company)	51194 करोड़ रूपये

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

बीज के बाजार में इन विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी किसानों को लूट रही हैं। किस विदेशी कम्पनी के पास बीज बेचने वाली अपनी और कितनी कम्पनियाँ है, इसका आंकड़ा नीचे प्रस्तुत है :-

कम्पनी का नाम	नियन्त्रण में अन्य बीज कम्पनियों की संख्या
शेल (Shell)	68
सैन्डोज (Sandoz)	37
फाइजर (Pfizer)	34
सीबा-गायगी (Ciba Geiga)	26
अपजोन (Upjohn)	15
केमानोबेल (Kamanobel)	11
आक्सीडेंटल पेट्रोलियम(Occidently Petrolium)	10

इसके अतिरिक्त 16 सित्म्बर 1988 को सरकार द्वारा घोषित 'नयी बीज-नीति' के तहत कुछ और विशालकाय विदेशी कम्पनियों ने बीज का व्यापार शुरू कर दिया है। वे कम्पनियाँ निम्न है :-

1. कारगिल सीड कार्पोरेशन (Cargil Seeds Corporation)
2. पी. एच. आई. बायोजीन लिमिटेड (P. H. I. Biogene ltd.)
3. नेशनल आर्गेनिक लि. (National Org.ltd.)
4. बेजो शीतल सीड कम्पनी (Beio Sheetal Seed Company)
5. आई. टी. सी.(Indian Tobaco Company)

(सोया सीड़ 51194 करोड़ रू. - 2008)

6. हिन्दुस्तान लीवर (Hindustan Lever)

कीटनाशकों का कहर

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रायपुरा-जंगला गांव में 15 अप्रैल 1990 की रात को एक समारोह में विषाक्त भोजन खाने से 200 से अधिक लोग मारे गये। इस दर्दनाक हादसे के कारणों का सही-सही पता चला; जब पूरी जांच की गयी। जांच के बाद पाया गया कि लोगों की मोत अत्यन्तक घातक कीटनाशक पैरथियान और ई.एन.पी. के कारण हुयी। जिस गेहूं की बनी पूडियाँ इस भोज में खायी गयी उस गेहूं में ये दोनों कीटनाशक मिले हुये थे। उल्लेखनीय है कि इन दोनों कीटनाशकों पर सभी पश्चिमी देशों में रोक लगी हुयी है। ये दोनों कीटनाशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी प्रतिबन्धित हैं। मगर हमारे देश में

ये दोनों ही कीटनाशक इन विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाये जा रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में फंसकर यह माना गया कि खेती की उपज बढ़ाने के लिये यदि ढेरों तरह के जहरीले कीटनाशी रसायनों का भरपूर इस्तेमाल जारी नहीं रहा तो कीटाणु सारी फसल को चट कर जायेंगे और सारी मानवता भुखमरी की चपेट में आ जायेगी। इन कम्पनियों द्वारा प्रचारित विकास; किसी अन्य विकल्प को प्रकृति प्रेमियों व पर्यावरणवादियों का सुहाना सपना समझकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। मिट्टी की हिफाजत का परम्परागत देशी तौरतरीका, खरपतवार, घरेलू व कृषीय कूड़ा-कचरा और जानवरों के मल-मूत्र से बनी खाद, परस्पर मदद पहुँचाने वाली फसलों का बारी-बारी से बोया जाना यानी फसल-चक्र, यह सब विदेशी कम्पनियों, द्वारा विकसित तकनीक ने लील लिया है। मिट्टी, हवा, पानी और फसल के बीच जो प्राणवान, समन्वित और निरापद नाता था, वह बेमानी हो गया है। उसका स्थान ले लिया बेकस मिट्टी और जहरीले रासायनिक द्रव्यों ने।

'हरित क्रान्ति' के बाद खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गयी है। इसका नतीजा यह है कि जो अनाज जीवनदायी माना जाता है, वही उर्वरकों व कीटनाशकों के कारण गुणवत्ता में निम्न स्तर का होकर अस्वास्थ्यकर और जानलेवा तक होने लगा है। 'हरित क्रान्ति' के दौरान अनाज उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि असल में एक मिथक है, उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सन् 1947 के बाद के पहले दशक में जहाँ अन्न उत्पादन में 3.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुयी। वहीं अगले दशक में अर्थात् 60 के दशक में यह दर मात्र 2.25% प्रतिशत रही। यह दर दो दशकों तक जारी रही। एकमात्र गेहूं ही ऐसा अनाज है जिसका उत्पादन 4.5% वार्षिक दर से बढ़कर 7.62% हो गयी लेकिन दूसरी ओर का सच यह है कि बाकी अन्य सभी अनाजों की वृद्धि दर लगातार घटती गयी। इन आँकड़ों से हरित क्रान्ति के भोजन पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। हरित क्रान्ति के दौरान गेहूं का उत्पादन क्षेत्र बढ़ता गया और मोटे अनाजों, दालों, तिलहन आदि का उत्पादन क्षेत्र घटता गया। इस कारण भोजन में प्रोटीन की मात्र घटती गयी। नये अनाजों का असर पशुओं को भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा उपज देने वाली फसलों का भूसा पोषक तत्वों के मामले में कमजोर होता है।

आज अनाज, फल, सब्जियाँ, दलहन, तिलहन, दूध और मांस-मछली तक सभी में विषाक्त तत्वों की भरमार है जो एक धीमी मौत की ओर हमें

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

धकेल रही है। इसके बावजूद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल न केवल जारी है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। आँकडों पर नजर डालें तो विशेषज्ञों का कहना है कि सन् 1960 से 1980 के दोरान भारत में कीटनाशकों की खपत में 20 गुना इजाफा हुआ है। इस दौरान कीटनाशकों के उत्पादन में 14% की बढ़ोत्तरी हुयी है और इनका आयात भी इस बीच 7 गुना बढ़ा।

सन् 1989 से 1990 के बीच में कीटनाशकों की खपत 1 लाख 20 हजार टन हुयी। इस का मात्र दो तिहाई भाग खेती में इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के अनुसार पिछले 20 वर्षो में कीटनाशकों के इस्तेमाल से 10% फसल को बचा लिया गया। लेकिन जिस अनुपात में इन कीटनाशकों का जहर भोजन के जरिये देशवासियों के शरीर में पहुँचा है और उससे जो हानि हुयी व हो रही है, उसे देखते हुये 10% फसल को बरबाद होने से बचाने की उपलब्धि बहुत महंगी है। जन और धन की इस व्यापक हानि के सामने 10% फसल की बरबादी का जोखिम सस्ता ही ठहरेगा।

इन कीटनाशकों के कारण देश में कितने लोग काल-कवलित हुये हैं, इसके सही-सही आँकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। कीटनाशक मिले भोजन व असावधानीवश कीटनाशकों के सम्पर्क में आने के कारण जहाँ हजारों लोग मौत के मुंह में समाये हैं वहीं इन कीटनाशकों से पैदा होने वाली बीमारियाँ भी आम होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है जहाँ कीटनाशक हादसे ज्यादा और हर साल होते हैं। इन कीटनाशकों से जोड़कर उनकी शिनाख्त करना बहुत लंबी प्रक्रिया है।

कीटनाशकों से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि भारत जैसे विकासशील देश में इस्तेमाल होने वाले 70% कीटनाशक ऐसे हैं जिन पर विकसित देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डी.डी.टी. हमारे देशों में एक आम कीटनाशक है पर अन्य अनेक देशों में यह प्रतिबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जमीन, वनस्पति और शरीर पर इसका बहुत लंबे समय तक घातक असर बना रहता हैं मगर अपने देश में कृषि क्षेत्रों में इसकी खपत 3500 टन प्रतिवर्ष तथा मलेरिया उन्मूलन आदि कार्यक्रमों में 4000 टन प्रतिवर्ष है। बी.एच.सी. (बेंजीन हेक्साक्लोराइड), मिथाइल पैराथियान, हैप्टाक्लोर, डाई ब्रोमोक्लोरो प्रोपेन, एजेंट आरेंज, फास्वेल, डेल्ड्रिन, क्लोरेडेन, बूटाक्लोर जैसे कीटनाशक जो पश्चिमी देशों सहित दुनिया के कई अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, जिनका बेचना उन देशों में गंभीर अपराध घोषित हो चुका है, उन्हीं कीटनाशकों के घातक असर का अहसास करने के लिये इन 'हरित क्रान्ति' के झंडाबरदारों को कितनी भोपाल त्रासदियों का इंतजार है।

14.

आधुनिक विकास या प्रकृति विनाश

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कारगुजारियों और उसके फलस्वरूप विकसित विकास-प्रक्रिया का सबसे भयावह नतीजा प्रकृति के विनाश के रूप में हुआ है। पर्यावरण की बरबादी का मुख्य कारण है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उत्पादन शैली, जिसके चलते पश्चिम के देश अमीर हुये हैं। लेकिन अब यह संकट उन देशों पर सबसे अधिक मंडरा रहा है जहां से आधुनिक विकास प्रक्रिया की शुरूआत हुयी थी। पश्चिम के देशों में जितनी उपभोग की वस्तुयें बन रही हैं, उतनी ही अधिक उपभोक्ताओं की हवस बढ़ रही है। नतीजा उस कचरे के रूप में सामने है जो हमारी पृथ्वी को दिन-दूनी रात-चौगुनी गति से प्रदूषित करता जा रहा है जो अपने आने वाले दिनों में कई तटीय शहरों को विश्व के नक्शे से समाप्त कर देगा।

वर्तमान में कार्बन डाईआक्साइड पर्यावरण के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। उद्योगों के इस अंधे युग के आरंभ होने से पहले कार्बन डाईआक्साइड वातावरण में एक निश्चित अनुपात में रहती थी। एकसर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक क्रान्ति से पहले वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड प्रति 10 लाख अंशों में 280 अंश थी। आज इसमें 25 प्रतिशत बढोत्तरी हो चुकी है और सन् 2075 तक गैस की मात्र दुगुनी हो जायेगी। अगर इस बात को दुनिया भर के देशों के जंगलों के विनाश से जोड़ दिया जाए, तो यह अंदाज सामने आता है कि कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा वायुमंडल में आज से मात्र 20 वर्ष बाद दुगुनी हो जायेगी। इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गये हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। पिछले 110 साल की तुलना में इस दशक के पहले 8 सालों में ही 4 साल सबसे गर्म साल थे। 2008 के पहले 7 महिनों ने तो एक शताब्दी का रिकार्ड तोड़ दिया,

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

ये 7 महिने इतने अधिक गर्म थे। 23 जून 2008 दोपहर में जब अमरीकी शहरों में 38 डिग्री सेल्यिस से ज्यादा गर्मी थी, हजारों किलोमीटर उपजाऊ भूमि पर पहली बार भयंकर सूखा पड़ा था और जो अंधड़ चल रहे थे वैसे इस शताब्दी में कभी देखने को नहीं मिले।

सन् 1950 से लेकर 2008 के बीच किस देश ने वातावरण में कितनी कार्बन डाईआक्साइड गैस छोड़ी इसका आँकड़ा नीचे दिया जा रहा है।

देश का नाम	कार्बन डाईआक्साइड की मात्र
उत्तरी अमेरिका	80.2 अरब टन
पूर्वी यूरोप के देश	62.9 अरब टन
पश्चिमी यूरोप के देश	50.1 अरब टन
एशिया महाद्वीप के सभी देश	18.3 अरब टन
प्रशांत क्षेत्र के सभी देश	14.2 अरब टन
अफ्रीका के देश	28.23 अरब टन

वैज्ञानिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव ने पृथ्वी की जलवायु को बदलना शुरू कर दिया है। 'ग्रीन हाउस' ऐसे विशाल कमरे होते हैं जहाँ खास किस्म के पौधे उगाये जाते हैं, विकास के तथाकथित ढाँचे के अन्तर्गत चलने वाले उद्योगों से कार्बन डाईआक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड, ओजेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन तथा कई अन्य गैसें वायु मंडल के निचले हिस्से में जमा हो जाती हैं। जिसके कारण पृथ्वी की गरमी को ये गैसे ऊपर जाने से रोकती हैं जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ताकि पौधों पर बदलते हुये मौसम का असर न पड़े। इन कमरों में अनुकूल मौसम बनाया जाता है। शीशे की छतें इन कमरों में लगी रहती हैं जिनसे धूप तो मिलती ही है लेकिन अन्दर गर्मी एक निश्चिम नाप से ज्यादा नहीं होती है। इन ग्रीन हाऊस का सबसे बड़ा असर यह होता है कि जो कार्बन डाईआक्साइड गैस बनती है वह कमरे से बाहर नहीं जाती जिससे तापमान बढ़ जाता है क्योंकि कार्बन डाईआक्साइड में गर्मी सोखने की विलक्षण क्षमता है, इसी वजह से ग्रीन हाऊस ठंडे मौसम में भी गर्म रहता है। अत: पृथ्वी पर भी यही प्रक्रिया दोहरायी जाती है कि कार्बन डाईआक्साइड या ऐसी ही अन्य गैसें गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं तो इसे वैज्ञानिकों ने 'ग्रीन हाउस प्रभाव' का भोला सा नाम दिया है।

'ग्रीन हाउस प्रभाव' के कारण पृथ्वी की जलवायु का ताप स्थायी रूप से कुछ डिग्री बढ़ जाने से प्रलय का कहर ढ़ा सकता है। इसके कारण मौसम बदल सकता है, उपजाऊ क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है, रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो सकती है, पर्वतों पर पिघलते हुये हिमनद समुद्र की सतह को दो मीटर तक ऊँची कर सकते हैं। जिसके कारण समुद्र तटीय शहर बम्बई, कलकत्ता, लक्षद्वीप आदि जलप्लावित होकर विलुप्त हो जायेंगे।

कार्बन डाईआक्साइड के अलावा एक खतरनाक गैस होती है क्लोरो-फ्लोरो कार्बन इस गैस का उपयोग ये कम्पनियाँ मुख्यत: रिहायशी चीजों के उत्पादन जैसे रेफ्रीजरेटर, फोटोकापियर, वातानुकूलित यन्त्र, एयरोसोल स्प्रे आदि में करती है।

आज प्रदूषण सम्बन्धी तकनीक के खिलाफ शिकायत की जा रही है, वह इन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने गरीब देशों को बेची है। अब ये कम्पनियाँ दार्शनिक दलीलें देकर विकल्प-तकनीक को इन देशों को देने से इन्कार कर रही हैं। ताकि ये देश पर्यावरण के संकट को झेलते रहें। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि पर्यावरण के संकट भौगोलिक सीमाओं का आदर नहीं करते हैं। भस्मासुर की तरह वे भी इन संकटों की चपेट में आ जायेंगे।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

15.

संस्कृति पर हमला

क्या करूँ ? "इनकी साँस में बदबू है।" कहकर एक नयी नवेली पत्नी उदास हो जाती है। फिर उसकी एक सहेली उसे डाक्टर के पास ले जाती है। डाक्टर सलाह देता है कि "यदि साँस की बदबू से छुटकारा पाना है तो 'कॉलगेट का सुरक्षा चक्र' अपनाइये।"

इसी तरह से 'क्लोज-अप फार क्लोजेज अस'। अर्थात् क्लोज-अप के इस्तेमाल से ही पति-पत्नी नजदीक आ सकते हैं। सवाल यह उठता है कि "क्या पति-पत्नि का रिश्ता एक चार-पाँच रूपल्ली वाली कोलगेट या क्लोज अप के पेस्ट की ट्यूब पर टिका हुआ है?" अगर आप "माल्टोवा माम" नहीं हैं तो पता नहीं आप अपने बच्चे को प्यार करती भी हैं या नहीं।

"आई एम ए काम्प्लान बॉय।"

"आई एम ए काम्प्लान गर्ल" यानि लड़के या लड़की को पैदा करने के लिये माँ-बाप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे या तो काम्प्लान के लड़के हैं या फिर कम्प्लान की लड़की।

इसी तरह बालों को काला बनाने तथा गिरने से बचाने के लिये कई तरह के हेयर डाई, तेल तथा दवाओं के विज्ञापन आते हैं। जबकि सच यह है कि अभी तक बालों को गिरने या सफेद होने से रोकने का कोई उपचार नहीं निकला है। लेकिन हर रोज ऐसे विज्ञापन टी.वी. पर आते रहते हैं जो लोगों के मन में सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं पैदा करते। यही बात दंत मंजन पर भी लागू होती है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी मंजन नहीं है जो दातों की बीमारियों को दूर कर सके या फिर दांतों को रोग लगने से बचाये। फिर भी टी. वी. पर या पत्र-पत्रिकाओं में जिस तरह के चमकते हुये दांतों को दिखाया जाता

है, वह किसी खास कम्पनी के मंजन के चमत्कार के रूप में होता है। एक के बाद एक सभी दांतों के खराब हो जाने पर भी लोग उपचार की दृष्टि से मंजनों की निरर्थकता को देख नहीं पाते।

किसी विशेष कम्पनी की साड़ी में सजी हुयी सुन्दर औरत, सूट में सजा हुआ सुन्दर नौजवान, कोका या पेप्सी की बोतल लिये समुद्र तट के रमणीक माहौल में खड़े सुन्दर स्त्री-पुरूष, विशेष कम्पनी के स्वीमिंग सूट में समुद्र तट पर क्रीड़ा करती हुयी बालायें - ये सब चटकीले-भड़कीले विज्ञापन ऐसा मानसिक माहौल तैयार करते है कि लोग विज्ञापन मॉडलों की सुन्दरता का राज विभिन्न परिधानों और कोका-पेप्सी में देखने लगते हैं। बड़ी तोंद वाले लालाजी और दो क्विंटल वजन वाली सेठानी भी इन कम्पनियों का सूट या बाथिंग सूट पहनकर अपने को हीरो-हीरोइन समझने लगते हैं। इस तरह सुन्दरता का अर्थ खास कम्पनी के परिधानों और सजावट में निहित होने लगता है। जबकि सुन्दरता किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वभाव से आती है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सफलता उनके द्वारा की जाने वाली धुआंधार विज्ञापन बाजी में निहित है। प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये ये कम्पनियाँ विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। वर्ष 2007-2008 में कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विज्ञापन बाजी पर किये गये खर्च के आँकड़े नीचे दिये जा रहे है।

	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	विज्ञापन पर खर्च करोड़ रूपये (1993-94)	(2007-08)
1	हिन्दुस्तान लीवर	90.00	1422.90
2	आई.टी.सी.	47.85	427.83
3	ब्रुक बाण्ड इण्डिया	47.57	N.A.
4	कालगेट-पामोलिव	43.05	256.51
5	नेस्ले	32.35	172.2
6	गाडफ्रे फिलिप्स	32.45	137.94
7	गोदरेज-जनरल इलैक्ट्रिक	31.60	1.49
8	प्रॉक्टर एण्ड गैम्बिल	29.54	68.84
9	फिलिप्स	22.31	93.80
10	हरबर्ट सन्स	21.88	66.08
11	वी. एस. टी. इन्डस्ट्रीज	17.51	14.05
12	ग्लैक्सो	15.05	217.46

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

13	कैडबिरी	14.53	157.44
14	ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज	14.23	179.78
15	रेकिट एण्ड कोलमैन	12.52	207.85
16	बी. पी. एल	14.47	0.57

इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापनों ने एक खास किस्म की 'स्टेटस प्राब्लम' को जन्म दिया है। अब रोटी, कपड़ा और मकान वाली विचारधारा तो समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह ले ली है नये-नये चिप्स, कुकीज, रैंगलर जीन्स, वॉल पेपर, आधुनिक टाइल्स आदि ने। भले ही श्रीमती जी दिन भर पड़ी सोती रहें, पर वैक्यूम क्लीनर न होने की वजह से उन्हें वक्त ही नहीं मिलता खाना बनाने का। या फूड प्रोसेसर जब नहीं होगा तो खाना बनाने में देर तो लगेगी ही, इसमें उनकी क्या गलती है। इन सबका परिणाम होता है अतार्किक एवं अनावश्यक व्यय, जो कि धीरे-धीर आपको तार्किक एवं आवश्यक लगने लगता है। 'स्टेटस सिंबल' पहले से ऊँचा होना रहता है लेकिन वेतन उस अनुपात में बढ़ता नहीं, नतीजा होता है व्यक्ति के अंदर एक द्वन्द्व प्रारम्भ होता है, जिसमें अधिकांशत: पलड़ा विज्ञापनों का भारी रहता है। इस तरह एक ईमानदार व्यक्ति के भ्रष्टाचारी बनने की कहानी शुरू होती है यानि विज्ञापनों का रिश्ता भ्रष्टाचार से भी है।

विज्ञापनों में कभी भी वस्तु को गुणवत्ता के आधार पर बेचने की कोशिश नहीं की जाती है। ये विज्ञापन तो मध्यम वर्ग के ग्लैमर को भुनाने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञापन व्यक्ति में एक हीन भावना पैदा करते हैं। अधिकांशत: होता यह है कि विज्ञापित वस्तु होती मध्यमवर्ग के इस्तेमाल की है पर विज्ञापन में दिखाया जाता है, विशुद्ध रईसाना पांच सितारों वाली जीवन शैली। मध्यम वर्ग की एक कमजोरी होती है कि उसमें उच्च वर्गीय जीवन के प्रति एक विशेष किस्म की जिज्ञासा तथा वैसा जीवन जीने की दमित इच्छा होती है। विज्ञापन भयंकर सिद्ध होते हैं। एक आम आदमी चाहे जितनी भी विलासिता की वस्तुयें एकत्रित कर ले पर वह कभी भी उस किस्म की जीवन शैली को वहन नहीं कर सकता जैसी कि उसे विज्ञापन में दिखायी जाती है। इसका परिणाम होता है एक भीषण हीन भावना का जन्म, जो बढ़ती जाती है तथा एक सीमा के आगे जाने पर वैयक्तिक विघटन का करण बन जाती है।

विज्ञापन के इस स्वप्न संसार से जो विसंगतियाँ अल्प आय और मध्यम आय वर्ग के परिवारों में पनप रही हैं उनका सीधा परिणाम है कुंठा का जन्म।

पाश्चात्य शैली के उपभोक्तावाद का यह हमला हमारे सारे नैतिक मूल्यों को नष्ट करता जा रहा है। विज्ञापन का यह जादुई संसार हमें रूमानी दुनिया में ले जाता है। बार-बार का दोहराव हमारे मन में उस वस्तु विशेष को पाने की लालसा पैदा कर देता है। फिर हमारा कोमल मन नैतिकता से परे धन संग्रह की ओर मुड़ जाता है। और प्रारम्भ हो जाती है एक अनवरत तृष्णा की दौड़ जिसका कहीं अंत नहीं है। इसी का फायदा अब ये कम्पनियाँ उठा रही हैं उपभोक्ताओं को ऋण मुहैया कराके। ये प्रलोभन देकर उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींच रही हैं। इनका निशाना है सम्पन्न मध्यमवर्ग जिसकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, यह अमरिका की कुल आबादी के बराबर बैठता है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन शैली को जीने, की लालसा पालने वाला यह वर्ग संवेदनहीन हो जाता है, जो किसी बदलाव के काम करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। आधुनिक प्रचार माध्यमों और समाज के विशिष्ट सुविधाभोगी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हमारे ऊपर विकृत उपभोक्तावादी 'फेंकू संस्कृति' लाद रही हैं। उनकी विज्ञापन बाजी से हमारा मानसिक दिवालियापन बढ़ रहा है। सारा का सारा उत्पादन मात्र 27 करोड़ लोगों के लिये हो रहा है।

अब तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने मनोरंजन परोसने के नाम पर अपने टेलीविजन नेटवर्क को शुरू कर दिया है। सी.एन.एन., स्टार, ए.टी.एन, एम.टी.वी. , एल.टी.वी., यू.टी.वी. आदि अनेकों बहुराष्ट्रीय टेलीविजन कम्पनियों का जाल पूरे देश में फैल गया है। मनोरंजन के नाम पर सैकड़ों चैनल देश में चल रहे हैं। इन चैनलों पर दिखाये जाने वाले सीरियल, फिल्में तथा अन्य कार्यक्रम हमारे समाज को सांस्कृतिक रूप से खोखला बना रहे हैं। चार दर्जन से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन विदेशी टी.वी. चैनलों के प्रमुख समय को खरीद लिया है। सीरियल तथा कार्यक्रमों में क्या संस्कृति दिखायी जायेगी, इसका फैसला बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पैसा तय करता है। यह इस देश में पहली बार हो रहा है जब सीरियल तथा अन्य कार्यक्रम कलाकर्मियों और रचनाकारों की कल्पना या भावना से नहीं बन रहे हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरों के निर्देशों पर बन रहे हैं। इस नये सांस्कृतिक उद्योग का सच यही है।

आज हमारी संस्कृति एक झटके में ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चली गयी है। विदेशी चैनलों के कार्यक्रमों में एक समूची नई किस्म की उत्तेजक और भौंडी जीवन शैली दिखायी जा रही है। इसे देखकर दीनहीन, थके-हारे और निन्याबे बार असफल रहने वाले लोगों के मन में भी कामवासना जागृत हो जाती है। इन चैनलों पर दिखाये जा रहे कार्यक्रमों या फिल्मों द्वारा एक

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

घोषित सैक्स और हिंसा का युद्ध चलाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य व्यभिचार, यौनिक लिप्सा और हिंसा को बढ़ावा देना है। हिंसा और सैक्स की कुंठाओं के पनपने पर एक आम व्यक्ति ऐसी कल्पना का ताना-बाना बुन लेता है जो टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले दृश्य जैसी ही होती है। जब बार-बार यह कुंठित कल्पना दोहरायी जाती है तो फिर व्यक्ति के दिमाग में यह प्रयोग के रूप में दोहराने के अहसास को जीना चाहता है और यदि वह उसमें असफल रहता है तो फिर उसमें खालीपन और हीनता पनपने लगती है। इसी खालीपन को भरने के लिये व्यक्ति को जब भी मौका लगता है तो वह चूकना नहीं चाहता। कुंठा और हीनता से भरा हुआ व्यक्ति अपना विवेक छोड़ देता है और फिर सैक्स और हिंसा के वही खेल खेलने लगता है जो टेलीविजन पर उसने देखा था। अब विकसित समाजों की भोगवादी संस्कृति की विकृतियाँ हमारे यहाँ फैल रही हैं। इनसे मानसिक ओर आर्थिक गुलामी का पूरा ढाँचा हमारे ऊपर लद रहा है। आज हम अपनी जमीन से कट रहे हैं। सांस्कृतिक विलगन और आत्मनिर्वासन का संकट बढ़ रहा है। जिससे हमारी अस्मिता को ही गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आर्थिक दोहन से अधिक बड़ा खतरा है - मानसिक तौर पर परावलंबी होते जाना, इसी कारण हमारा आत्मविश्वास और अभिक्रम क्षीण हो रहा है।

16.

राजनैतिक हस्तक्षेप

यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया जाय तो उस देश की राजनीति अपने आप ही नियंत्रण में आ जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दुनिया के तमाम देशों में इसी सिद्धान्त पर व्यापार किया है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बढ़ती हुयी घुसपैठ ने राज्यों की सम्प्रभुता के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इन कम्पनियों के व्यापार करने के तरीकों के कारण अब राज्य की संकल्पना ही बेकार हो गयी है। 'राज्य की सम्प्रभुता', 'राज्य की नीति', 'राज्य की शक्ति', 'राज्य की अखंडता' आदि शब्द अब अर्थहीन हो गये हैं। राज्य की नीतियाँ अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्देशों पर तय होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रित देशों में से एक माने जाने वाले अमरीका की क्या हालत है ? यह अमरीकी सिनेटर सिलवेस्टर क्लार्क से 18 मार्च 1989 को 'न्यूर्याक टाइम्स' में प्रकाशित एक बयान से दिखती है "हमारे यहाँ विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय इन स्वयंभू प्रतिष्ठानों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) द्वारा लिये जाते हैं, अब अमरीकी सरकार की अपनी पहल, भूमिका और उसके लचीलेपन में कमी आयी है।" इस कथन से यह बात साफ है कि अमरीकी सरकार के फैसलों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। यही अखबार (न्यूयार्क टाइम्स) आगे लिखता है कि "निजी बैंक, किसी सार्वजनिक बहस या निर्वाचित प्रतिनिधियों की देखरेख के बिना ही अमरीका की विदेशी आर्थिक नीतियों का निर्माण प्रभावी तरीके से कर रहे हैं।" एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाती है - फोटोकापी के उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनी 'जेरॉक्स' की प्रबंध समिति इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि इसने कई बार अमरीका के 'फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन' के अधिकारियों से मिलने तक से इंकार कर दिया। ये अधिकारी कम्पनी से कुछ सूचनायें प्राप्त करना चाहते थे। 'जेरॉक्स' की प्रबंध समिति का मानना है कि अमरीका का 'संघीय व्यापार आयोग' बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

अमरीकी सिनेटर मैरी गोल्डवाटर ने हाल ही में सीनेट में भाषण करते हुये कहा कि "आज हमारे लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वही काम कर रही है, जो कुछ समय पूर्व तक सी.आई.ए. कर रहा था।" अमरीका के लिये तमाम तरह की गुप्त सूचनायें एकत्रित करने का काम अमरीकी कम्पनियाँ बहुत अच्छे से करती हैं। सी.आई.ए. के अतिरिक्त अमरीका की किसी भी संस्था या प्रतिष्ठान ने इतने संदेह और आलोचना को जन्म नहीं दिया जितना कि अमरीकी कम्पनियों ने। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बदनामी के मुख्य कारण हैं वे अपराध और गुप्त कार्यवाइयाँ जिनके पीछे इन कम्पनियों का हाथ रहता है। सच तो यह है कि आज ऐसे किसी भी बड़े राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को ढूँढ पाना कठिन है जिनके पीछे कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वार्थ नहीं जुड़े हों। आज ये कम्पनियाँ ही निर्धारित करती हैं कि तमाम देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं अन्य नेताओं को किस प्रकार के सुर निकालने चाहिए ? ये कम्पनियाँ उन शासनाध्यक्षों/नेताओं के प्रति बहुत ही निर्मम होती हैं जो इन कम्पनियों की बात नहीं मानते। ऐसे लोगों को सीधे-सीधे उनके पदों से हटा दिया जाता है या उनकी हत्या तक करवा दी जाती है। उदाहरण के लिये - 1972 में चिली की जनता द्वारा चुनी गयी यूनिटी सरकार के विरूद्ध जो हिंसक षड्यंत्र रचा गया, वह पेप्सीकोला तथा आई.टी.टी. द्वारा संचालित था। इस षड्यंत्र में चिली के राष्ट्रपति डा. सल्वादोर अलेंदे सहित 14 प्रमुख मंत्रियों की हत्या कर दी गयी। इस हत्याकांड में विख्यात कवि एवं साहित्यकार पाब्लो नेरूदा भी मारे गये। इस षड्यंत्र को इसलिये कराया गया क्योंकि डॉ. सल्वादोर अलेंदे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरोधी थे और अपने देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। अपनी हत्या से कुछ घंटे पूर्व डॉ. आलेंदे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में गुहार लगायी थी कि "मेरे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोषण से बचाया जाय।" संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में भाषण देकर जैसे ही डॉ. अलेंदे चिली लौटे उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया गया और उनकी हत्या हो गयी। डॉ. अलेंदे के बाद जो सरकार चिली मे बनी, उसके लिये मुख्य चिन्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वापस बुलाने की थी, न कि देश के विकास का।

इसी तरह ब्राजील, बोलीविया और ग्वाटेमाला में सरकारों का तख्ता पलटने की साजिशों में अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रमुख हाथ रहा है। निकारागुआ की पिछले चार दशकों से चली आ रही त्रासदी के लिये भी अमरीकी कम्पनियाँ जिम्मेदार हैं। अल सल्वाडोर में नरसंहारों का जो सिलसिला एक बार इन अमरीकी कम्पनियों के इशारों पर शुरू हुआ था, वह आज भी बदस्तूर जारी है। ईरान में अहमद रजा शाह पहलवी के शासनकाल में अमरीकी कम्पनियों का प्रवेश हुआ और तभी से ईरान में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में यही हालात ईरान-ईराक युद्ध की परिणति बने। ईरान-ईराक युद्ध की समाप्ति

पर सबसे अधिक सदमा 'लाकहीड' कम्पनी को पहुँचा, क्योंकि युद्ध के दौरान यह कम्पनी ईरान और ईराक दोनों को ही हथियार बेच रही थी। युद्ध की समाप्ति के बाद इस 'लाकहीड' कम्पनी ने ईरान में आंतरिक युद्ध पैदा कर दिया। इसी के चलते ईरान के मुजाहिदीनों को नि:शुल्क हथियार दिये गये। ईरान की सरकार के खिलाफ मुजाहिदीनों को भड़काया गया। बाद में यही मुजाहिदीन भागकर अफगानिस्तान की सरहद पर एकत्रित होते रहे। हथियारों का जखीरा बढ़ता रहा। यही मुजाहिदीन अफगानिस्तान के लिये भी सिरदर्द बने। इन्हीं मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलटा। फिर अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप हुआ। भयंकर खून-खराबा हुआ जो आज तक जारी है। हालांकि रूस ने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का वापस बुला लिया है लेकिन अफगानिस्तान में कत्लेआम जारी है। अब अमरीकी फौज वही कर रही है, जो पहले रूस ने किया था। आज हालत यह है कि मुजाहिदीनों के घर में रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा लेकिन हथियारों का जखीरा भरपूर मिल जायेगा। अफगानिस्तान के सारे आर्थिक संसाधान युद्ध की ज्वाला में नष्ट हो चुके हैं। रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये लोग पड़ोसी को मारने में नहीं चूकते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और एक अच्छा खासा देश बरबाद हो गया है। मुजाहिदीनों के कई संगठनों को अमरीकी कम्पनियों के हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार ही इन संगठनों को बातचीत की मेज तक नहीं पहुँचने देते हैं। अमरीकी सरकार मुजाहिदीनों के कई संगठनों को सरकार बनाने का सपना दिखलाती है। इसलिये ये संगठन एक दूसरे के खिलाफ बन्दूकें ताने खड़े है और इससे अमरीकी कम्पनियों के हित सधे हुये है।

राजनीतिज्ञों से रिश्ते

26 फरवरी, 1976 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक बैठक में ऐसी संहिता बनाने की मांग की गयी जो रिश्वत व भ्रष्टाचार को गैर कानूनी करार दे सकें। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका खुला विरोध किया। अमरीकी राष्ट्रपति का आग्रह था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी तमाम उपायों को स्वैच्छिक होना चाहिए ओर नैतिक अभिप्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। इसके पीछे उनकी विशेष चिंता थी कि इस प्रकार के कानून बन जाने से अमरीकी कम्पनियाँ घाटे में पड़ सकती हैं, अत: इस नियम को बनने ही नहीं दिया जाय। इस बात के लिये अमरीकी राष्ट्रपति पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दबाव डाला गया। तत्कालिन अमरीकी राष्ट्रपति ने 24 अन्य देशों का समर्थन जुटाकर भ्रष्टाचार विरोधी इस नियम को पारित नहीं होने दिया। मजे की बात यह है कि उसी दोरान अमरीकी कम्पनी 'लाकहीड' पर

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

भ्रष्टाचार के लिये 2 साल 6 महीने तक मुकदमा चला। मुकदमें के फैसले स्वरूप लाकहीड को 6 लाख 47 हजार डालर का जुर्माना देना पड़ा। जबकि लाकहीड ने उस दौर का सबसे बड़ा 'भ्रष्टाचार कांड' करते हुये 224 लाख डालर की रकम रिश्वत के रूप में 19 देशों के शासनाध्यक्षों तथा अन्य लोगों को दी थी।

वे कौन से रिश्ते हैं जिनके चलते अमरीकी राष्ट्रपति तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वकालत करते हैं और सिर्फ वकालत ही नहीं बल्कि इन कम्पनियों को बचाने का काम भी करते हैं। कम्पनियों को घाटा नहीं होने पाये यह अमरीकी राष्ट्रपति की चिंता में मुख्य रूप से शामिल रहता है। इन रिश्तों को समझने के लिये अमरीकी शासन तन्त्र में उच्च पदों पर बैठे हुये लोगों की खोज-खबर लेने की जरूरत है।

सामान्यत: यह देखा गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकारियों की अमरीकी शासन तन्त्र में नियुक्ति होती रहती है। यह बात नीचे दिये गये कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होती है - उदाहरण

(1) पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन, राष्ट्रपति बनने के पहले रेडियो और टेलीविजन की कई कम्पनियों के मालिक थे। कुछ समय तक वे आई.टी.टी. के प्रमुख भी रहे। जॉनसन एण्ड जॉनसन नाम की बहुराष्ट्रीय कम्पनी के जनक भी लिन्डन बी. जॉनसन ही थे।

(2) अमरीकी सरकारी खजाने के पूर्व सचिव विलियम ई. सिमोन, सचिव बनने से पहले कई अमरीकी बीमा कम्पनियों और बैकों के प्रमुख रह चुके थे।

(3) अमरीका के पूर्व वाणिज्य सचिव फ्रेडरिक बी. डेन्ट, जी.ई.सी. के निदेशक रह चुके थे, अपने वाणिज्य सचिव बनने से पहले।

(4) पेंटागन के पूर्व प्रमुख राबर्ट एस. मैकनमारा, पैंटागन में आने से पूर्व हथियार बनाने वाली कम्पनी आई.बी.एम. के अध्यक्ष थे। बाद में वे विश्व बैंक के भी अध्यक्ष रहे।

(5) पूर्व अमरीकी विदेश सचिव जान बी. कोनेली, टेक्सास इन्स्टूमेन्ट्स कम्पनी के अध्यक्ष रहे।

(6) अमरीका के एटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करने वाले एन. कट्जेनखाव, बी.एफ.कार्पोरेशन के अध्यक्ष थे, एटॉर्नी जनरल बनने से पहले।

(7) अमरीकी कानून विभाग के प्रमुख क्लार्क क्लिफोर्ड, यूनियन कार्बाइड के प्रबन्ध निदेशक रह चुके थे।

(8) इंग्लैण्ड के प्रतिरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख एडमिरल डी. एशमोर, हथियार बनाने वाली अंग्रेजी कम्पनी के अध्यक्ष रह चुके थे।

(9) इंग्लैण्ड के गृह-नागरिक सेवा के प्रमुख डब्लू. आर्मस्ट्रांग, अंग्रेजी बैक 'मिडलैड' के अध्यक्ष रहे चुके थे।

(10) इंग्लैण्ड के खजाना विभाग के प्रमुख ए. लोर्ड, डनलप कम्पनी के निदेशक रह चुके थे।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और भ्रष्टाचार

अपने मुनाफों को अधिकतम बनाने के लिये ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ रिश्वत का सहारा लेती हैं और खूब भ्रष्टाचार करती हैं। ये कम्पनियाँ उन देशों के शासनाध्यक्षों और राजनेताओं को घूस देती हैं, जिन देशों में इन कम्पनियों का व्यापार होता है। घूस या रिश्वत देने की कारगुजारियों में वे सभी कम्पनियाँ शामिल पायी जाती हैं, जिनके नाम अकसर ही शानदार कारों, सैनिक साजो सामान या हवाई जहाजों पर दिखायी देते है। दुनिया की प्रथम श्रेणी की सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिये रिश्वत देती हैं। अक्सर जिन प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, पार्टी नेताओं या राष्ट्रपतियों के चित्र और नाम फैशनेबुल पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं, वे रिश्वत लेने के अपराधी पाये जाते हैं। रिश्वत लेने के सौदों में शामिल शासनाध्यक्षों ने कई बार रिश्वत देने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिवालिया होने से बचाया है। उदाहरण के लिये; अमरीकी सरकार ने 'लाकहीड' कम्पनी को वित्तीय कठिनाईयों से उबरने के लिये अपनी गारंटी पर 25 करोड़ डालर के कर्जे निजी बैकों से दिलवाये 'लाकहीड' स्कैडल दुनिया के सबसे चर्चित स्कैंडलों में से एक रहा है। 'लाकहीड' तथा ऐसी ही कुछ अन्य कम्पनियों के रिश्वत देने के जो मामले सिद्ध हुये हैं, उनमें से कुछ को नीचे दिये जा रहा है -

नीदरलैंड में रानी जूलियाना के पति राजकुमार बर्नहार्ड ने कई बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से घुस ली। बर्नहार्ड फोकार एअरक्राफ्ट और रायल डच एयर कम्पनी (के.एल.एम.) के निदेशक थे। इसी कारण लाकहीड कम्पनी को उनमें दिलचस्पी थी। सन् 1961 से 1971 तक लाकहीड कम्पनी ने राजकुमार बर्नहार्ड को रिश्वत के रूप में 11 लाख डालर दिये।

इटली के तत्कालीन राष्ट्रपति लिओने को भी 'लाकहीड' कम्पनी ने रिश्वत दी। इस कांड के खुलने के बाद राष्ट्रपति लिओने को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इटली के तत्कालीन गृहमंत्री ल्यूगी गुई को भी 'लाकहीड' स्कैंडल में फंसे होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। गृहमंत्री ने 'लाकहीड' कम्पनी के 14 सी - 130 परिवहन विमानों की खरीद को बढ़ावा दिया था। हालांकि इटली की जनता और विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना था कि इटली के स्वदेशी विमान, 'लाकहीड' के विमानों की तुलना में अच्छे और सस्ते हैं। लाकहीड के साथ हुयी समझौता वार्ता में इतालवी पक्ष ने लाकहीड को सूचित कर दिया था कि जब तक उनकी कृपा दृष्टि का बदला नहीं मिलेगा, सौदा नहीं हो सकता। 'लाकहीड' ने इस इशारे को समझ लिया और 22 लाख डालर से राष्ट्रपति, गृहमंत्री और रक्षामंत्री की जेबें गर्म कर दी।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तनाका, किशी और फुकुडा ने भी रिश्वत

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

लेकर घोटाले किये। प्रधानमंत्री तनाका ने लाकहीड से रिश्वत खायी, जिसका आरोप सिद्ध हो जाने पर तनाका को जेल की सजा हुयी। प्रधानमंत्री किशी और फुकुडा ने अमरीकी कम्पनी ग्रुम्मन से 70 लाख डालर रिश्वत के रूप में लिये। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी 'लाकहीड' से 92 लाख डालर लिये।

पश्चिमी जर्मनी के पूर्व रक्षामंत्री फ्रेंज जोसेफ स्ट्रस ने फाइटर विमानों के आर्डर देते समय 'लाकहीड' कम्पनी से 12 लाख डालर रिश्वत के रूप में स्वीकार किये। लाकहीड के इन विमानों की अविश्वसनीयता के कारण इनका नाम 'उड़ते हुये कफन' रखा गया। पश्चिमी जर्मनी के राजनेता इस विमान को स्त्रियों को विधवा बनाने वाले विमान कहा करते थे।

80 के दशक में बोलिविया के राष्ट्रपति वेरियेंटोस ने गल्फ आयल कम्पनी से एक हेलीकॉप्टर प्राप्त किया था, जिसकी कीमत 1 लाख 10 हजार डालर थी। बोलिविया के राष्ट्रपति को इस कम्पनी ने अपनी शाखा खोलने के लिये 3 लाख 50 हजार डालर रिश्वत के रूप में दिये।

ईरान में अहमद रजा शाह पहलवी ने अपने शासन के दौरान कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से रिश्वत खायी। बाद में जब इसका भण्डाफोड़ हुआ तब पता चला कि शाह के परिवार के सदस्यों ने भी रिश्वत खायी इस काण्ड में ईरान के कई उच्च नेता भी शामिल थे।

हाल ही मे अमरीकी कम्पनी मैकडोनेल-डगलस ने, एफ-16 विमानों का आर्डर प्राप्त करने के लिये 15 लाख डालर, पाकिस्तान के राजनेताओं तथा अधिकारियों को दिये। इस बात पर कई बार पाकिस्तान की संसद में भी हंगामा हुआ है।

मिस्र के इजरायल अधिकृत क्षेत्र में पश्चिम की कई बड़ी कम्पनी तेल की संभावना का पता लगाने में जुटी हुयी है। हाल ही में वहां एक रहस्यपूर्ण दुर्घटना घटी। पता चला कि समुद्र तट पर काम करने के लिये जरूरी उपकरण पास ही में स्थित ओमान में मौजूद है। अत: ओमान के अधिकारियों को 10 लाख डालर की रिश्वत, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये दी गयी कि जब ओमान का डेरिक (तेल की संभावना पता करने में काम आने वाला यन्त्र) चोरी किया जा रहा हो, तब वे इस पर ध्यान नहीं दें। इस प्रकार ओमान का वह डेरिक चुराया गया और इजरायल अधिकृत मिस्र के क्षेत्र में पहुंचा दिया गया।

ईरान के शाह पहलवी से अमरीकी कम्पनी टाटे एण्ड लायले ने एक चीनी आयात के समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये। बाद में पता चला कि ईरान को इस चीनी के आयात की कोई जरूरत नहीं थी; क्योंकि ईरान में पहले से ही उपलब्ध चीनी की मात्र काफी थी। इस कारण ईरान को 4 करोड़ 50 लाख डालर का नुकसान हुआ और इस कम्पनी ने विश्व बाजार में चीनी की कीमतों

से अधिक दाम वसूलकर अतिरिक्त मुनाफा कमाया।

अमरीका के चर्चित 'वाटरगेट कांड' की जांच के समय यह पता लगा कि राष्ट्रपति निक्सन के निर्वाचन कोष में 17 अमरीकी कम्पनियों ने विशाल धनराशि दी। नोरथ्रोप कम्पनी ने 1,50,000 डालर, गल्फ आयल कम्पनी ने 1,00,000 डालर, फिलिप्स ने 1,00,000 डालर, ऐशलैंड ने 1,00,000 डालर, अमरीकी एयरलांइस ने 55,000 डालर और ब्रानिफ एयर कम्पनी ने 40,000 डालर दिये। चूंकि संघीय प्रत्याशियों के चुनाव अभियान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन देना गैर कानूनी था, इसलिये वाटरगेट कांड निक्सन के लिये अत्यन्त ही दु:खदायी सिद्ध हुआ। इस कांड के खुलने पर निक्सन को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा।

दक्षिण कोरिया में पार्क चुंग के शासनकाल में गल्फ आयल कम्पनी ने उर्वरकों व अन्य रसायनों का उत्पादन करने के लिये 35 करोड़ डालर की पूंजी लगायी। यह कम्पनी पार्क चुंग के कोष में 10 लाख डालर रिश्वत के रूप में दिये। थोड़े समय बाद जब पार्क चूंग के एक प्रतिनिधि ने, किसी राजनैतिक कार्य के लिये गल्फ आयल कम्पनी से 1 करोड़ डालर की मांग की तो कम्पनी ने इस मामले को प्रेस में लीक कर दिया। अखबारों में यह सारा मामला छपा और दक्षिण कोरिया में काफी हंगामा हुआ। पार्क चुंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके शासन की छुट्टी हो गयी।

हाल ही में बदनाम लाकहीड कम्पनी ने कोलंबिया में अपने विमान बेचने के लिये वहां के सेनानिवृत्त जनरल को 2 लाख डालर दलाली के रूप में दिये। स्पेन में इस कम्पनी ने अधिकारियों को 13 लाख डालर देकर, 2 करोड़ डालर के विमानों का आर्डर प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति क्लार्क को इस लाकहीड कम्पनी ने 90 लाख डालर घूस के रूप में दिये। इस रिश्वत से लाकहीड कम्पनी को दक्षिण अफ्रीका में 10 करोड़ 17 लाख डालर के विमान बेचने का मौका मिला। लाकहीड ने सन् 1970 में इटली के रक्षामंत्री को 6 करोड़ डालर मूल्य के विमान बेचने के लिये 16 लाख डालर की रिश्वत दी।

1986 में हुआ बोफोर्स घोटाला तो अब जग जाहिर हो चुका है। 1986 में भारत सरकार ने स्वीडन की कम्पनी से 1700 करोड़ रूपये की 'एफ.एच.-77 बी. होवित्जर' तोपें खरीदी। इन तोपों की खरीद के बाद स्वीडन के रेडियों ने पर्दाफाश किया कि बोफोर्स कम्पनी ने इस सौदे में भारतीय अधिकारियों तथा कुछ राजनेताओं को लगभग 67 करोड़ रूपये की रिश्वत दी है। बोफोर्स कम्पनी ने भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुये सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुये लोगों को रिश्वत के दम पर अपने पक्ष मे तैयार कर लिया। इस घोटाले की जांच संसदीय समिति द्वारा की गयी और आज तक जारी है। इस जांच में अभी तक 250 करोड़ रू. खर्चा हो चुका है। आलफे पाल्मे इस बोफोर्स घोटाले के कुछ ऐसे

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

रहस्यों को जानते थे, जिनके खुलने पर बोफोर्स कम्पनी को काफी नुकसान हो सकता था। अत: बोफोर्स कम्पनी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को ही मौत की नींद में सुला दिया ताकि वे रहस्य उन्हीं के साथ दफन हो जायें।

1981 में भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की एक कम्पनी से 430 करोड़ रू. की पनडुब्बियाँ खरीदी थी। इस 430 करोड़ रू. के सौदे में लगभग 30 करोड़ रू. का घोटाला हुआ । जर्मनी की कम्पनी ने 30 करोड़ रू. दलाली के रूप में भारतीय अधिकारियों और नेताओं को दिये।

60 के दशक में चेकोस्लोवाकिया से भारत सरकार ने पिस्टल खरीदी थीं। इन पिस्टलों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रू. की रिश्वत चेक कम्पनी ने भारतीय अधिकारियों को दी। संसद को इसकी जानकारी होने पर तत्कालीन रक्षामंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

अमरीकी कम्पनी नोरथ्रोप ने हाल ही में सऊदी अरब सरकार के साथ एफ-16 लड़ाकू विमानों का सौदा किया। इस सौदे में सऊदी अरब के शेख, वहां के वायुसेनाध्यक्ष तथा एक अन्य अधिकारी के 10 करोड़ 60 लाख डालर की रिश्वत दी गयी।

अमरीकी कम्पनी नोरथ्रोप, इटली की कम्पनी टेलीफोन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स, जर्मन कम्पनी सीमेन्स तथा जापानी कम्पनी निप्पन ने 1975 में ईरान में टेलीफोन का जाल बिछाने का ठेका प्राप्त करने के लिये, तत्कालीन ईरान सरकार को 20 लाख डालर रिश्वत के रूप में दिये।

यूनाईटेड ब्राण्डस कम्पनी ने होण्डुरास देश में अपने विशाल फार्मों में पैदा होने वाले केलों पर निर्यात शुल्क में कमी कराने के लिये राष्ट्रपति ओसवॉल्डो लॉपेज को 10 लाख डालर रिश्वत रूप दिय। इस कांड का पर्दाफाश होने पर होण्डुरास के राष्ट्रपति ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।

जर्मनी की हैकलर एंड कॉख कम्पनी ने कोलंबिया की सरकर के साथ हुये एक सैनिक राइफलों की खरीद के सौदे में कोलंबिया के सैनिक अधिकारियों को 2 लाख डालर की रिश्वत दी।

एशलैण्ड आयल कम्पनी ने हाल में ही गेबन देश के राष्ट्रपति अलबर्ट बर्नार्ड बोंगों तथा अन्य दो सरकारी अधिकारियों को 2 लाख डालर की रिश्वत देकर, गेबन में भूगर्भ तेल की खुदाई एवं सफाई का अधिकार पत्र प्राप्त किया। इस रकम का भुगतान कम्पनी ने अपने सामाजिक कल्याण कोष से किया।

वर्ष 1993 में भारत में जो प्रतिभूति घोटाला हुआ वह दुनिया के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा माना जाता है। इस घोटाले में देश के लोगों के हजारों करोड़ रूपये डूब गये और फायदा हुआ विदेशी बैंकों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को। सरकार द्वारा जांच के लिये बनायी गयी संयुक्त संसदीय समिति ने स्पष्ट रूप से विदेशी बैंकों को इस घोटाले के लिये जिम्मेदार ठहराया। सिटी

बैंक, बैंक ऑफ अमरीका, ए.एन.जेड. गिन्डलेज और स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंकों ने पूरे घोटाले में अहम भूमिका निभाई इन बैंकों ने इस घोटाले के माध्यम से भारत के खून पसीने की कमाई का विदेशी मुद्रा भण्डार खाली कर दिया। क्योंकि इस घोटाले के माध्यम से हजारों करोड़ रू. की सम्पत्ति देश से बाहर चली गयी। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में 60,000 करोड़ रूपये से भी अधिक की रकम शामिल है।

1994 में भारत में चीनी की कुछ कमी हो गयी। इस पर केन्द्र सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने चीनी के दाम बढ़ा दिय। अत: केन्द्र सरकार को बढ़े हुये दामों पर चीनी आयात करनी पड़ी। इससे देश को 360 करोड़ रूपये से भी अधिक का नुकसान हुआ। दूसरी और देश की आम जनता को अत्यन्त ही महंगी चीनी खरीदनी पड़ी। 12 रू. किलो वाली चीनी देश के गरीब लोगों को 18 से 20 रू. किलो में खरीदनी पड़ी

अफ्रीका में हस्तक्षेप

दक्षिण अफ्रीका राजनैतिक रूप से तो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लम्बे संघर्ष के बाद आजाद हो गया है लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अभी भी गुलाम है। रंगभेद और नस्लवाद की समस्या आज भी दक्षिण अफ्रीकी समाज में बनी हुयी है। नस्लवाद की इस समस्या की जड़ें वहां के समाज में अत्यन्त ही गहरी हैं। नस्लवाद के जहर को दक्षिणी अफ्रीकी समाज में फैलाने का काम अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बहुत ही बेहयाई के साथ किया है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दक्षिणी अफ्रीकी नस्लवादी सरकार का शुरू से ही समर्थन करती रही है। डब्लू.पी. बोथा और एफ.डी. क्लार्क के शासनकाल में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने वहां की जनता के राष्ट्रवादी आन्दोलन को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन कम्पनियों ने बोथा और क्लार्क सरकार को जोरदार समर्थन किया, जबकि पूरी दुनिया में इन सरकारों के खिलाफ प्रतिबन्ध लगे रहे।

यह सारा खेल अमरीका, इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी व फ्रांस के निगमों के इशारे पर हुआ। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य में 1600 से अधिक निगम कार्य कर रहे हैं जिनके वहां पर मोटे तौर पर 1700 करोड़ डालर के प्रत्यक्ष निवेश व 2300 करोड़ डालर के पत्राधान निवेश हैं। इनमें 600 से अधिक इंग्लैण्ड के, 400 से अधिक अमरीका के, 130 से अधिक प. जर्मनी के निगम मोजूद हैं जिनकी आर्थिक धमनियों में दक्षिण अफ्रीकी नस्लवादी शासन का सुनहरा जीवन रक्त बहता रहा है। दक्षिण अफ्रीकी अर्थतन्त्र में अमरीका के प्रत्यक्ष निवेश 2000 करोड़ डालर के है। दक्षिण अफ्रीका के समस्त उद्योगों का 72 प्रतिशत हिस्सा

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

विदेशी पूंजी के नियंत्रण में हैं। बहुराष्ट्रीय निगमें दक्षिण अफ्रीकी प्राकृतिक संसाधानों का जबर्दस्त शोषण करके भारी मुनाफा बटोर रहे है। दक्षिण अफ्रीका का 'फिनांशियल मेल' बताता है कि इंग्लैण्ड की कम्पनियाँ 310 प्रतिशत मुनाफे कमा रही हैं। अमरीका की कम्पनियां 270 प्रतिशत मुनाफे कमा रही हैं। जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उसके मुनाफों की तुलना में कहीं ज्यादा है। निवेशकों की नजर में दक्षिण अफ्रीका हमेशा ही सोने की खान रहा है। एक ऐसी स्फूर्तिदायक जगह वहां मुनाफे तगड़े है और समस्यायें कम।

खान उद्योग में काम करने वाले 90 प्रतिशत काले लोग है ओर उनकी आमदनी सफेद लोगों की तुलना में मात्र 5 प्रतिशत है। निर्माण उद्योग में काम करने वालों में आधे अफ्रीकी है। वहाँ उनकी आय गोरे लोगों की तुलना में 17 प्रतिशत है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैण्ड, अमरीका, स्वीडन व प. जर्मनी की निगमें जो पैसा अफ्रीकियों को अदा करते है वह गरीबी की रेखा से भी बहुत नीचे है अर्थात् उसे पैसे से आवश्यकता भर भोजन, कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते है। चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये।

पश्चिमी देशों की सरकारें नस्लवाद और पृथकता की भर्त्सना तो बड़े जोरदार शब्दों में करती हैं पर जब कुछ ठोस काम करने की बात सामने आती है तो वे बिल्कुल विपरीत ढंग से पेश आती हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में यथास्थिति को बनाये रखने में अपनी मौजूदा विशाल आमदनी की गारंटी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरूद्ध संघर्ष करने का एक आधार देखती रही है। इस प्रकार ये सारी जनता की स्पष्ट उपेक्षा ही नहीं करते बल्कि वे वास्तव में हर प्रकार का अपराध करने के लिये भी तैयार है।

जब दुनिया भर में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अत्याचारों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शित किया जाता रहा और विभिन्न देशों में रंगभेदवाद की हुकूमत के विरूद्ध अनेक जन-अभियान छेड़े गये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी निन्दा करते हुये अनेक प्रस्ताव पारित किये और सुरक्षा परिषद ने इसके विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के निर्णय लिये, लेकिन इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर कोई असर नहीं हुआ। निक्सन के समय में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने नीति संबंधी एक गुप्त दस्तावेज एन.एस.एम.-39 स्वीकृत किया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकारों के साथ समझ-बूझ कर संपर्क और संचार का विस्तार करने का आव्हान किया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रति पश्चिमी देशों की नीति दो प्रकार की रही - एक सरकारी जिसमें नस्लवाद और पृथकतावाद के विरूद्ध शाब्दिक धमकी आती थी, और दूसरी कार्यवाही संबंधी जिसमें जन-आक्रोश के विरूद्ध नस्लवादियों का बचाव करने की कार्यवाईयाँ शामिल थीं। आज ये निगमें अंगोला, मोजाम्बीक, अफगानिस्तान ओर हाल में ईरान के उदाहरणों से

भयभीत हैं। सरकारों का मुख्य काम विदेश नीति को उस वास्तविकता के अनुकूल बनाना है जिसे इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने काफी पहले पैदा किया था। ये कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पूँजी लगाने का वातावरण बहुत अनुकूल है और इस कारण इसे नयी विश्व अर्थव्यवस्था में एक उपयोगी भूमिका अदा करनी है बेशक उसकी भूमिका होगी पर केवल इन बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये। निगमों के साथ संबंधों का मजबूत करने के लिये जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है यह सरकार उसमें कोताही नहीं बरतती है। उदाहरण के लिये, इसने सिडनी एस. बैरन एंड कम्पनी को प्रतिवर्ष 3,65,000 डालर के स्थान पर 6,50,000 डालर देना शुरू कर दिया है, यह कंपनी अमरीका में दक्षिण अफ्रीका में हितों को पूरा करने के लिये काम करती है। अमरीकी व्यवसायियों के साथ संपर्कों को बढ़ाती है; आकर्षक सौदों के समझौते करने में मदद करती है जिसमें हथियारों से संबंधित सौदे भी शामिल हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय निगम अफ्रीकी लोगों की हत्या करके पैसा बना रहे हैं उनके ट्रेडमार्क उस हर गोली पर दिखायी दे सकते हैं जो अश्वेत प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भेजे जाने वाले हथियार अत्यन्त चक्करदार रास्तों से पानी जहाज द्वारा लाये जाते हैं जो सी.आई.ए, प. जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर सेवाओं द्वारा निर्धारित किये जाते है। उदाहरण के लिये अमरीका निर्मित लड़ाकू विमानों को ले लीजिये, उनके हिस्सों को इटली में जोड़ा जाता है, फिर इजरायल को बेचा जाता है और दक्षिण अफ्रीका तक उन्हें प. जर्मनी के जहाजों द्वारा सिंगापुर होकर पहुँचाया जाता है। यही लड़ाकू विमान रोडेशिया में मुक्ति आंदोलन को कुचलने के लिये वहाँ की सरकार को सौंपे गये थे।

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य उन थोड़े से देशों में से एक है जिसने नाभिकीय हथियारों के बढ़ाव को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है, हालांकि 100 से अधिक देशों ने इसे स्वीकार किया है। इसी वजह से उन पश्चिमी ताकतों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती हैं कि जो हथियारों के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका को मदद न देने के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुविदित निर्णयों का उल्लंघन करके स्वयं अपनी नाभिकीय क्षमता का विकास करने में नस्लवादियों की सहायता कर रहे हैं। इजरायल इसमें विशेष रूप से सक्रिय है। नाभिकीय हथियारों के बढ़ाव को रोकने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर न करने वालों में वह भी एक है। पश्चिमी बहुराष्ट्रीय निगमों को दक्षिण अफ्रीका में नभिकीय उत्पादन करते हुये अब 45 वर्ष से अधिक हो चुके हैं।उन्होंने नस्लवादियों को नाभिकीय ईधन व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी है। जोहांसबर्ग में यूरेनियम को समृद्ध बनाने का एक विशाल समुच्चय खड़ा किया जा चुका है। प्लूटोनियम के रेडियों सक्रिय आइसोटोपों के उत्पादन का काम जारी है। इन सभी कार्यो में मुख्य भूमिका प. जर्मनी की सीमेन्स, लुर्गी और

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

लेकोल्ड तथा ए.जी., अमरीका की फोक्सबोरो और फेडरल प्रोडक्ट्स कंपनियाँ अदा कर रही हैं। यह बात काबिले गौर है कि यूरेनियम को समृद्ध बनाने के जो उपकरण भेजे जा रहे हैं उसमें नाटो की भागीदारी है। इंग्लैण्ड की रियो-टिटो-जिंक, फ्रांस की टोटल मिनेरेएट न्यूक्लियारे, ई.एल.एफ. एक्यूटेआइन नामक कंपनियों ने नाभिकीय कच्चे माल की दौड़ में अपने प्रयासों को एकजुट कर लिया है। उन्होंने 5,000 टन यूरेनियम आक्साइड निकालने के लिये नामीबिया में एक विशाल खान 'शौसिंग' का निर्माण कर लिया है। इस आशय के समाचार मिले हैं कि दक्षिण अफ्रीका इजरायल को यूरनियम की आपूर्ति करेगा और इजरायल दक्षिणी अफ्रीका को नाभिकीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायेगा। गत वर्ष सितंबर में दक्षिण अफ्रीकी तटों पर जिस रहस्यपूर्ण कौंध को देखा गया था वह इजरायल द्वारा किया गया नाभिकीय विस्फोट था, जिसे दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से किया गया था।

मई 1985 में बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग के अधिवेशन में अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने यह मांग करते हुये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इन नस्लवाद को समर्थन देने वाली निगमों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये जायें और उन सारे निवेशों को वापस कर लिया जाय जो नस्लवादियों की सहायता कर रहे हैं। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये नाईजीरिया के राजदूत एल.ओ. हेरीमेन ने घोषणा की थी कि "निगमों ने नस्लवादी सरकारों के अत्याचारों की सहायता इसलिये की है कि वे भी अपने अपार मुनाफों को बनाये रखने के लिये वहां यथास्थिति कायम रखना चाहती हैं। ये कम्पनियाँ अफ्रीकी लोगों में आत्म सम्मान के विरूद्ध होने वाली हिंसा में तथा उस अत्याचार में नस्लवादी सरकारों की भागीदारी एवं सहयोगी हैं। जिनके कारण जनता को अपार मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं।" समाजवादी देशों, एशिया व लैटिन अमरीका के देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और यह स्वीकार कर लिया, लेकिन इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस व जर्मनी ने इसका विरोध किया। पहले भी 1997 में, 198 में तथा 1979 में अनेक ठोस प्रस्ताव रखे गये थे और उनमें प्रिटोरिया के साथ बहुराष्ट्रीय निगमों के सैनिक सहयोग को उजागर करने की आवश्यकता पर ध्यान खींचा गया था।

दक्षिण अफ्रीका में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण निगमों के अध्यक्षों की टिप्पणी जो कि लंदन के दैनिक 'मोर्निंग स्टार' में छपी है -

जनरल मोटर्स : "हमें वहाँ 50 वर्ष से ऊपर हो गये हैं और हमारी योजना वहाँ लंबे समय तक रहने की है....."

कालटेक्स पेट्रोलियम : हम नया पूंजी निवेश इसलिये कर रहे हैं कि बाजार फैलता जा रहा है....."

मेनहेट्टन बैंक : "हम पहले की भाँति काम कर रहे है शीघ्र ही हम और बड़े क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे....."

गुडईयर : "हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है जिसके कारण हमें यहाँ से बाहर जाना पड़े....."

एक अमरीकी प्रवक्ता : "अधिकांश अमरीकी कम्पनियाँ पहले की तरह चल रही हैं....."

इन निगमों को विश्वव्यापी भर्त्सना के सम्मुख निश्चय ही बचाव करना पड़ता है। नस्लगत असमानता को समाप्त करने के लिये इनकें पाखंडपूर्ण चरित्र का जब 'मोर्निंग स्टार' द्वारा भंडाफोड़ किया गया तो सामने आया कि :-

"अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने मांग की कि जनरल मोटर्स के पोर्ट एलिजाबेथ स्थित कारखाने के पेशाबघरों के दरवाजे से रंगभेद सूचक बोर्ड हटा लिये जाये। जनरल मोटर्स ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे हटा लेंगे। लेकिन अब पता चला है कि उन्होंने वे बोर्ड तो हटा लिये हैं पर उनके स्थान पर रंगीन चाभियों वाले दरवाजे लगा दिये है: "गोरों के लिये नीले तथा कालों के लिये नारंगी"।

यह रवैया प्रत्येक क्षेत्र में पाया जात है। प्रिटोरिया सरकार अधिक से अधिक बोर्ड बदलने का कार्य करती है लेकिन भेदभाव कायम है। अमरीकी पत्रिका 'साइंस मोनीटर' में छपे एक इंटरव्यू में वहाँ की कार फर्मे इस बात पर एकमत हो गयी हैं कि वे उन संगठनों को चंदा नहीं देंगी जो काले लोगों के हितों की देखभाल करते हैं।

इंग्लैण्ड, अमरीका व अन्य देशों की कंपनियाँ अब बड़े स्तर की व्यापारिक कार्यवाईयों पर अधिक भरोसा नहीं करती हैं, वह नस्लवादी नीति में अब मध्यमवर्गीय व्यवसायियों और छोटी मछली फंसाने पर आमादा है। उनकी सलाह यह है कि अच्छी आय को सुनिश्चित करने के लिये उन कम्पनियां के शेयर खरीदने चाहिऐ जो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रही हैं। सीधा सा तर्क यह है कि निगमों की अमानवीय नीतियों में यथा सम्भव अधिक से अधिक लोगों को फंसाया जाय और इस प्रकार केवल 5 या 10 डालर फेंक कर ही उनको इच्छा या अनिच्छा पूर्वक नस्लवादी अपराध में भागीदार बना लिया जाय।

दक्षिण अफ्रीका की अनेक कंपनियाँ जिनमें अनेक तो पश्चिमी निगमों की सहयोगी कंपनियाँ हैं, लैटिन अमरीका में विशेष दिलचस्पी दिखा रही है। दक्षिण अफ्रीका चिली के साथ मिलकर व्यापार करता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित आंग्ल अमरीकी कम्पनी ने, जो दक्षिण अफ्रीका स्थित दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली कम्पनी है, ब्राजील में सोने के खनन की विशाल फर्म में 65 प्रतिशत शेयर खरीद लिये हैं। पीकिंग भी अब प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg iklr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

हाथ मिला रहा है। चिली की तानाशाही सरकार को पीकिंग से सहायता मिल रही है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता से लैटिन अमरीकी 'गुरिल्ले' और दक्षिण अफ्रीकी नस्लवादी, दक्षिण अटलांटिक में एक सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक संघ का पवित्र गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रांतिकारी और मुक्ति आंदोलनों को रोका जा सके। इस प्रकार के विचारों को नाटो के सेनाध्यक्षों ने और निगमों के आकाओं ने एक लंबे समय से पाला पोसा है और समर्थन दिया है। दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य और अर्जेटीना की सरकार ने युद्ध सामग्री बनाने वाले निगमों के बची सूचनाओं और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था भी है। अर्जेटीना द्वारा प. जर्मनी के निगमों से नाभिकीय प्रौद्योगिकी खरीदे जाने को देखते हुये यह आदान-प्रदान विशेष महत्व का हो जाता है। पर यह बात निश्चित है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में कितनी ही पूँजी क्यों न लगायें, यह नस्लवाद और पृथकतावाद बचने वाला नहीं है, उसका अन्त तो निश्चित है, उदाहरण जिम्बाब्वे में देश भक्तों की विजय में लक्षित है।

17.

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और भारत

जो धन देता है, वह अपनी धुन भी बजवाता है। ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दुनिया के जिस देश में काम कर रही हैं, वहाँ अपनी धुने बजवा रही है। हमारा देश भी कोई अपवाद नहीं है।

जून, 1990 में भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। यह नीति पूरी तरह से विश्व बैंक के प्रभाव में बनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पुरोहिताई करता है।

विश्व बैंक ने 'भारत के व्यापार सुधाार के लिये नीति' विषयक रिपोर्ट सं. 8995-आई. एन. 30 नवम्बर 1990 को तैयार कर भारत सरकार को सौंपी थी। 21 जून 1991 को शपथ ग्रहण करने के बाद ही नरसिंह राव सरकार ने विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में दिये गये निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया। प्रस्तुत तालिका में विश्व बैंक की शर्तों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी की मुख्य बातों का उल्लेख किया जा रहा है :-

आर्थिक नीति के पुर्नगठन के लिये विश्व बैंक की शर्तें	fo'o cId fjikVl dk iljk lUnHk	1991&92] 92&93] 93&94 dk cctV eа dUnz ljdkj }kjk ekuh x;h 'krs
1. राजकोषीय घाटे में कमी करने के साथ-साथ मुद्रा दर को संशाधित किया जाये	2-19] 4-50] 8-62] 9-13] 9-51] 9-45	1990-91 राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। 1991-92 में इसे 6.2 प्रतिशत तथा 1992-93 में 5 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया। 1993-94 में इसे 4.7 प्रतिशत पर ला दिया गया है।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr iklr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

मुद्रा विनिमय दर का कम से कम 21 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाये।		1 जुलाई 1991 को डालर के मुकाबले रूपये का 9.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। 3 जुलाई 1991 को पुन: रूपये का 12.82 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया। 92-93 में रूपये का 60\40 क अनुपात में आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। जिसके चलते 60 प्रतिशत परिवर्तनीय हिस्से का 19.8 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। 93-94 के बजट में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का फैसला कर सरकार ने विश्व बैंक के निर्देशों का तकरीबन पूरे तौर पर पालन कर दिया।
2. व्यापार नीति में संशोधन के निर्देश	9-16	4 जुलाई 91 को घोषित नयी व्यापर नीति में आयात को सरल बनाया गया। एक्जिम स्क्रिप के माध्यम से आयात सुविधा एवं सभी पूरक लाइसेंस समाप्त किए गये।
(क) भारतीय उद्योगों को आयात के प्रति संरक्षण समाप्त कर, आयात नियंत्रण समाप्त किए जाये।		1992-97 की आयात निर्यात नीति में आयात व्यवस्था को सरल बनात हुए लाइसेंस प्रणाली एवं प्रतिबंध समाप्त कर व्यापार मुक्त किया गया। कुछ मामलों को छोड़कर वास्तविक उपभोक्ता नीति समाप्त। आयात शुल्क निर्धारण के लिये स्वत: कर निर्धारण योजना लागू की गयी।
(ख) आयात की नकारात्मक सूची एक बनाये जाये एवं संक्षिप्त किया जाये।	4-50] 4-55] 9-24	आयात-निर्यात नीति में केवल वस्तुएं निषिद्ध एवं 68 वस्तुएं प्रतिबंधित। स्वदेश आने वाले भारतीयों को 5 किलो सोना अपने साथलाने की अनुमति, सीमा शुल्क 220 रूपये प्रति दस ग्राम की दर से देय। इससे पूर्व सोना निषिद्ध सूची में था।
(ग) पूंजीगत वस्तुओं एवं मध्यवर्तियों के आयात पर लाइसेंस समाप्त किया जाये।	9-45	1992-93 में पूंजीगत वस्तुओं को नकारात्मक सूची से हटाकर इनका आयात उदार किया गया।
(घ) सरणीबद्ध वस्तुओं का आयात करने वाली सरकारी एजेन्सियों का एकाधिकार समाप्त किया जाये तथा इन्हें लघु क्षेत्र के लिये आयात की भूमिका निमाने हेतु कहा जाये।	9-20	6 अक्टूबर 1991 को राज्य व्यापार निगम एवं धातु व्यापार निगम का चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में एकाधिकार समाप्त कर इन्हें निजी ट्रेडिंग हाऊस के समकक्ष बनाया गया। कुछ आवश्यक बनाया गया। कुछ आवश्यक वस्तुओं (पेट्रालियम, खाद्यान्न, खाद्य तेल, उर्वरक आदि) को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं विसरणीकृत नयी आयात-निर्यात नीति में केवल 8 वस्तुएं सारणीबद्ध 17 सितम्बर 92 को डी.ए.पी. उर्वरक और 21 सितम्बर को विमाटिन ए व उसका पैरामिक्स विसरणीकृत किया गया।
(ड) सीमा शुल्क कम कर न्यूनतम स्तर या शून्य स्तर पर लाया जाये अन्यथा समान सीमा शुल्क दर 20 प्रतिशत की जाये। शुल्क के खंडों की संख्या तीन की जाये।	5-36] 6-47] 9-19] 9-29] 9-27] 9-32	शीर्ष टैरिफ स्तर 300 प्रतिशत से कम कर 150 प्रतिशत किया गया। 91-92 में सीमा शुल्क में 744.5 करोड़ रूपये की छूट दी गयी। 16 जनवरी 92 को इस्पात की वस्तुओं पर आयात शुल्क घटा दिया गया। 31 दिसम्बर 92 को नेप्था विसरणीकृत किया गया। शुल्क खंड़ों की संख्या, चार कर शीर्ष टैरिफ स्तर 110 प्रतिशत किया गया। सीमा शुल्क में 2035 करोड़ रूपये की छूट दी गयी। 93-94 के बजट में शीर्ष टैरिफ स्तर 85 प्रतिशत किया गया। सीमा शुल्क में 3273 करोड़ रूपये की छूट दी गयी।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

(च) पूंजीगत सामान व मध्यवर्तियों पर औसत 30 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने का निर्देश	9-45	92-93 में कोयला खनन, पेट्रोलियम शोधन, ऊर्जा परियोजना के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत किया गया। 92-93 में परियोजना आयातों और सामान्य मशीनरी पर सीमा शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रानिक पर 50 प्रतिशत कर दिया गया। अन्य पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया गया। मध्यवर्तियों पर रियायती सीमा शुल्क का प्रावधान रखा गया। 1993-94 बजट में कोयला खनन, पेट्रोलियम पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत, विद्युत परियोजनाओं पर 20 तथा परियोजना और सामान्य मशीनरी पर 35 प्रतिशत रखने का फैसला लिया गया।
(छ) उपभोक्ता वस्तुओं को आयात की नकारात्मक की नकारात्मक सूची से निकालकर आयात की अनुमति दी जाये तथा सीमा शुल्क कम किया जाय। सीमा शुल्क कम न करने की स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाये।	9-23] 9-24] 9-32	9 फरवरी 1992 को यात्री सामान के साथ 35 घरेलू इलैक्ट्रोनिक उपकरण लाने की अनुमति दी गयी। 1 यात्री 1.50 लाख रूपये मूल्य के उपभोक्ता उपकरण 150 प्रतिशत शुल्क देकर ला सकता है। इससे पूर्व सीमा शुल्क 225 प्रतिशत था। 93-94 के बजट में यात्री सामान के साथ 1.50 लाख रूपये मूल्य की सभी वस्तुएं लाने की छूट दे दी गयी।

3. निर्यात नीति में संशोधन के निर्देश	6-55] 6-56] 6-57] 6-58]	91-92 में निर्यात लाइसेंसो की जटिल प्रक्रिया समाप्त कर सरल व्यवस्था अपनायी गयी।
(क) निर्यात, व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार किए जायें तथा निर्यात नीति को सरल बनाया जाये।	4-54] 6-50	निर्यातित वस्तुओं की विभिन्न सूचियाँ समाप्त कर एक नकारात्मक सूची बनायी गयी।
(ख) रैप लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया जाये तथा इसे संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में अपनाया जाये।		91-92 में रैप लाइसेंस की एक्जिम स्क्रिप में बदला गया। सभी प्रकार के निर्यात पर 30 प्रतिशत एक्जिम स्क्रिप देने की घोषणा की गयी।
(ग) राजकोष पर भार पड़े बिना निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाये।	4-56	4 जुलाई 91 को निर्यात के लिए, नकद मुआवजा सहायतासमाप्त कर, सभी आयात (पेट्रोलियम, खाद्य तेल, खाद्यान्न एवं उर्वरक को छोड़कर) एक्जिम स्क्रिप से करने की अनुमति दी गयी। 92-93 में रूपये को आंशिक परिवर्तनीय बनाने के बाद एक्जिम स्क्रिप समाप्त कर दिया गया।
(घ) निर्यातोन्मुखी उद्योगों को मशीन आयात पर शुल्क में छूट दी जाये। यह छूट तीन से पांच वर्ष में दी जा सकती है	6-49] 9-38	निर्यात संवर्धक पूंजीगत सामान के आयात में सीमा शुल्क में छूट दी गयी।
4. सीमा शुल्क कम करने से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए उत्पादन शुल्क, आयकर एवं घरेलू कर में वृद्धि की जाये।	9-34] 9-35	91-92 में विशेष उत्पादन शुल्क दो गुना किया गया। उत्पादन शुल्क में कुल 1799 करोड़ रूपये और आयकर में 2139 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी। 92-93 में उत्पाद शुल्क में कुल 2515 करोड़ रूपये तथा

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

		प्रत्यक्ष करों में 795 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी। चेलैया समिति ने अति लघु और कुटीर उद्योगों पर भी उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।
5. जो वस्तुएं उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं हैं, उन पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये। (विश्व बैंक ने उर्वरक, कीटनाशक, कृषि और औषधियों पर उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया था।)	5-31] 5-34] 9-34] 5-32] 5-41 5-36] 5-39] 9-34	चेलैया समिति ने उर्वरकों पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव देते हुए, कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है।
6. उत्पादन कर प्रणाली में परिवर्तन कर मोडवेटस वेट प्रणाली अपनायी जाये।		चेलैया समिति ने मोडवेट व वेट प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है।
7. औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर उद्योगों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जाये।	1-1] 9-64	जुलाई 91 में घोषित नयी औद्योगिक नीति में लाइसेंसे प्रणाली परिवर्तित कर र्सि 18 उद्योगों के लिए ही लाइसेंसे की जरूरत रखी गयी। उद्योगों में अब विदेशी कम्पनियाँ शत-प्रतिशत निवेश भी कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गयी। 5 मार्च 93 को घोषित नयी राष्ट्रीय खनिज नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्योगों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला किया जाय।
8. उद्योगों को प्राप्त संरक्षण समाप्त	v/;k; & 7] 4-25	16 जनवरी 92 को इस्पात नियंत्रण मुक्त किया गया

		किया जाये। आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीद में घरेलू उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकता बंद की जाये। और खरीद में घरेलू उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकता भी समाप्त कर दी गयी। 92-93 में फोस्फेटिक उर्वरक और केरोसीन व रसोई गैस वितरण को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया।
9. सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन करते हुए घाटे में चलने वाली इकाइयों को बंद किया जाये।	8-67] 9-13] 9-63	नयी औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन की घोषणा की गयी और रूग्ण उद्योगों को औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष भेजने का फैसला लिया गया।
10. उद्योगों में अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी की जाये, इसके लिए बहिर्गमन नीति अपनायी जाये और उससे प्रभावित कर्मचारियों के संरक्षण हेतु कोष निर्मित किया जाये।	8-66] 9-64] 9-67	91-92 में स्वर्णिम विदाई योजना एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने का फैसला लिया गया। 91-92 में बहिर्गमन नीति से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पुर्नप्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए पुर्ननिर्माण कोष बनाने की घोषणा करते हुए 200 करोड़ रूपये का कोष बनाने का निर्णय लिया गया। 92-93 में इस कोष के लिए 1000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी।
11. सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचे जाये।	9-62	91-92 में 31 उपक्रमों के 3038 करोड़ रूपये के शेयर बेचे गये। 92-93 में 3500 करोड़ रूपये के शेयर बेचने का लक्ष्य रखा गया था, इनमें से 13 उपक्रमों के 1866 करोड़ रूपये के शेयर बेचे गये। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 4904 करोड़ रूपये के शेयर बेच दिये गये।

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

18.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सच्चा पहलू

मरे हुये लोगों को जलाकर कमाई करने वली दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'इन्टरनेशनल सर्विस कार्पोरेशन' (I.S.C.) है। इसके पास विश्व भर में 502 शवदाह गृह हैं। यह कम्पनी शवों को जलाकर एक वर्ष में औसतन 69 करोड़ 28 लाख 17 हजार डालर (13 अरब 16 करोड़ 35 लाख 23 हजार रूपये) कमाती हैं। यह कम्पनी अमेरिका की है।

युद्ध में काम आने वाली मिसाइलें को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी सेस्त्र एयर क्राफ्ट (CesnaAircraft) है। अपने स्थापित होने से सन् 2008 तक यह कम्पनी 18 लाख 81 हजार मिसाइलें बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों को बेच चुकी हैं। यह कम्पनी सन् 1911 में स्थापित हुयी थी। सामान्य रूप से यह कम्पनी प्रति वर्ष लगभग 2,300 मिसाइलें का उत्पादन करती है। युद्ध के दिनों में कम्पनी का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि मिसाइलों का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि मिसाइलों की खपत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये ईरान-ईराक युद्ध के समय में कम्पनी ने 3000 मिसाइलों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया था। यह अमेरिकी कम्पनी है।

विश्व भर में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनीयाँ हैं उनमें सबसे बड़ी है - हथियारों का उत्पादन करने वाली अमेरिका बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'जनरल मोटर्स' (General Motors)। इस कम्पनी ने सन् 1994 में 154 अरब डालर (4928 अरब रूपये) की बिक्री की अपने उत्पादों को बेचकर।

दुनिया में सबसे अधिक विषैली गैसों का उत्पादन करने वाली कम्पनी अमेरिकी की है जिसका नाम है 'ड्यूपान्ट' (Dupont) दुनिया के सभी विकासशील

देशों में उत्पादन के तौर तरीकों के कारण जितनी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, उस मात्र का 10 गुना अधिक, विषैली गैसें अकेले ड्यूपान्ट उत्पादित करती है। ध्यान रहे कि, ये विषैली गैसें ओजोन की परत को लगातार कमजोर करने के लिये जिम्मेदार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के विनाश के लिये अगर सबसे अधिक जिम्मेदार कोई है, तो वह है-अमरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'ड्यूपान्ट' (Dupont) दूसरे स्थान पर आती है ब्रिटेन की 'इम्पीरियल केमीकल इन्डस्ट्री' (I.C.I.) दोनों कम्पनियों के दुनिया भर में स्थित कारखाने, 500 टन के बराबर प्रतिदिन जहरीली गैसें छोड़ते हैं।

सबसे अधिक लडाकू विमानों का उत्पादन करने वाली कम्पनी हैं - 'बोइंग'। इस कम्पनी ने सन् 1994 में लगभग 21 अरग डालर (672 अरब रूपये) के लड़ाकू विमान बनाये। यह अमरिकी कम्पनी अन्य मालवाहक व यात्री वाहक हवाई जहाज भी बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कम्पनी 'इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन' (I.B.M.) अमेरिका की है। इस कम्पनी का सन् 1994 का विशुद्ध मुनाफा लगभग 58 अरब डालर (1856 अरब रूपये) था। यह कम्पनी इलैक्ट्रानिकी की चीजें बनाने के अलावा हथियार भी बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक शराब का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'एनह्यूसर-बुश इनकार्पोरेशन' (Anheuser-Bush Incorporation) अमेरिका की है। यह कम्पनी विश्व के 54 देशों में बेचने के लिये 92 अरब 13 करोड़ लीटर शराब प्रति वर्ष बनाती है।

दुनिया में सबसे अधिक सिगरेटों का उत्पादन करके बेचने वाली कम्पनी अमेरिका की 'आरजेरेनाल्ड टोबैको कम्पनी' है। यह कम्पनी प्रति वर्ष 110 बिलियन (110 अरब) सिगरेटों का उत्पादन करती है। याद रहे कि 500 सिगरेटों के बनाने में एक बड़ा पेड़ समाप्त हो जाता है। पूरे विश्व में लगातार पेड़ों की संख्या अत्यन्त तेजी से कम होती जा रही है।

विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन बनाने वाली कम्पनी 'सात्ची एण्ड सात्ची' (Satchi And Satchi) ब्रिटेन की है। कम्पनी ने दुनिया की तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये सन् 1988 में 135 अरब 29 करोड़ डालर (257 अरब 5 करोड़ रूपये) के विज्ञापन तैयार किये थे।

प्रतिवर्ष विज्ञापन पर सबसे अधिाक खर्चा करने वाली कम्पनी 'सीयर्स रोब्यूक एण्ड कम्पनी' (Sears Roebuk And Company) अमेरिका की है। सन् 1988 में इस कम्पनी ने (1 अरब 18 करोड़ 68 लाख डालर 822 अरब 54 करोड़ 92 लाख रूपये) विज्ञापन पर खर्च किये। यह कम्पनी रेडीमेड वस्त्र

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022

iLrr b&iLrd lLdj.k eDr :i l miyC/k gA lEi.k b&iLrd lkfgR; lxg ikIr dju d fy; ykx vku dj % http://www.rajivdixit.net http://www.rajivdixit.com

तथा जुतों का उत्पादन करती है।

विश्व की 570 ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का वार्षिक कारोबार 20 अरब डालर (640 अरब रूपये) से भी अधिक है। इनमें सबसे विशालकाय 100 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा है।

दुनिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सबसे बड़ा समूह "जैसपर ग्रुप" (Jespar Group) है, जिसके पास अकेले अपनी 451 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं।

जुलाई 1995 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 12,32,951 कम्पनियाँ हैं। इनमें 102664 सरकारी तथा बाकी निजी कम्पनियाँ है।

पश्चिमी जर्मनी व यूरोप के कई अन्य देशों में चल रहे 'ग्रीन पीस मूवमेंट' की अक्टूबर 1994 की रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - "ऐसी कोई भी कम्पनी जो एक साथ दुनिया के एक से अधिक देशों में काम करती हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनी मानी जानी चाहिए।"

आंकड़ों के स्रोत :-

1. इन्टरनेशनल जेनेटिक रिसोर्स प्रोग्राम : जेनेटिक रिव्यू (1987)
2. सरकारी प्रेस नोट्स (1988)
3. कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स (1985, 1986, 1987, 1988, 1993, 1994)
4. फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू (1989, 1992, 1993, 1994)
5. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन (1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
6. इन्डियन इन्वेस्टमेण्ट सेन्टर रिपोर्ट (1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
7. फारचून (5 जून 1989, 4 जून 1990, 31 जुलाई 1989, जुलाई 1995)
8. इकॉनामिक टाइम्स (7 जून 1990, 28 जून 1990, 21 जुलाई 1989, 16 जुलाई 1995)
9. विश्व बैंक रिपोर्ट (1989, 1992, 1993)
10. विश्व स्वास्थ्य संगठन : रिपोर्ट ऑन पेस्टीसाइड्स (1989)
11. मिरर (अक्टूबर 1989, नवम्बर 1989)
12. जर्नल ऑफ आई. आई. पी. ए. (1989)
13. रिपोर्ट ऑन मार्केटिंग रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर. 1989)
14. नव भारत टाइम्स (17 मई 1990)
15. गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड्स (1989)
16. योजना भवन बुलेटिन (1989)
17. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स (नवम्बर, दिसम्बर 1989)

किताबें

1. द मल्टीनेशनल : लेखक - क्रिस्टोफर टु जेन्धर
2. मल्टीनेशनल कार्पोरेशन एण्ड डवलपिंग नेशन्स : लेखक-रेमण्ड वर्नोन
3. सोवरैनिटी एटवे (रेमण्ड वर्नोन)
4. सीड ऑफ डिपेन्डेन्स (डी.एस.एफ. 1988)
5. एनीथिंग फॉर ए डालर (ऊषा मेनन)
6. टेमिंग द जायन्ट्स (वी. गौरी शंकर)
7. कार्टेल्स इन एक्शन (स्टाकिंग व मेरिन)
8. मोनोपोली केपीटल (पॉल बरान व स्वीजी)
9. द अमेरिकन इन्वेडर्स (एफ. ए. मेकेन्जी)

lEi.k lkfgR; lxgk dh efnr ifr ikIr dju d fy; lEid dj % Lon'kh idk'ku] o/kk] egkjk"V % lEid l= % 08380027016 / 08380027022